पेज-06

सीधी और सच बात, साहस के साथ

आज की जनधारा

डाक पंजीयन 29/2010-2012

वेब संस्करण
www.aajkijandhara.com
www.jandhara.in
Jandhara24x7
@AJandhara/Jandhara24/7
AajkiJandhara & Jandhara24x7
6232949114, 8959444440

RNI No.- CTHIN/26/A4159

वर्ष : 01, अंक : 29, जगदलपुर, मंगलवार 23 जून 2026

रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, मध्यप्रदेश से प्रकाशित epaper www.aajkijandhara.com | email:aajkijandhara@gmail.com | ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-9, वि.सं. 2083 | पृष्ठ : 12 | मो. : 9425203900, 9425243430 मूल्यः 2.00 रु.

लखनऊ की कोचिंग में आग, 15 मौतें

इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स, बचने के लिए बाथरूम में छिपे, दम घुटा, एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जानकारी के मुताबिक, आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में थंब इम्प्रेशन वाले गेट लॉक हो गए थे। छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जयंत नाम के एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूद कर जान बचाई। लेकिन वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पहुंची थीं। फायरकर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, जिससे शव निकाले हैं।

घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई थीं। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी

हैं। सीएम योगी घटनास्थल पहुंचे। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर जाएंगे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं।

मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर बोलीं- अटॉप्सी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा,अलीगंज में आग की घटना घटी है। जितने को हम बचा सकते हैं, हम उनको बचाएंगे। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। अभी सब शुरू हो गया है।

अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जताया: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

रो पड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

इस भयानक अग्निकांड की त्रासदी और इसमें जान गंवाने वाले मासूमों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बेहद भावुक हो गए। मीडिया से बात करने के दौरान इस दर्दनाक घटना का जिक्र आते ही डिप्टी सीएम खुद को संभाल नहीं पाए और कैमरे के सामने ही फफक-फफक कर रो पड़े।

प्रधानमंत्री ने किया मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भी ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

राहुल गांधी ने जताया दुख: राहुल गांधी ने भी इस भीषण अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया: रक्षामंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

बीजेपी मेयर रोते हुए बोलीं- आदिवासी महिला हूं इसलिए षडयंत्र

- अंबिकापुर में 3 लाख रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, कांग्रेस बोली- भ्रष्टाचार का खुला खेल

सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम की भाजपा महापौर मंजूषा भगत पर मीना बाजार लगाने की अनुमति दिलाने के एवज में 3 लाख लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेयर ने इस ऑडियो को फर्जी बताया है। सोमवार को मेयर अजाक थाने पहुंचीं। ऑडियो बनाने के साथ उसे वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

मीडिया से बात करते हुए महापौर रोने लगीं और उन्होंने कहा कि मेरे

खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है। वे आदिवासी महिला हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21 जून की शाम उन्हें फोन पर बताया गया कि आपका किसी ने ऑडियो जारी किया है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वह ऑडियो सुना। महापौर ने कहा कि उन्हें नहीं लगा कि वह आवाज उनकी है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है।

वहीं, कांग्रेस ने 3 लाख घूस लेने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। इधर, युवक कांग्रेस ने कलेक्टोरेट चौक पर प्रदर्शन किया और सड़क पर स्पीकर लगाकर लीक ऑडियो को पब्लिक को सुनाया।

रोते हुए बोलीं महापौर-मेरे खिलाफ षडयंत्र हुआ: मीडिया से बात करते हुए महापौर मंजूषा भगत भावुक हो गईं और रोने लगीं। उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने थाना प्रभारी से मांग की कि वायरल ऑडियो की बारीकी से जांच की जाए और इसमें जिस व्यक्ति अनुराग मिश्रा की आवाज बताई जा रही है, उसकी भी जांच की जाए।

महापौर ने कहा कि इस ऑडियो से वे और उनका परिवार मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वे कई दिनों ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाया, अभिषेक सस्पेंड

कोलकाता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को पार्टी में बगावत ने बड़ा मोड़ ले लिया। उलुबेरिया पूर्व के विधायक ऋ्रब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित करने और ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला बागी खेमे की एक अहम बैठक में लिया गया, जिसमें खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने वाले नेताओं ने नई संगठनात्मक समिति के गठन के तुरंत बाद प्रस्ताव पारित कर अभिषेक बनर्जी के निलंबन की घोषणा की।

बागी गुट ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नई गठित संगठनात्मक समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। ऋ्रब्रत गुट की

बैठक न्यू टाउन के एक होटल में हुई, जिसमें बागी विधायकों और कोलकाता नगर निगम समेत तीन जिलों के 70 पार्षदों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में हावड़ा मध्य से विधायक अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह पार्टी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया।

बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक को संबोधित करते हुए ऋ्रब्रत बनर्जी ने कहा कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर तीन साल ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक कर रहे हैं। सीजेपी ने नीट पेपर लीक में सुसाइड करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम 5:30 बजे प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर पर मोमबत्तियां लेकर आने की अपील की। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हजारों लोग जंतर-मंतर पर आ रहे हैं और यह प्रदर्शन धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है। पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे हमारे साथ हैं।

पिकअप वाहन ट्रक से टकराया, 6 मजदूरों की मौत

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा-बैतूल नेशनल हाईवे पर एक पिकअप वाहन की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार मजदूर दूर जा गिरे। हादसा सोमवार सुबह करीब 10 बजे टेमनी खुर्द के पास हुआ। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। केवल एक मृतक की पहचान हो पाई है, जबकि 5 शव अभी अज्ञात हैं। जिला अस्पताल में अब तक 20 घायल लाए जा चुके हैं। इनमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज, नागपुर रेफर किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। 20 से 25 डॉक्टर घायलों के उपचार में जुटे हैं। सर्जिकल आईसीयू में 3 मरीज भर्ती हैं। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में 4 मरीज भर्ती हैं।

थरूर बोले- जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयान के कारण एक बार फिर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, थरूर ने 21 जून को श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने जम्मू-कश्मीर की स्थिति और हालात में आ रहे सुधार पर बात की। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन इस दौरे के बाद मुझे पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस हुआ।

सीफूड फैक्ट्री में गैस रिसाव, 5 की मौत

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक निजी फिश मील निर्यात फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बताया कि रातभर में तीन और महिलाओं की मौत हो गई। इससे पहले 21 जून की शाम तक दो मौतें दर्ज की गई थीं। हादसा 21 जून को पेरियापालयम के पास कन्निगाइपैर गांव में स्थित फैक्ट्री की उत्पादन इकाई में हुआ था।

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल एआरवाय न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी लगातार बढ़ रही है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1फीसदी पानी की कमी है। राइस कैनाल में 38फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

मुस्लिम हमें काफिर बोलते हैं: मंत्री विजयवर्गीय

इंदौर। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा- यहां सड़क बन रही है। यहां हिंदू भाई भी रहते हैं और मुस्लिम भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अगर हम काफिर हैं, तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो। आपके घर में लाड़ली बहना-लाड़ली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है, तो मत लो।

उन्होंने कहा, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही हमारी नीति रही है। आप हमें वोट दो या नहीं दो, हमारा काम जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा करना उनका दायित्व है। राजनीतिक समर्थन मिले या न मिले, विकास कार्य जारी रहेंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने आगे कहा कि उनकी सरकार और पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।

उद्धव के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल

- 4 साल में दूसरी टूट, शिंदे बोले- छक्का लगाया, आदित्य ने पाला बदलने वालों को बिकाऊ कहा

मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान किया।

इस दौरान शिंदे ने कहा कि जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष-बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब 40 विधायक थे और अब छक्के लग चुके हैं। हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसीलिए आज ये 6 सांसद बालासाहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए।

उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा- पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातोंरात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया। 6 सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं उद्धव गुट में 9 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार टूट हुई।

उद्धव की बैठक में 4 विधायक नहीं पहुंचे: इससे पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

ट्रम्प के इशारों पर काम नहीं करता: नेतन्याहू

- लेबनान में इजराइली सेना हटाने से इनकार, अमेरिका-ईरान की बातचीत फिर शुरू

तेल अवीव/तेहरान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोग यह समझते हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पर काम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यरुशलम में आयोजित एक समिट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रम्प चाहते हैं। लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं।

इजराइली पीएम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने-अपने हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय एक जैसी नहीं होती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जरूरत महसूस होगी तब तक इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में रहेगी। इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटाए

- सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए, धर्म सेना अध्यक्ष का मोदी को लेटर, ट्रस्ट भंग करने की मांग

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारियों को सोमवार को हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है। हटाए गए कर्मचारियों को दूसरी जगह ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके अलावा, गणनास्थल पर 3 सीसीटीवी बढ़ाए गए हैं। अब सीसीटीवी की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।

इधर, धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी आज सीएम योगी आदित्यनाथ को

शुरुआती रिपोर्ट सौंप सकती है। टीम रविवार शाम को योगी से मिलने पहुंची थी, लेकिन उनके मानसून सेशन की मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से मुलाकात नहीं सकी थी। एसआईटी ने जिन लोगों से पूछताछ की है, उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या से बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है।

इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव भी शामिल हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गोपाल राव अयोध्या छोड़कर कर्नाटक चले गए हैं। ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

बंगाल में मदरसों को मिलने वाली रकम आधी हुई

- महिलाओं को नौकरी में 33फीसदी आरक्षण, सरकारी कर्मचारियों को 38फीसदी डीए, भाजपा सरकार का पहला बजट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में कहा गया कि सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरेगी और इसमें महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165.42 करोड़

कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 4 लाख 30 हजार करोड़ के बजट में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समय शुरू हुई सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं (जैसे- अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा) को जारी रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 38फीसदी कर दिया गया है। वहीं, कोलकाता में एक नए एयरपोर्ट बनने की भी घोषणा की गई है। ⏮शेष पृष्ठ 10 पर

राहुल-उमेश की 'वॉशरुम गुफ्तगू' से गरमाई कांग्रेस की सियासत

उमेश पटेल को मिल सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान

- युवा चेहरा, झीरम कनेक्शन और भूपेश का साथ बन रही पसंद

कृष्ण कुमार सिकंदर

रायपुर। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद प्रदेश कांग्रेस की सियासत में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दौरे के दौरान राहुल गांधी और विधायक उमेश पटेल के बीच हुई लंबी निजी बातचीत ने संगठन में संभावित बदलावों को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए उमेश पटेल के नाम पर विचार कर सकता है।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान वॉशरुम के

पास उमेश पटेल से काफी देर तक अकेले में बातचीत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज कुछ दूरी पर मौजूद रहे। हालांकि इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

उमेश पटेल के नाम को लेकर पार्टी में कई समीकरण उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं। वे युवा नेता हैं और लंबे समय से संगठन व विधानसभा की राजनीति में सक्रिय हैं। साथ ही वे झीरम कांड में मारे गए कांग्रेस नेता नंदकुमार पटेल के पुत्र हैं, जिससे उनका पार्टी के पुराने नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत भावनात्मक जुड़ाव माना जाता है। इसके अलावा उमेश पटेल को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक समीकरण नजर आते रहे हैं। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रभाव है, वहीं दूसरी ओर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अपने-अपने समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर संतुलन साधने की चुनौती भी कांग्रेस नेतृत्व के सामने है। हाल ही में टीएस सिंहदेव ने संकेत दिए थे कि मौका मिलने पर वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में नई चर्चा शुरू हुई थी। वहीं दीपक बैज ने सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें केंद्र की राजनीति में जाने की सलाह दी थी। भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात कही थी। इसे संगठन में अंतिम निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के हाथ में होने के संकेत के रूप में देखा गया। अब राहुल गांधी और उमेश पटेल की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर सकती है।

हालांकि उमेश पटेल को पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी से उनकी अकेले में हुई बातचीत और प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा समीकरणों के बीच उमेश पटेल का नाम प्रदेश संगठन की नई जिम्मेदारी के संभावित दावेदारों में तेजी से उभर रहा है।

छत्तीसगढ़ में मानसून की धमाकेदार एंट्री! दंतेवाड़ा से दाखिल हुआ मानसून

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से मानसून का प्रवेश हुआ है। इसके साथ ही प्रदेशभर में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। मानसून की एंट्री के साथ ही बस्तर संभाग में जोरदार बारिश दर्ज की गई। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई। वहीं राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में भी बादलों ने डेरा डाला और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है।

मानसून की दस्तक किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। प्रदेश के अधिकांश किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। अच्छी बारिश होने से धान की बुवाई और अन्य कृषि कार्यों को गति मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मानसून पहुंचने से फसलों की उत्पादकता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ था।

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT, BILASPUR (C.G.)

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
Balance Sheet as at 31st March, 2026

PARTICULARS	SCHEDULE	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1,29,27,34,932.20	1,25,43,37,362.20
Reserves & Surplus	2	4,18,20,71,090.55	3,44,76,37,056.79
Deposits	3	47,14,61,79,310.27	47,45,06,77,488.58
Borrowings	4	8,56,02,26,992.58	7,54,18,55,151.82
Other liabilities & Provision	5	3,74,14,71,105.78	3,60,68,73,166.08
Total :		64,92,26,83,431.38	63,30,13,80,225.47
ASSETS			
Cash & Balances with RBI	6	50,66,94,843.70	44,51,51,809.70
Bank Balance with Banks and money at call and short notice	7	6,06,47,31,228.84	6,46,08,21,604.28
Investments	8	48,98,34,99,751.96	47,29,03,17,664.96
Advances	9	5,38,39,31,322.04	5,31,86,56,211.55
Fixed Assets	10	31,35,47,536.68	33,15,16,302.24
Other Assets	11	3,67,02,78,748.16	3,45,49,16,632.74
Total :		64,92,26,83,431.38	63,30,13,80,225.47
Contingent Liability	12		
Bills for collection		-	-

Note: Significant Accounting Policies & Notes on
Schedules referred to above forms an integral part of the Balance Sheet

As per our Report of even date attached
For M/s. P.C. BAFNA & CO.
Chartered Accountants
FRN. NO. 002147C
SD/-
CA RUPALI VYAS
Partner
M.NO. 466344
UDIN :-26466344VBKWRK1595
Place : Bilaspur
Date : 16.06.2026

For, Jila Sahkari Kendriya Bank Mydt, Bilaspur
SD/-
Shri Rajnish Singh
President
SD/-
Shri Prabhat Mishra
Chief Executive Officer
SD/-
Chief Accountant

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2026

PARTICULARS	SCHEDULE	(Current Year) 31-03-2026 (In Rs.)	(Previous year) 31-03-2025 (In Rs.)
Income			
Interest earned	13	3,53,91,65,940.98	3,74,22,29,985.40
Other income	14	4,28,12,748.04	5,20,52,339.77
Total		3,58,19,78,689.02	3,79,42,82,325.17
Expenditure			
Interest expended	15	1,96,12,95,611.32	2,13,83,43,034.30
Operating expenses	16	1,14,81,92,334.94	1,22,44,85,741.13
Provisions & Contingencies			
Total :		3,10,94,87,946.26	3,36,28,28,775.43
Profit / Loss			
Net Profit/Loss (-) for the year		47,24,90,742.76	43,14,53,549.74
Profit/Loss (-) brought forward			
Balance carried over to Balance Sheet			
Total :		47,24,90,742.76	43,14,53,549.74
Appropriations			
Transfer to Statutory reserves			
Transfer to Other reserves			
Transfer to Government/ Proposed dividend			
Balance carried over to balance sheet			
Total :		-	-

As per our Report of even date attached
As per our Report of even date attached
For M/s. P.C. BAFNA & CO.
Chartered Accountants
FRN. NO. 002147C
SD/-
CA RUPALI VYAS
Partner
M.NO. 466344
UDIN :-26466344VBKWRK1595
Place : Bilaspur
Date : 16.06.2026

For, Jila Sahkari Kendriya Bank Mydt, Bilaspur
SD/-
Shri Rajnish Singh
President
SD/-
Shri Prabhat Mishra
Chief Executive Officer
SD/-
Chief Accountant

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 1
CAPITAL

Capital	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. For Nationalised Banks Capital (Fully owned by Central Government)	-	-
II. For Banks incorporated outside India Capital	-	-
(i) (The amount brought in by banks by way of Start-up capital as prescribed by RBI should be shown under this head)		
(ii) Amount of deposit kept with the RBI Under section 11(2) of the Banking Regulation Act, 1949	-	-
Total		
III. For other Banks		
Authorised Capital (Shares of Rs.100 each)	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
Issued Capital (Shares of Rs.100 each)	1,29,27,34,932.20	1,25,43,37,362.20
Subscribed Capital (Shares of Rs.100 each)	1,29,27,34,932.20	1,25,43,37,362.20
Called-up Capital (Shares of Rs..... each)		
Less : Calls unpaid		-
Add : Forfeited shares		-
Total	1,29,27,34,932.20	1,25,43,37,362.20

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS

Particulars	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
RESERVES		
Statutory Reserve Fund	33,80,42,840.89	23,01,79,453.46
Agricultural Stablization Fund	24,22,65,776.99	17,04,91,453.53
Building Fund	48,22,54,385.45	22,45,98,385.45
Divdend Equalization Fund	1,50,558.28	1,30,558.28
OTHER RESERVES		
Bad and Doubtful Debt. Reserve	2,14,33,95,990.87	1,90,19,99,990.87
Investment Depriciation Reserve	1,80,408.00	1,80,408.00
Other Reserves	23,45,96,793.89	44,22,52,793.89
Balance in Profit & Loss Account	74,11,84,336.18	47,78,04,013.31
Total :	4,18,20,71,090.55	3,44,76,37,056.79

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 3
DEPOSITS

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
A.I. Demand Deposit		
(i) From Banks	-	-
(ii) From Others	1,03,39,43,465.79	80,74,89,285.76
Total (I)	1,03,39,43,465.79	80,74,89,285.76
II Saving Bank Deposit	39,90,40,68,692.30	40,75,39,93,400.02
Total (II)	39,90,40,68,692.30	40,75,39,93,400.02
III Term Deposit		
(i) From Banks	-	-
(ii) From Others	6,20,81,67,152.18	5,88,91,94,802.80
Total (III)	6,20,81,67,152.18	5,88,91,94,802.80
Grand Total (I+II+III)	47,14,61,79,310.27	47,45,06,77,488.58
B. (i) Deposits of branches in India	-	-
(ii) Deposits of branches outside India	-	-
Total		

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 4
BORROWINGS

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Borrowing in India		
(i) Reserve Bank of India	-	-
(ii) Other Banks	8560226992.58	7,54,18,55,151.82
(iii) Other Institutions and agencies	-	-
II. Borrowings outside India		
Total : (I and II)	8,56,02,26,992.58	7,54,18,55,151.82
Secured borrowings included in I and II above-Rs.	-	-

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 5
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Provision for loss due to fraud(Sub-Annexure-1)	-	
II.Others (including other provisions except as mentioned in pt(I.) above)	3,74,14,71,105.78	3,60,68,73,166.08
Total	3,74,14,71,105.78	3,60,68,73,166.08

SCHEDULE - 6
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Cash in hand (Including balance with RBI)	50,66,94,843.70	44,51,51,809.70
	-	-
Total : (I and II)	50,66,94,843.70	44,51,51,809.70

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 7
BALANCES WITH BANKS and Money at Call and Short Notice

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. In India	6,06,47,31,228.84	6,46,08,21,604.28
(i) Balance with Banks		
a) In Current Accounts	6,06,47,31,228.84	6,46,08,21,604.28
b) In other Deposit Accounts	-	-
(ii) Money at Call and Short Notice	-	-
a) With Banks	-	-
b) With other Institutions	-	-
Total (I and II)	6,57,14,26,072.54	6,90,59,73,413.98
II. Outside India		
i) In Current Accounts	-	-
ii) In other Deposit Accounts	-	-
(ii) Money at Call and Short Notice	-	-
Total (I,II and III)	-	-
Total (I and II)	6,57,14,26,072.54	6,90,59,73,413.98

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 8
INVESTMENTS

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Investment in India in		
(i) Government Securities	13,85,10,88,550.00	14,17,15,89,300.00
(ii) Other Approved Secutiries	35,000.00	35,000.00
(iii) Shares.	25,60,46,369.28	25,60,46,369.28
(iv). Debentures & Bonds		
(v) Subsidiaries and/or joint ventures		
(vi) Others (in the form of FDR)	34,87,63,29,832.68	32,86,26,46,995.68
Total	48,98,34,99,751.96	47,29,03,17,664.96
II. Investment outside India in		
(i) Government Securities (Including local authorities)	-	-
(ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	-	-
(iii) Others (to be specified)	-	-
Total	-	-
Grand Total (I and II)	48,98,34,99,751.96	47,29,03,17,664.96

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 9
ADVANCES

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
i) Short term loans cash credit & overdraft , bills	5,10,74,46,877.84	5,02,97,97,154.06
Of which secured, against		
a) Govt. & Other approved Securities	50,04,876.00	34,98,814.00
b) Other tangible Securities of the advances	5,09,33,22,826.86	5,01,81,09,655.77
Of which Amt. Due from Individuals	91,19,174.98	81,88,684.29
Of the advances amount Overdue considered bad &DF		-
ii) Medium term loans	19,83,28,470.68	20,49,96,691.65
Of which secured, against		
a) Govt. & Other approved Securities		-
b) Other tangible Securities	10,08,29,791.88	11,51,09,637.73
Of the advances amount, due from Individuals	9,74,98,678.80	8,98,87,053.92
Of the advances amount Overdue considered bad & DF		-
ii) Long term loans	7,81,55,973.52	8,38,62,365.84
Of which secured, against		
a) Govt. & Other approved Securities		-
b) Other tangible Securities	2,06,70,187.48	2,53,09,641.01
Of the advances amount, due from Individuals	5,74,85,786.04	5,85,52,724.83
Of the advances amount Overdue considered bad & DF		-
Total		
Grand Total	5,38,39,31,322.04	5,31,86,56,211.55

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 10
Fixed Assets

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Premises		
At cost as on 31 march of preceding year	41,41,07,647.14	41,18,12,697.14
Addition during the year		
Deduction during the year		
Depreciation to date	16,28,46,527.70	14,96,06,469.70
Total	25,12,61,119.44	26,22,06,227.44
II. Other Fixed Asets (Including furniture and fixtures		
At cost as on 31 march of preceding year	22,07,14,738.02	21,86,65,494.08
Addition during the year	-	-
Deduction during the year	-	-
Depreciation to date	15,84,28,320.78	14,93,55,419.28
Total	6,22,86,417.24	6,93,10,074.80
Grand Total (I and II)	31,35,47,536.68	33,15,16,302.24

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 11
OTHER ASSETS

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Inter- Office adjustments (Net)	90,44,57,847.08	1,78,62,67,500.91
II. Interest accrued		
- On Loans & Advances	83,87,25,784.67	84,06,85,615.91
III. Tax paid in advance /Tax deducted at source	-	-
IV. Others	1,92,70,95,116.41	82,79,63,515.92
Total	3,67,02,78,748.16	3,45,49,16,632.74

Note: In case there is any unadjusted balance of loss the same may be shown under this item with appropriate footnote.

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 12
CONTINGENT LIABILITIES

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Claims against the bank not acknwledged as debt	-	-
II. Liablity for partly paid investments	-	-
III. Liability on account of outstanding forward exchange	-	-
IV. Guarantees given on behalf of constituents	-	-
(a) In India		
(b) Outside India		
V. Acceptances, endorsement and other obligations	-	-
VI. Other items for which the bank is contingently liable DEAF	24,92,86,863.05	-
Total	-	-

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 13
INTEREST EARNED

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
(i) Interest / discount on Advances / Bills	3,53,91,65,940.98	3,74,22,29,985.40
(ii) Income on investments	-	-
(iii) Interest on balances with RBI and other inter bank fund		
(iv) Others	-	-
Total	3,53,91,65,940.98	3,74,22,29,985.40

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 14
OTHER INCOME

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
I. Commission, exchange & brokerage	1,95,73,782.34	1,86,81,573.92
II.Profit on sale of investments	-	-
Less : Loss on sale of investments	-	-
III. Profit on revaluation of investments		
Less : loss on revaluation of investments	-	-
IV. Profit on sale of Land, buildings and other assets	-	-
Less : Loss on sale of Land, buildings and other assets	-	-
V. Profit on exchange transactions	-	-
Less: Loss on exchange transactions	-	-
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and / or joint ventures abroad / in India	-	-
VII. Miscellaneous Income	2,32,38,965.70	3,33,70,765.85
Total	4,28,12,748.04	5,20,52,339.77

Note : Under Items II to V loss figures may be shown in brachets.

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 15
INTEREST EXPENDED

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
Interest on deposits	1,96,12,95,611.32	2,13,83,43,034.30
Others		-
Total	1,96,12,95,611.32	2,13,83,43,034.30

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur (C.G.)
SCHEDULE - 16
OPERATING EXPENSES

PARTICULARS	(Current Year) AS AT 31.03.2026 (In Rs.)	(Previous year) AS AT 31.03.2025 (In Rs.)
Payments to and provisions for employees	37,50,95,292.00	37,41,77,607.00
Rent, Taxes and lighting	22,37,71,434.48	28,22,23,222.51
Printing and stationery	60,10,179.49	62,81,821.47
Depreciation on bank property	2,23,46,232.50	2,37,15,948.09
Auditors fees and expenses (Including branch auditors)	2,300.00	710.00
Law charges	27,24,210.00	37,70,785.00
Postages, telegrams, telephones etc.	8,30,051.19	9,14,951.91
Other expenditure	51,74,12,635.28	53,34,00,695.15
Total	1,14,81,92,334.94	1,22,44,85,741.13

बस्तर-धारा

मंगलवार 23 जून 2026, www.aajkijandhara.com

दुर्गूकोंदल जनपद कार्यालय में जड़ा ताला, कमीशनखोरी और अनियमितताओं के लगाए गंभीर आरोप

सीईओ को हटाने की मांग पर जनपद पंचायत में तालाबंदी

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि

जनधारा समाचार

कांकेर। जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुरेन्द्र बंजारे को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्यों और क्षेत्र के सरपंचों ने जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जनपद पंचायत में विकास कार्यों के संचालन में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं और शिकायतों के बावजूद प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय मामले को नजरअंदाज कर रहा है।

चेक जारी करने के बदले 3 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप: धरना दे रहे जनप्रतिनिधियों ने सीईओ सुरेन्द्र बंजारे पर प्रत्येक निर्माण कार्य के भुगतान संबंधी चेक जारी करने के बदले 3 प्रतिशत कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायतों में विकास कार्य कराने वाले जनप्रतिनिधियों और एजेंसियों को भुगतान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। आरोप है कि कमीशन नहीं देने पर फाइलों को लंबित रखा जाता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

खनिज न्यास निधि के कार्यों को लेकर भी नाराजगी: प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से स्वीकृत निर्माण कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर बाहरी ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है। उनका कहना है कि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और स्थानीय ठेकेदारों को अवसर देने के बजाय बाहर के लोगों को काम सौंपा जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि खनिज न्यास निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है और कई निर्णय बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति के लिए जा रहे हैं।

पहले भी सीईओ हटाने को लेकर हुआ था बड़ा आंदोलन: दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत में सीईओ को हटाने को लेकर यह दूसरा बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। वर्ष 2023 में तत्कालीन सीईओ नीलम उइके के खिलाफ भी जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्यों और भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोला था। उस दौरान खनिज न्यास निधि से खरीदी गई सामग्रियों, खेल सामग्री और सड़क निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। लंबे विरोध-प्रदर्शन के बाद तत्कालीन सीईओ का स्थानांतरण हुआ था।

चेतावनी के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई: धरना दे रहे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को

ज्ञापन सौंपकर चक्काजाम और आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद सीईओ को हटाने या आरोपों की जांच करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज होकर अब जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।

प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल: जनपद कार्यालय में तालाबंदी और धरने के बाद क्षेत्र की राजनीति भी गर्मा गई है। स्थानीय लोगों की नजर अब प्रशासन पर टिकी है कि वह आरोपों की जांच कर क्या कार्रवाई करता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

लिलेझर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर शपथ लिया गया

चारामा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिलेझर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर नियमित रूप से योग करने का शपथ लिया गया ।संस्था के योग शिक्षक विजय राय एवं राजेश महावीर के द्वारा वैदिक मत्रों के साथ सामान्य योग अभ्यास क्रम कामन योगा प्रोटोकॉल का निर्देशों का पालन करते हुए योग कराया गया जिसके अंतर्गत ग्रीवा चालन, स्कंध खिंचाव ,स्कंध चक्र, कटि संचालन, घुटना संचालन, ताड़ासन , वृक्षासन पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, अं त्रिकोण आसन ,दंडासन, भद्रासन ,वज्रासन , उस्त्रासन, शशांक आसन, मंडूकासन, मकरासन, भुजंगासन ,सलभासन सेतु बांध आसान पवनमुक्तासन आदि आसान कराया गया। प्राणायाम के अंतर्गत कपालभाति ,अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी एवं ध्यान कराया गया।

योग पश्चात मुख्य अतिथि गरिमा रावटे जनपद सदस्य चारामा ,विशिष्ट अतिथि के रूप में लक्ष्मण नाग सरपंच लिलेझर,शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरदेव बगमरिया, प्राचार्य लखन लाल ठाकुर, धडुमेश्वर रावटे ,वरिष्ठ व्याख्याता राजेश कोमरा तथा दीपक सेन उपस्थित थे।

शुद्ध पेयजल के लिए सघन क्लोरीनेशन अभियान जारी, 28 हजार से अधिक हैंडपंप होंगे जीवाणुमुक्त

विशेष संधारण अभियान के तहत लगभग तीन हजार हैंडपंपों की हुई मरम्मत

जगदलपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जगदलपुर मंडल द्वारा बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में सघन क्लोरीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा ऋतु के पूर्व शुरू किए गए इस अभियान के तहत स्थापित हैंडपंपों और नल जल योजनाओं का व्यापक स्तर पर क्लोरीनेशन किया जा रहा है।

अभियान के दौरान मैदानी अमले द्वारा संबंधित क्षेत्रों के सभी गांवों में स्थापित पेयजल स्रोतों को जीवाणुरहित बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें स्थानीय समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है। जल प्रबंधन से अधिकतर महिलाओं के जुड़े होने के कारण महिला जल वाहिनी की सक्रिय

भागीदारी देखने को मिल रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कैलाश मंडरिया ने बताया कि आगामी 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के साढ़े 28 हजार से अधिक हैंडपंपों तथा एक हजार से अधिक नल जल योजनाओं के क्लोरीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही जल प्रदाय योजनाओं की जलापूर्ति टंकियों की सफाई भी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि क्लोरीनेशन अभियान के साथ-साथ हैंडपंपों की संधारण स्थिति की भी निगरानी की जा रही है। अप्रैल माह से चलाए गए विशेष संधारण अभियान के तहत लगभग तीन हजार हैंडपंपों की मरम्मत की गई तथा 5 हजार 600 से अधिक राइजर पाइप बदले गए हैं। वर्तमान में भी लगभग साढ़े पांच हजार से अधिक राइजर पाइप और अन्य आवश्यक स्पेयर पार्ट्स जिलों को उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार हैंडपंपों का सुधार कार्य जारी रखा जा सके।

मा. शा गिरहोला के बच्चों ने लहराया अपना परचम

जनधारा समाचार

चारामा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें एक छात्रवृत्ति योजना भी है जिसे राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य परीक्षा एनएमएमएसई कहते हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गिरहोला विगत कई वर्षों से नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा, प्रयास स्कूल परीक्षा इनमें अच्छा परिणाम दे रहा है। इस वर्ष भी शाला के कक्षा आठवीं से दो छात्राओं कु एकता देवांगन और कु ईशा देवांगन का चयन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में हुआ है। शासन द्वारा इन्हें हर महीने 1000 की छात्रवृत्ति कक्षा 12 वीं तक प्रदान की जाएगी। जो इनके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत काम आएगा। शाला में इन परीक्षाओं के तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसका हर वर्ष अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है। बच्चों को उनके सफलता के लिए समस्त स्टाफ ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

सीएम हेल्पलाइन मे प्राप्त आवेदनों का निराकरण शीघ्र करें : कलेक्टर क्षीरसागर

एप के माध्यम से होगी निर्माण कार्यों की समीक्षा

कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत संबंधी आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों को भी शीघ्र निराकृत करने के लिए निर्देशित किया है। निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आगामी 01 जुलाई से डीएमएफ से संबंधित निर्माण कार्यों की समीक्षा ''निर्माण एप'' के माध्यम से की जाएगी तथा जल्द ही अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा भी इसी एप के माध्यम से किया जाएगा। इस व्यवस्था निर्माण कार्यों की सुचारू

मॉनिटरिंग हो सकेगा, जिससे कार्यों में तेजी आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की घोषणा के पालन में स्वीकृत निर्माण कार्यों सहित सांसद एवं विधायक निधि अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई तथा इन कार्यों में भी तेजी लाने कहा गया है।

कलेक्टर द्वारा विभिन्न कार्यालयों के कंडम वाहन जिनका नीलामी हो चुकी है और उक्त वाहन अभी तक परिसर में है, ऐसे वाहनों को तत्काल हटाने के लिए आरटीओ को निर्देशित किया गया है। दूरस्थ अंचलों में दूरसंचार टॉवर, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, किसानों का एग्रीटेक में पंजीयन सहित अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा किया गया एवं समय-सीमा में सभी कार्यों निराकृत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर अंतागढ़ ए.एस. पैकरा, सभी एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों को अनिवार्य करने वाले आदेश के खिलाफ फूटा आक्रोश

- **संयुक्त मोर्चा ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन**

जनधारा समाचार

चारामा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी शिक्षण सत्र से शासकीय विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना के दौरान सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र जैसी धार्मिक गतिविधियों को अनिवार्य किए जाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। इस आदेश के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति संयुक्त मोर्चा ब्लॉक चारामा (उत्तर बस्तर कांकेर) के बैनर तले विभिन्न आदिवासी, सामाजिक, सांस्कृतिक और जन संगठनों ने पुरजोर तरीके से मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को विभिन्न समाजों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने चारामा में एकत्रित होकर कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पहुंचकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और संस्कृति मंत्री के नाम एक कड़ा विरोध पत्र (ज्ञापन) सौंपा।

?संयुक्त मोर्चा ने इस आदेश को भारतीय

संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। संगठनों का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक राज्य है, जहाँ आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट धार्मिक मान्यताएं, पेन परंपरा और जीवन-दर्शन है। ऐसे में किसी एक विशेष धार्मिक परंपरा को थोपना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 28, 29, 46 और पांचवीं अनुसूची के तहत मिले मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही इस आदेश को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आदिवासी समुदायों के अधिकारों के घोषणापत्र के भी विपरीत बताया गया है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, हलबा में उत्साहपूर्वक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

चारामा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, हलबा में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के अनुरूप योग दिवस का आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं नागरिकों को योग के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम की सरपंच श्रीमती सुशीला तारम , ग्राम के गणमान्य नागरिक विक्रम शोरी, विद्यालय के प्राचार्य अमित सक्सेना, उप-प्राचार्य दिवान, संकुल समन्वयक महेश जैन, वरिष्ठ व्याख्याता गवर्ना सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विद्यालय के पी.टी.आई. (व्यायाम शिक्षक) कनक साहू एवं तुषार मांडवी के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। योग सत्र के दौरान विभिन्न योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान तथा मंत्रोच्चारण का अभ्यास कराया गया। साथ ही

विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए नियमित योग के महत्व से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अमित सक्सेना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित एवं संतुलित जीवन जीने की एक उत्कृष्ट जीवन-पद्धति है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

पूरे कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने अत्यंत उत्साह एवं अनुशासन के साथ सहभागिता निभाई। विद्यालय परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से स्वास्थ्य, सकारात्मकता एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश समाज तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

किसान उत्सव दिवस में स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण संस्थाओं ने निभाई सक्रिय भागीदारी

जगदलपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका प्रभाग ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देश जारी कर शनिवार को जून 2026 को आयोजित होने वाले पीएम-किसान उत्सव दिवस को स्व-सहायता समूहों एवं सामुदायिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश पर बस्तर जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंड में स्व सहायता समूहों ने सहभागिता निभाई।

ज्ञात हो कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर, हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किया। इस अवसर को देशभर में पीएम-किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों

को कृषि, आजीविका और ग्रामीण विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का अवसर मिला। ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में स्व सहायता समूहों सदस्यों, किसान परिवारों, ग्रामीण युवाओं और सामुदायिक संस्थाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने कहा गया था। साथ ही स्व सहायता समूहों की बैठकों, ग्राम संगठनों, सी एल एफ एवं अन्य माध्यमों से कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश थे। जिसके परिपालन में कार्यक्रम के दौरान गांवों, ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी।

स्कूलों में गूंजा करो योग रहो निरोग का नारा बच्चों और शिक्षकों ने किया सामूहिक योगाभ्यास

जगदलपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के गरिमामय अवसर पर बस्तर जिले के ग्रामीण अंचल और शैक्षणिक संस्थानों में योग के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विकासखंड जगदलपुर के अंतर्गत आने वाले संकुल केंद्र बाबूसेमरा और ग्राम चिलकुटी के विद्यालयों में विशेष योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर स्वास्थ्य और सजगता का संदेश दिया।

ग्राम चिलकुटी स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में सुबह की ताजी हवा के बीच स्कूल प्रांगण में छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने एक साथ विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस दौरान बच्चों को योग का महत्व समझाते हुए बताया गया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक एकाग्रता बढ़ाने

का सबसे सशक्त माध्यम है। शिक्षकों ने बच्चों को योग से होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए प्रेरित किया कि नियमित योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने का संकल्प भी दिलाया गया।

इसी क्रम में संकुल केंद्र बाबूसेमरा में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां संकुल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने इस सामूहिक योगाभ्यास में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सभी ने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे कई महत्वपूर्ण आसनों का प्रदर्शन किया।

530 एनसीसी गर्ल कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ

बस्तर। रायपुर ग्रुप के अंतर्गत तथा एमपी एवं सीजी एनसीसी निदेशालय के मार्गदर्शन में 1 छत्तीसगढ़ गर्ल्स एनसीसी बटालियन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ 20 जून को परचनपाल में हुआ। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 29 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आई लगभग 530 गर्ल कैडेट्स भाग ले रही हैं।

इस शिविर का उद्देश्य कैडेट्स में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रीय एकता, साहस, आत्मविश्वास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। शिविर के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, मैप रीडिंग, व्यक्तित्व विकास, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा विभिन्न सैन्य एवं साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, समूह चर्चा, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से कैडेट्स के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जनदर्शन में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश

पटवारी पर मनमानी, लापरवाही और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप

- **चार गांवों के लोगों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग**

कांकेर। जिले के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मनकेशरी, नवागांव भावगीर, घोटिया और पारधीपारा के ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को जनदर्शन में खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर हल्का पटवारी सुधीर लकड़ा के खिलाफ शिकायत सौंपते हुए उस पर लापरवाही, मनमानी, भेदभावपूर्ण रवैया, राजस्व कार्यों को वर्षों तक लंबित रखने तथा कथित रूप से रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए बनाई गई राजस्व व्यवस्था का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो टाल देते हैं: ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि भूमि सीमांकन, नक्शा त्रुटि सुधार, फौती नामांतरण, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्य महीनों नहीं बल्कि वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि पटवारी से संपर्क करने के लिए कई बार फोन लगाए जाते हैं, लेकिन फोन नहीं उठाया जाता। वहीं कार्यालय पहुंचने पर भी लोगों को आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रवैये के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। कई मामलों में लोगों के जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पाने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो रहा है।

काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप: ग्राम मनकेशरी निवासी प्रेम कुमार और राकेश जुर्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी सुधीर लकड़ा पर काम के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

सर्व समाज प्रमुखों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन

आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा, जल-जंगल-जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की उठाई मांग

बीजापुर। जिले के विभिन्न आदिवासी सामाजिक, सांस्कृतिक, युवा एवं जनसंगठनों के प्रतिनिधियों तथा सर्व समाज प्रमुखों ने सोमवार को राज्यपाल के नाम 15 सूत्रीय मांगों से संबंधित संयुक्त ज्ञापन कलेक्टर बीजापुर को सौंपा। ज्ञापन में आदिवासी समाज के संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई।

प्रतिनिधियों ने बताया कि 6 जून को रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित सर्व समाज की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों के आधार पर यह मांगपत्र तैयार किया गया है। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय से जुड़ी है तथा राज्य का लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऐसे में संविधान प्रदत्त अधिकारों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

ज्ञापन में जनगणना में पृथक आदिवासी धर्म कोड की मान्यता, परिसीमन के दौरान आदिवासी प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, निजीकरण पर रोक तथा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अलावा आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों की जांच, भू-माफिया नियंत्रण कानून लागू करने, भूमि अधिग्रहण एवं खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति, खनिज संपदा से होने वाले लाभ में स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा

नक्सल मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी युवाओं की रिहाई की मांग भी की गई।

ज्ञापन में धर्म परिवर्तन के आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए देवगुड़ियों, सरना स्थलों, गोटुल एवं अन्य पारंपरिक आस्था केंद्रों को कानूनी संरक्षण देने, पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आदिवासी शिक्षा एवं मातृभाषा संरक्षण के लिए विशेष पहल करने की मांग भी शामिल है।

सर्व समाज प्रमुखों ने राज्यपाल से आदिवासी समाज की अस्मिता, स्वशासन, परंपरागत अधिकारों एवं संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर आवश्यक हस्तक्षेप कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी, कंवर समाज अध्यक्ष कमलेश पैंकरा, गोंड समाज अध्यक्ष पांडुराम तेलाम, मुरिया समाज के पाकलु तेलम, उरांव समाज अध्यक्ष पी.आर. भगत, तेलगा समाज प्रमुख मंगल रोटेल, महिला प्रभाग की सावित्री हपका, रानी पुनेम, सरोजना ताती, रैनू ओयाम, गुड्डू मोडीयम सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं समाज प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

तसर खाद्य पौधों की नर्सरी तैयार करने का प्रशिक्षण आयोजित

- **अर्जुन एवं साजा के 5,000 पौधे तैयार, तसर पालन से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय**

बीजापुर। कार्यालय सहायक संचालक रेशम के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कोसा बीज केंद्र भैरमगढ़ के हितग्राहियों को तसर खाद्य पौधे अर्जुन एवं साजा की नर्सरी तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन की तकनीक से अवगत कराना तथा तसर पालन के लिए आवश्यक खाद्य पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों को बीज चयन, बीज अंकुरण की विधि, पॉलीबैग में मिट्टी, रेत एवं जैविक खाद के उचित अनुपात, पौधों की देखभाल, संरक्षण एवं नर्सरी प्रबंधन की संपूर्ण तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप हितग्राहियों द्वारा लगभग 5,000 अर्जुन एवं साजा के पौधे तैयार किए गए हैं।

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में तैयार इन पौधों को आगामी वर्ष लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपित किया जाएगा। पौधों के पूर्ण विकसित होने के बाद इन पर लगभग 400 तसर स्वस्थ डिम्भ समूहों का पालन किया जा सकेगा, जिससे अनुमानित 20,000 कोसों का उत्पादन प्राप्त होगा। उत्पादित कोसों का औसत बाजार मूल्य लगभग 60 हजार रुपये होने का अनुमान है। इससे हितग्राहियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तसर पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण हितग्राहियों के लिए रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि का प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है।

जिले के नानगुर तहसील में दर्ज की गई सबसे ज्यादा वर्षा

जगदलपुर। सोमवार की सुबह बस्तर जिले के कई हिस्सों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसने चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार 22 जून को सुबह की शुरुआत बेहद सुहावनी रही और अलग-अलग क्षेत्रों में मध्यम से भारी बौछारें दर्ज की गईं। इस दौरान बस्तर जिले की नानगुर तहसील में सबसे अधिक 15.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जिला मुख्यालय जगदलपुर में 10.8 मिलीमीटर वर्षा के साथ मौसम खुशनुमा हो गया। इसके अलावा बस्तर तहसील में 9.5 मिलीमीटर और लोहांडीगुड़ा में 7.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि भानपुरी में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं बकावण्ड, बस्तानार, दरभा, तोकापाल और करपावण्ड जैसे क्षेत्रों में सुबह पानी नहीं बरसा, लेकिन आसमान में बादल घिरे हुए हैं। वर्तमान मानसून सीजन में 1 जून 2026 से अब तक बस्तर तहसील में उम्मीद से काफी बेहतर बारिश हुई है।

बस्तर में स्वच्छता का नया उजाला

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लेकर गांवों में अभियान जारी

जनधारा समाचार

जगदलपुर। बस्तर जिले को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। पूरे देश में 01 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बस्तर जिले की ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गति देने के लिए ग्राम पंचायत आड़ावाल, चेराकुर, बुरुन्दवाड़ा, बिलोरी और हल्बा कचोरा सहित कई गांवों में जन-जागरूकता चरम पर है, जहां ग्राम पंचायत भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और हाट-बाजारों में दीवार लेखन और ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। दीवारों पर चार डिब्बा चार रंग, स्वच्छता का नया उमंग और हरा, नीला, लाल और काला (या पीला), यही है स्वच्छता का उजाला जैसे

आकर्षक नारे लिखे गए हैं जो ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं।

इस नई पहल के तहत ग्रामीणों को अपने घरों से ही कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर डस्टबिन में डालने की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके तहत रसोई के कचरे, फल, सब्जी के छिलके और बासी भोजन जैसे गीले कचरे को हरे डस्टबिन में डालने की सलाह दी गई है। वहीं कागज, प्लास्टिक, गत्ता, कांच और बोतल जैसे सूखे कचरे के लिए नीले डस्टबिन का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सैनिटरी पैड, डायपर, मेडिकल वेस्ट और ब्लेड जैसे सैनिटरी अपशिष्ट को लाल डस्टबिन में तथा खराब बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल और चार्जर जैसे हानिकारक ई-वेस्ट को पीले डस्टबिन में पृथक रूप से संग्रहित करने की समझाइश दी जा रही है। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए स्वच्छता दीदियां, महिला स्व-सहायता समूह और पंचायत प्रतिनिधि खुद घर-घर पहुंचकर लोगों को कचरा अलग करने की इस पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा रहे हैं।

आधार की उलझन सुलझी, चेहरे पर लौटी मुस्कान

- **जिला प्रशासन की सजगता से सोड़ी पोज्जे और सोड़ी लच्छी को मिला ई-आधार**

दोरनापाल। सुकमा जिला प्रशासन सुकमा द्वारा आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने और उनकी जमीनी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए ग्राम साकलेर की महिला आवेदिका सोड़ी पोज्जे और ग्राम ताड़मेटला की सोड़ी लच्छी की एक बड़ी तकनीकी समस्या का स्थाई समाधान निकाला है। ये दोनों हितग्राही वर्ष 2024 में आधार नामांकन कराने के बाद भी तकनीकी त्रुटियों के कारण भौतिक आधार कार्ड न मिलने से परेशान थीं और लंबे समय से महत्वपूर्ण शासकीय लाभों से वंचित चल रही थीं। जब दोनों महिलाओं ने दोबारा नया आधार कार्ड बनवाने का प्रयास किया, तो पोर्टल पर आधार पहले ही जारी हो चुका है का एरर प्रदर्शित होने लगा। नियमानुसार एक व्यक्ति का दोबारा नामांकन संभव न होने के कारण यह मामला उलझ गया था और हितग्राही असमंजस में थीं।

इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासन और तकनीकी टीम ने मुस्तैदी दिखाई। अधिकारियों ने नियमों के दायरे में रहकर आवेदिकाओं के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला, गहन जांच की और उनके पूर्व में जेनरेट हो चुके आधार नंबर को सफलतापूर्वक ट्रैक कर लिया।

बीजापुर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत

ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने किया प्रदर्शन

बीजापुर। बीजापुर जिले में डीजल-पेट्रोल की किल्लत को लेकर किसान और आम जनता परेशान हैं। इस समस्या को लेकर विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में पूरे बीजापुर के किसान और यूनियन नैमेड से ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां मिनीग्राउंड में आम सभा का आयोजन किया गया।

सभा में विधायक मंडावी ने सरकार और प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के ढाई वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार आम जनता की समस्याओं का निराकरण नही कर पा रही है। बरसात का समय आ चुका है। किसान खाद, बीज के लिए परेशान तो थे ही, परंतु अब बड़ी समस्या पेट्रोल, डीजल की उत्पन्न हो गई है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा, किसान पेट्रोल पंपों में जा रहे हैं तो पंप के कर्मचारियों द्वारा गलत बरताव कर भगा दिया जा रहा है। ऐसी कई समस्याएं किसानों को खेती करने में आ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस समस्या का जल्द समाधान करें अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे।

व्यापारी दुकानों में अधिक दामों पर बेच रहे डीजल-पेट्रोल

दूर-दराज से आए किसानों का कहना है कि बारिश का मौसम आने को है। हम किसान पेट्रोल-डीजल के लिए भटक रहे हैं। हमें चिंता सता रही है कि हम फसल इस बार अपनी खेतों में कैसे बोएंगे। डीजल-पेट्रोल के लिए जाने पर पंप के कर्मचारी बदतमीजी से पेश तो आते ही हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल के लिए भी मना किया जाता है। वहीं हमारे सामने व्यापारियों को डीजल पेट्रोल जरकिन और डिब्बों में दिया जा रहा है। फिर वही व्यापारी अपने दुकानों से हमें ब्लैक में डीजल, पेट्रोल की कीमत से अधिक दामों में बेचा जा रहा है। इस मामले में प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो निंदनीय है।

माँ बम्बलेश्वरी स्वयं सहायता समूह बना आत्मनिर्भरता की मिसाल

- **सीमेंट ईंट निर्माण से महिलाओं ने कमाए 69,600, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ाए कदम**

बीजापुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुल्लापेंटा में संचालित माँ बम्बलेश्वरी स्वयं सहायता समूह ने सामूहिक प्रयास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से गठित इस समूह ने आजीविका संवर्धन के लिए सीमेंट ईंट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर परिश्रम करते हुए लगभग 3000 सीमेंट ईंटों का निर्माण एवं विक्रय किया, जिससे उन्हें लगभग

69,600 की आय प्राप्त हुई। यह उपलब्धि महिलाओं के सामूहिक श्रम, समर्पण और आत्मविश्वास का परिणाम है।

प्राप्त आय से समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं ने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा भविष्य के लिए बचत पर भी विशेष ध्यान देना शुरू किया है। समूह की नियमित बैठकों, आपसी सहयोग और एनआरएलएम के सतत मार्गदर्शन ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया तथा उन्हें स्वरोजगार के नए अवसरों की ओर अग्रसर किया।

28 से 30 जून तक चलेगा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान

- **जिले में 76,544 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक**

कांकेर। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दो बून्द खुराक पिलाकर प्रतिरक्षित किया जाएगा। इस अभियान के दूसरे एवं तीसरे दिन टीकाकर्मी दल द्वारा घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में इस संबंध में आज जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 76,544 बच्चों

के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 1,281 पोलियो बूथ बनाए गए हैं तथा 3,155 बूथ टीकाकर्मी दलों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 1,274 घर-घर भ्रमण दल सदस्य तथा 31 ट्रांजिट टीम सदस्य तैनात किए जाएंगे। बताया गया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के पिछले चरण में जिले में 76,967 बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध 76,940 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी, जो लगभग 96.06 प्रतिशत उपलब्धि रही।

अभियान के सफल संचालन के लिए जिले के सभी विकासखण्डों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए पोलियो बुथ एवं आवश्यक टीम गठित की गई है। विकासखण्ड अंतागढ़ में 228 पोलियो बुथ में 460 टीकाकर्मी दल, भानुप्रतापपुर में 130 पोलियो बुथ में 441 टीकाकर्मी दल, चारामा में 111 पोलियो बुथ में 422 टीकाकर्मी, दुर्गूकोंदल में 147 पोलियो बुथ में 320 टीकाकर्मी, कांकेर ग्रामीण में 134 पोलियो बुथ में 337 टीकाकर्मी दल, कोयलीबेड़ा में 372 पोलियो बुथ में 720 टीकाकर्मी, नरहरपुर में 135 पोलियो बुथ में 370 टीकाकर्मी दल और कांकेर शहरी में 24 पोलियो बुथ में 85 टीकाकर्मी दल नियुक्त किया गया है। इस अभियान के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर से बी.ओ.पी.वी. वैक्सीन की 96 हजार खुराकें प्राप्त हो चुकी हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान को सफल बनाएं।

उल्लेखनीय है कि 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो-मुक्ति का प्रमाण-पत्र मिलना एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय उपलब्धि है। तब से भारत 14 वर्ष से अधिक समय से पोलियो-मुक्त है। विश्व स्तर पर वाइल्ड पोलियो वायरस का प्रसार अभी भी बच्चों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें भारत के कुछ पड़ोसी देश भी शामिल हैं, जिससे रोग के पुनः संक्रमण का जोखिम बना हुआ है।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर अंतागढ़ श्री ए.एस. पैकरा, एसडीएम कांकेर अरूण वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. ठाकुर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. ओ.पी. शंखवार सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

जनदर्शन में मिले 40 आवेदन

- **सभी आवेदनों को त्वरित निराकृत करने कलेक्टर ने दिए निर्देश**

कांकेर। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के पहुंचे 40 आवेदकों ने अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को अवगत कराया। प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया।

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित जनदर्शन में ग्राम पंचायत पानीडोबीर के ग्रामीणों द्वारा एकलव्य विद्यालय निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार भूमि रजिस्ट्रीकरण, नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास, वारिसान प्रमाण पत्र, दुकान संचालित हेतु लोन, राशन कार्ड बनाने, जल जीवन

मिशन अंतर्गत कनेक्शन प्रदान करने, विद्युत पोल हटाने, भूमि आबंटन, नक्शा, खसरा दुरुस्तीकरण सहित विभिन्न मांग एवं समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर क्षीरसागर ने प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। जनदर्शन के अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर अंतागढ़ ए.एस. पैकरा, सभी एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने दिया करें योग रहें निरोग का संदेश

- **दिनचर्या में शामिल करने का लिया संकल्प**

जगदलपुर। कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर एक विशेष और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए करें योग रहें निरोग का महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित किया गया।

इस विशेष अवसर पर शिवम योग समिति जगदलपुर से मुख्य मार्गदर्शक के रूप में किशोर पारख उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों को विभिन्न योग क्रियाओं का व्यावहारिक अभ्यास कराया। उन्होंने योगाभ्यास के वैज्ञानिक लाभों और मानव शरीर तथा मस्तिष्क पर योग के सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को मानसिक एकाग्रता और शारीरिक सुदृढ़ता के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी, जिससे छात्र

अत्यधिक प्रभावित हुए। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ विभिन्न प्रकार के योगासनों जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, भुजंगासन, भ्रामरी और शवासन के महत्व को समझा और इनके माध्यम से शारीरिक व मानसिक विकास तथा तनाव मुक्ति की तकनीकों को जाना। योग की इन अद्भुत विधाओं से प्रभावित होकर उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं ने स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने का दृढ़ संकल्प भी लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि महाविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता एवं सहायक संचालक अनुसंधान डॉ एके ठाकुर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एनसीसी स्टाफ से पृथ्वीराज मोहंती उपस्थित रहे। इस पूरे गरिमापूर्ण आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने में एनएसएस प्रभारी डॉ सोनाली कर के साथ-साथ शिवम योग समिति जगदलपुर के धीरज राठी और डॉ संदीप जोशी एवं डॉ. विक्की कुमार ने अपना सक्रिय योगदान दिया।

फरसगांव में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन

कोण्डागांव। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत फरसगांव के नवीन सभा कक्ष में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पात्र एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष मानकू नेताम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर एसडीएम फरसगांव अश्वन कुमार पुसाम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मयंक कुमार बसन्तवानी, टी.एल. नाग, योग साधक योगेश्वर साहू सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन एवं जन-जागरूकता का संदेश दिया।

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रही, जो जीवन के प्रत्येक पड़ाव में स्वस्थ, सक्रिय एवं संतुलित रहने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम के दौरान योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर को निरोग, मन को प्रसन्न तथा जीवन को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों ने नियमित रूप से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

टाटामारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

कोण्डागांव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टाटामारी, केशकाल में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सेवकराम नेताम, नगर पंचायत अध्यक्ष बिहारीलाल शोरी, पार्षदगण, वनमंडलाधिकारी केशकाल श्रीमती दिव्या गौतम, एसडीएम सुश्री आकांक्षा नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षक सुनील जैन ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा कहा कि योग को दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाकर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। उन्होंने सभी से निरोग एवं स्वस्थ जीवन के लिए नियमित रूप से योग अपनाने का आह्वान किया।

सरकार की लाचरता से शराबखोरी और अय्याशी का अड्डा बना मनगटा : रूपेश दुबे

राजनांदगांव। छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने कहा कि आए दिन मनगटा क्षेत्र में अवैध कारोबार के समाचार से पूरा क्षेत्र कलंकित हो गया है और अब यह इलाका शराबखोरी अय्याशी और देह व्यापार का केंद्र बिंदु बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जिला होने के बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण इन अवैध कारोबारियों के लगातार अनैतिक कार्य सामने आ रहे है। कार्यवाही दिखावे मात्र के होने के कारण यहाँ के अवैध कृत्यों में संलिप्त कारोबारियों के सामने प्रशासन बौना साबित हो गया है।

प्रवक्ता दुबे ने यह भी कहा कि अब अवैध निर्माण जिन रिसॉर्ट के डायवर्शन नहीं है, जिन रिसॉर्ट में अनैतिक आपत्तिजनक सामग्री मिले है, जहां शराबखोरी हो रही है, जो अय्याशी अघोषित देह व्यापार का केंद्र बना कर सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे है, उन्हें जमीदोज करना ही सीधा व सरल उपाय है, क्योंकि अवैध प्लाटिंग या कब्जा से ज्यादा खतरनाक ये अवैध व्यापारियों के रिसॉर्ट है, क्योंकि इनके दुष्कृत्य से इस क्षेत्र की संस्कृति सभ्यता का क्षरन और अनैतिक वातावरण बन गया है। 150 से अधिक रिसॉर्ट में मात्र 15 से 20 को नोटिस जवाब की औपचारिकता से कुछ नहीं होगा, बल्कि सजग कलेक्टर से इस क्षेत्र के रिसॉर्ट का डायवर्शन ना कर अवैध निर्मित रिसॉर्ट को जमींदोज करने की मांग की है।

अघोर आश्रम के अनुयायियों ने मोतीपुर मुक्तिधाम में चलाया स्वच्छता अभियान

- गुरुदेव हरीश यादव के मार्गदर्शन में जुटे सेवाभावी
- प्रत्येक रविवार को अलग-अलग मुक्तिधामों की बदलेगी सूरत

राजनांदगांव। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से शक्तिधाम अघोर शोध एवं जनकल्याण आश्रम, बाबूटोला द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का शंखनाद किया गया है। इसके तहत आश्रम के अनुयायियों ने इस रविवार को मोतीपुर स्थित मुक्तिधाम परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया। आश्रम के गुरुदेव हरीश यादव के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में सेवाभावी सदस्यों ने श्रमदान कर पूरे परिसर की सूरत बदल दी।

समिति ने इस अभियान को केवल एक दिन तक सीमित न रखकर एक दूरगामी कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक रविवार को शहर के अलग-अलग वार्डों के मुक्तिधामों को चिन्हित कर वहां विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा। मोतीपुर मुक्तिधाम में अभियान के दौरान न केवल झाड़ियों और कचरे को साफ किया गया, बल्कि नागरिकों से सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया गया।

गुरुदेव हरीश यादव ने कहा कि समाज की सक्रिय सहभागिता से ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। हर नागरिक को इस जिम्मेदारी को समझना होगा।

आश्रम द्वारा शुरू की गई इस अनूठी और अनुकरणीय पहल की पूरे शहर में जमकर सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस तरह का अभियान चलाना समाज को एक नई दिशा देगा।

विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

भिलाई। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रथम वाहिनी छसबल परिसर में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर के सहयोग से आयोजित इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में लगभग 500 अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) जैसी महत्वपूर्ण जांचें निःशुल्क की गईं, वहीं जरूरतमंदों को दवाएं भी वितरित की गईं।

जवानों की सेहत को प्राथमिकता, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजन

प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रशासनिक भवन में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का संचालन पुलिस महानिदेशक ए.डी. गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा , पुलिस महानिरीक्षक बी.एस. ध्रुव तथा उप पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय) सदानंद के मार्गदर्शन में किया गया।

शिविर के दौरान सेनानी एवं डीआईजी राजेश कुकरेजा की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उप सेनानी प्रज्ञा मेश्राम, सहायक सेनानी जयलाल मरकाम, सहायक सेनानी गोरखनाथ सहित मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

हृदय, हड्डी, लिवर और सामान्य रोगों के विशेषज्ञों ने दिया परामर्श : शिविर में मेडिशाइन हॉस्पिटल के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने विभिन्न रोगों से संबंधित स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्रदान किया। हृदय रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, पेट और लिवर संबंधी समस्याओं के साथ-साथ सामान्य मौसमी बीमारियों के उपचार एवं बचाव को लेकर भी मार्गदर्शन दिया गया।

विशेष रूप से एसटीएफ के चिकित्सक डॉ. अमित चंद्राकर ने भी अपनी सेवाएं देते हुए जवानों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

आधुनिक मशीनों से हुई जांच, मुफ्त बांटी गई दवाएं : शिविर में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सहायता से ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बीएमडी जांच की गई। परीक्षण के बाद जिन जवानों और परिजनों को उपचार की आवश्यकता महसूस हुई, उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श देने के साथ आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं।

चौबीसों घंटे सेवा देने वाले जवानों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रयास : अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अपने जवानों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमेशा संवेदनशील रहा है। इसी सोच के तहत समय-समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि प्रदेश और देश की सुरक्षा में दिन-रात जुटे जवान स्वस्थ, फिट और ऊर्जावान बने रहें।

राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे जय प्रकाश साहू

राजनांदगांव। युवा कांग्रेस जिला महामंत्री जयप्रकाश साहू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की। जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से ही बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच रहे थे तथा पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना हुआ था।

केंद्र सरकार धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है : कुलबीर

राजनांदगांव। कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह छाबड़ा ने नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के कारण छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है, जिससे उनकी मेहनत और समय प्रभावित हुआ है।

श्री छाबड़ा ने नीट-यूजी की परीक्षा पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाईड लाइन पर कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार युवाओं की मेहनत पर पानी फेरते हुए गड़बड़ियां कर नीट की परीक्षा रद्द करवा दिया, अब जब दोबारा हो रही परीक्षा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए खिलवाड़ किया गया। अर्धसैनिक बल और पूरी मिलेट्री बल लगाकर यह परीक्षा आयोजित की गई। हिन्दूवाद की बात कहने वाली भाजपा सरकार नए गाईड लाइन में परीक्षा केंद्रों पर मौली (धार्मिक धागा) और चेन जैसी वस्तुएं उतरवाने के नियम लोगों की आस्था से जुड़े प्रतीकों का अनादर करते हैं। हाथों में श्रद्धा और धार्मिक मान्यताओं के तहत पहनी जाने वाली मौली धागा को उतरवाना और तोड़कर फेंकना अनुचित है। यह नीट की परीक्षा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान लागू की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अर्धसैनिक बलों व मिलेट्री बलों की मौजूदगी में परीक्षा आयोजित किए जाने से अनावश्यक भय का माहौल बना है। वहीं देश के बाहर दूसरे 15 शहरों से जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उसमें मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है ।

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

अब अहिवारा में ही संचालित होगा संभागीय कार्यालय

दुर्ग। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड(सीएसपीडीसीएल), दुर्ग क्षेत्र ने उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है, पूर्व में जो विद्युत संभागीय कार्यालय अहिवारा, भिलाई-3 में स्थित था, उसे अब वहां से स्थानांतरित कर पूरी तरह से अहिवारा में ही कार्यशील कर दिया गया है। 20 मई 2026 से इस कार्यालय ने (जामुल रोड, मंगल भवन के सामने, सबस्टेशन परिसर) अहिवारा स्थित नवीन भवन में अपना कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया है।

इस स्थानांतरण का सीधा लाभ क्षेत्र के आठ वितरण केंद्रों से जुड़े 86 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को होगा। अब उन्हें अपनी बिजली संबंधी समस्याओं, बिल सुधार या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 25 किलोमीटर दूर भिलाई-3 की लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ही बिजली संबंधी बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इस संभागीय कार्यालय के अंतर्गत कुम्हारी और धमधा उपसंभाग के अंतर्गत आने वाले सभी वितरण केंद्र - धमधा, ठेलका, दारगांव, ननकट्ठी, कुम्हारी, मुरमुंदा, अहिवारा और जामुल शामिल हैं। कार्यालय के अहिवारा में खुल जाने से इन वितरण केंद्रों में उपभोक्ताओं को अब अपने बिल संबंधी कार्यों, विद्युत शिकायतों के निवारण या अन्य विद्युत सेवाओं के लिए अब भिलाई-3 नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल स्थानीय स्तर पर बेहतर और त्वरित सेवाएं प्रदान करने की दिषा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंतर्राज्यीय सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश

तीन आरोपी गिरफ्तार, ढाई लाख रुपये की सामग्री जब्त

भिलाई। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ-सट्टा और अवैध वित्तीय लेन-देन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्युल अकाउंट के जरिए संचालित एक अंतर्राज्यीय सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। थाना खुर्सीपार पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित लगभग ढाई लाख रुपये की सामग्री जब्त की है।

एडिशनल एसपी एवं पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। बाद में पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड अपने कब्जे में लेकर इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टे और अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता था।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस को सूचना मिली थी कि खुर्सीपार स्थित आईटीआई खेल मैदान के पास पुलिस ने अजय मिश्रा (23 वर्ष), निवासी सेक्टर-1, एवेन्यू-सी, भिलाई ,दीपक कुमार (32 वर्ष), निवासी नगदोई, जिला नालंदा (बिहार) ,करण कुमार सिंह (26 वर्ष), निवासी बालाजी नगर, खुर्सीपार निवासी कुछ युवक लैपटॉप और मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण बरामद हुए।

अन्ना रेड्डी एप के जरिए चलता था कारोबार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अन्ना रेड्डी ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टा कारोबार संचालित करते थे। आईपीएल सीजन के दौरान यह नेटवर्क झारखंड के रांची से संचालित किया गया। सट्टे से प्राप्त रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर वित्तीय गतिविधियों को छिपाने की कोशिश की जाती थी। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर पैसों के प्रवाह को छिपाया जाता था।

ऐसे काम करते थे म्युल अकाउंट

विवेचना में खुलासा हुआ कि आरोपी जरूरतमंद लोगों को कुछ राशि देने का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। खाता खुलने के बाद संबंधित व्यक्ति से एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल सिम ले लिए जाते थे। साइबर अपराध की दुनिया में ऐसे खातों को म्युल अकाउंट कहा जाता है। इन्हीं खातों के जरिए ऑनलाइन सट्टे की रकम का ट्रांसफर, निकासी और लेयरिंग की जाती थी, जिससे धन के स्रोत और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान छिपी रहे।

प्रतिबंधित नशीली सामग्री और घातक हथियारों की आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बैठक संपन्न

- पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त बैठक
- कूरियर संचालकों और प्रतिनिधियों को सुरक्षा एवं निगरानी संबंधी आवश्यक निर्देश

भिलाई। कूरियर एवं ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित नशीली सामग्री और घातक हथियारों की आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सोमवार को दुर्ग पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कंट्रोल रूम सेक्टर-06 में आयोजित इस बैठक में कूरियर कंपनियों के संचालकों और प्रतिनिधियों को सुरक्षा एवं निगरानी संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पार्सल बुकिंग के दौरान प्रेषक, प्राप्तकर्ता और बुकिंग कराने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त कर अभिलेखों में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कूरियर केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा कम से कम एक माह तक फुटेज सुरक्षित रखने को अनिवार्य बताया। संदिग्ध पार्सल मिलने पर तत्काल संबंधित थाना पुलिस को सूचना देने तथा नशीली औषधि या मादक पदार्थ होने की आशंका होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में औषधियों से संबंधित पार्सलों के लिए अलग रजिस्टर संधारित करने, प्रेषक और प्राप्तकर्ता की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने तथा ऐसे पार्सलों में ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि कूरियर सेवाओं का दुरुपयोग कर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की घटनाओं को रोकने के लिए सभी संचालकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस दौरान वैधानिक दायित्वों और सुरक्षा उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक संचालक संजय सिंह, औषधि निरीक्षक विष्णु प्रसाद साहू, गायत्री पटेल, जागेश्वरी साहू सहित विभिन्न कूरियर कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्वस्थ आयु के लिए योग अपनाने का संदेश, मंगल भवन में भव्य योग शिविर आयोजित

भिलाई 3। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा द्वारा रविवार को मंगल भवन परिसर में स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, निगम कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। साथ ही योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की विस्तार से जानकारी देते हुए नियमित योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और तनावमुक्त जीवन जीने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है।

कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, दिलीप पटेल, परिषद में नेता प्रतिपक्ष खिलावन वर्मा, वरिष्ठ पार्षद फिरोज फारुकी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। वहीं एसडीएम महेश सिंह राजपूत, निगम आयुक्त डी.एस. राजपूत, कार्यपालन अभियंता प्रेमलता चंद्राकर, ईई राजू, हेमंत, वीणू, मुकेश यादव, यशवंत

ठाकुर, श्यामता साहू, आशीष वर्मा सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा पतंजलि योग समिति की ओर से सुशीला व्यापारी सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने योग शिविर में भाग लिया। सामूहिक योगाभ्यास के दौरान पूरे परिसर में स्वास्थ्य, सकारात्मकता और अनुशासन का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा नियमित योग करने और स्वस्थ एवं निरोग समाज के निर्माण में योगदान देने के संकल्प के साथ हुआ। आयोजकों ने कहा कि योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर अनेक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है तथा बेहतर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है।

GST रजिस्ट्रेशन नम्बर बनवाएं मात्र 3 दिन में
5 साल पुरानी ITR फाइल बनवाएं
मात्र 5000/- में
(व्हाट्सएप पर बनवाएं)
www.onlytds.com
GST-Return
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
TDS रिफंड
CMA DATA
MSME रजिस्ट्रेशन
Food लाइसेंस
संपर्क - शेखर गुप्ता 9300755544, 8878655544

Chola
Enter a better life

चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी-54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का, इंडस्ट्रियल स्टेट, गुइंडी, चेन्नई- 600032.
शाखा कार्यालयः सातवीं मंजिल, करेंसी टावर, वीआईपी चौक
जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आपको, नीचे उल्लेखित ऋणी/बंधककर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके विरुद्ध वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरु की है तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा नोटिस भेजा गया, जो कि वापस लौटा दिया गया है। इसलिए आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त खाते के खिलाफ उल्लेखित बकाया ऋण राशि का नोटिस लेने और ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर कंपनी अपने अधिकार अधिनियम की धारा 13(4) का प्रयोग करके आपके खिलाफ कार्यवाही करेगी एवं नीचे उल्लेखित सुरक्षित संपत्ति का प्रवर्तन करके ब्याज एवं लागत के साथ आपने बकाया की वसूली करेगी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह नोटिस कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको संबोधित किया गया है।

ऋणी का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण
Loan Account - HE01HCH00000083625 **1. मनोज कुमार देवांगन पुत्र सुरेंद्र प्रसाद देवांगन, (आवेदक)**, मकान नं. 123, कोतरा रोड, दिनेश इलेक्ट्रिकल्स के पास, मेन रोड, रायगढ़, (छ.ग.)- 496001., **2. मेसर्स मनोज हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इसके मालिक के माध्यम से- मनोज कुमार देवांगन (सह-आवेदक)**, दिनेश इलेक्ट्रिकल्स के पास, कोतरा रोड, रायगढ़ (छ.ग.) - 496001, **3. सविता देवांगन पति मनोज कुमार देवांगन (सहआवेदक)**, मकान नं. 123, कोतरा रोड, दिनेश इलेक्ट्रिकल्स के पास, मेन रोड, रायगढ़, (छ.ग.) - 496001. **4. मेसर्स सविता हैंडलूम, इसके प्रोपाइटर सविता देवांगन (सह-आवेदक)** के माध्यम से- , **सी/ओ. मनोज कुमार देवांगन**, रायगढ़-सारंगढ़ रोड, सीपीएम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कुशल नगर, दानसरा, सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) - 496445, **5. सुरेंद्र प्रसाद देवांगन पुत्र शंकर लाल देवांगन (सह-आवेदक)**, मकान नं. 123, कोतरा रोड, दिनेश इलेक्ट्रिकल्स के पास, मेन रोड, रायगढ़, (छ.ग.) - 496001, **6. मेसर्स सुरेंद्र प्रसाद देवांगन** इसके मालिक **सुरेंद्र प्रसाद देवांगन (सह-आवेदक)** के माध्यम से- , दिनेश इलेक्ट्रिकल के पास, कोतरा रोड, रायगढ़, तहसील व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)- 496001.	₹ 40,00,000.00	08/06/2026 ₹ 39,34,470.00 as on 08/06/2026 उस पर ब्याज सहित एनपीए तिथिः 03/06/2026	खसरा नं. 306/12 (जिसमें खसरा नं. 307/12 एवं 308/12 भी शामिल हैं) मौजा- सारंगढ़, प.ह.नं.- 28 (पुराना प.ह.नं.-20), रा.नि.मं.- सारंगढ़, तहसील- सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (पहले रायगढ़ जिले में) छत्तीसगढ़। जो 0.020 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित रिहायशी प्लॉट वाली अचल संपत्ति के समस्त भाग व अंश। **चौहद्दीः उत्तर-** गली, **दक्षिण-** अछेराम, **पूर्व-** सेवति बाई, **पश्चिम-** उपेंद्र व हेमंत।
Loan Account - HE01LAI00000017928 **1. उत्तम चंद जैन पुत्र केवल चंद जैन (आवेदक), 2. लक्ष्मी बाई जैन पति उत्तम चंद जैन (सह-आवेदक), 3. विजय लाल जैन पुत्र केवल चंद जैन (सह-आवेदक), सभी का पताः** हनुमान मंदिर के पास, दुर्गा चौक, बाजार रोड, चन्द्रशेखर वार्ड नं. 12, ग्राम व पोस्ट- डौंडी, तहसील- डोंडी, जिला- बालोद (छ.ग.) - 491228. **4. मेसर्स मोतीलाल मोहनलाल जैन (सह-आवेदक)**, बाजार रोड, डौंडी, पोस्ट डौंडी, तहसील डोंडी, जिला- बालोद (छ.ग.) - 491228. **5. अंकित जैन पुत्र उत्तम चंद जैन (सह-आवेदक), 6. कोमल चंद जैन पुत्र केवल चंद जैन (सह-आवेदक), दोनों का पताः** हनुमान मंदिर के पास, दुर्गा चौक, बाजार रोड, चन्द्रशेखर वार्ड नं. 12, गांव व पोस्ट- डौंडी, तहसील डौंडी, जिला- बालोद (छ.ग.) - 491228।	₹ 49,00,000.00	11/06/2026 ₹ 41,28,617.00 as on 11/06/2026 उस पर ब्याज सहित एनपीए तिथिः 03/06/2026	खसरा नं. 1043 का भाग, मौजा- ग्राम डौंडी, नगर पंचायत, प.ह.नं.- 24, रा.नि.मं.- डौंडी, ब्लॉक- डौंडी, तहसील- डौंडी (पहले बालोद), जिला- बालोद (छ.ग.) क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट में स्थित प्लॉट नं. 143 का भाग वाली अचल संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश। **चौहद्दीः उत्तर-** श्यामकरण का मकान, **दक्षिण-** पुखराज का मकान, **पूर्व-** गली, **पश्चिम-** गली।

दिनांकः 22.06.2026, स्थानः रायपुर (छ.ग.)
प्राधिकृत अधिकारी/ चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कं.लिमि.

क्या जातियों से तय होगी नागरिकता?

■ संपादकीय

बिहार के भोजपुर जिले की हालिया घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे यहां किसी भी बड़ी घटना का मूल्यांकन तथ्यों और कानून के आधार पर होता है, या फिर उसकी दिशा जातीय पहचान तय करती है? भरत तिवारी को उनके समर्थक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं और फेसबुक लाइव के जरिए आत्मसमर्पण की बात करते हैं। उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो जाती है। पुलिस एनकाउंटर बताती है। आम जनता इसको हत्या मानती है। घटना की निष्पक्ष जांच अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया, राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने इसे जातीय चश्मे से देखना शुरू कर दिया। बहस इस बात पर कम हुई कि मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थीं, इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि मृतक किस जाति का था? भारतीय राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल हो, जाति के एंगल से जरूर सोचा जाता है। जातियों में जैसी एकता बढ़ रही है राजनीतिक दल उसे वोट की तरह देखने लग जाते हैं। इस घटना इस बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है कि न्याय, संवेदना और समर्थन भी जाति के आधार पर तय होने लगे हैं।

जब भी भारत में कोई बड़ी घटना होती है, किसी की हत्या, पुलिस एनकाउंटर, बलात्कार, दंगा, आरक्षण का प्रश्न या चुनाव, सबसे पहले जो सवाल उठता है, वह यह नहीं होता कि सच क्या है, बल्कि यह होता है कि वह किस जाति का था? लोग किसी भी निर्णय पर जाति के आधार पर पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं यदि मृतक हमारी जाति का है तो वह शहीद है। यदि आरोपी हमारी जाति का है तो उसके बचाव में तर्क खोजे जाने लगते हैं। यदि पीड़ित दूसरी जाति का है तो संवेदनाएं भी जाति के चश्मे से छनकर बाहर आती हैं। आजादी के बाद से भारतीय राजनीति और समाज इसी जाति के आधार से बनता और आगे बढ़ता रहा है। यह केवल राजनीति की विफलता नहीं, बल्कि समाज की गहरी मानसिक बीमारी का संकेत है। भारतीय संविधान ने नागरिक बनाए, लेकिन समाज आज भी जातियों में बंटा हुआ है। हजारों वर्षों पुरानी वर्ण व्यवस्था से इतर जाति व्यवस्था का प्रभाव आज भी हमारे सामाजिक व्यवहार, रिश्तों, विवाह, गांवों की बसाहट और यहां तक कि राजनीतिक सोच पर दिखाई देता है। दुखद यह है कि लोकतंत्र ने इस विभाजन को समाप्त करने के बजाय कई बार उसे और मजबूत किया है।

हर राजनीतिक दल समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की बात करता है। कोई गांधी का नाम लेता है, कोई डॉ. भीमराव अंबेडकर का, कोई भगत सिंह का, कोई दीनदयाल उपाध्याय का, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो कोई कार्ल मार्क्स और लेनिन का। लेकिन जब चुनाव में उम्मीदवार चुनने की बारी आती है, तब सबसे पहले जिस बात पर नजर जाती है, वह उसकी योग्यता नहीं बल्कि उसकी जाति होती है। सवाल यह है कि यदि राजनीति स्वयं जाति से ऊपर नहीं उठ पा रही, तो समाज से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह जातिवाद छोड़ देगा?

सत्तर के दशक का जेपी आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं था। वह सामाजिक परिवर्तन का भी सपना था। अनेक युवाओं ने अपने नाम से जातिसूचक उपनाम हटा दिए। यह संदेश था कि पहचान व्यक्ति के विचारों और कर्मों से बनेगी, जाति से नहीं। लेकिन समय बीता, मंडल राजनीति आई और सामाजिक न्याय के नाम पर एक नई राजनीतिक धुरी खड़ी हुई। इससे पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला, जो लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसके साथ ही जाति राजनीतिक शक्ति का सबसे प्रभावी हथियार भी बन गई। बिहार और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। वहां कोई भी बड़ी घटना कुछ ही घंटों में जाति की बहस में बदल जाती है। कानून, न्याय और अपराध की चर्चा पीछे छूट जाती है, जबकि जाति बहस का केंद्र बन जाती है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने राजनीतिक गणित के अनुसार पक्ष और विपक्ष तय करते हैं। ऐसा लगता है मानो न्याय का पैमाना संविधान नहीं, बल्कि जाति समीकरण हो।

यह प्रवृत्ति केवल बिहार या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जाति एवं सामुदायिक आधार पर बनते-बिगड़ते हैं। कहीं आदिवासी और गैर-आदिवासी की खाई है, कहीं धर्मांतरण को लेकर तनाव है, तो कहीं आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई। पहचान की राजनीति हर राज्य में अलग रूप धारण कर लेती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप एक ही है, समाज को अलग-अलग हिस्सों में बांटना।

यह भी सच है कि सदियों तक वंचित रहे समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, उनकी आवाज सत्ता तक पहुंची और लोकतंत्र अधिक समावेशी बना। इसे नकारना इतिहास के साथ अन्याय होगा। लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि यदि हर घटना को केवल जाति के चश्मे से देखा जाएगा तो कानून का शासन कमजोर होगा और समाज में स्थायी अविश्वास पैदा होगा।

कबीर ने सदियों पहले कहा था– 'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।' दुर्भाग्य यह है कि आज हम ज्ञान नहीं, जाति पूछते हैं। योग्यता नहीं, बिरादरी देखते हैं। विचार नहीं, वोट बैंक तलाशते हैं। यही कारण है कि चुनावी सभाओं से लेकर सोशल मीडिया तक हर बहस का निष्कर्ष अंततः जाति पर आकर रुक जाता है। चुनाव में लोकतंत्र का प्रतिनिधि चुना जाता है लेकिन बाद में देखा जाता है कि वह तो जाति के प्रतिनिधि में बदल गया है। यदि हर हत्या जाति की हत्या बन जाएगी, हर अपराध जाति के सम्मान का प्रश्न बन जाएगा और हर चुनाव जाति जनगणना का गणित बन जाएगा, तो संविधान की आत्मा कमजोर हो जाएगी।

भारत की राजनीति, समाज और प्रशासन को यह स्वीकार करना होगा कि सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति एक ही बात नहीं हैं। सामाजिक न्याय सभी को समान अवसर की बात करता है, जबकि जाति की राजनीति व्यक्ति और समाज को संकीर्ण बनाने की का षड्यंत्र है। एक समाज को जोड़ती है, दूसरी उसे वोट बैंक में बदल देती है। आज सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि किस जाति का वर्चस्व है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आने वाली पीढ़ी भी इसी जाति बोझ के साथ जीने को अभिशप्त रहेगी, जिसे खत्म करने का सपना कबीर ने देखा था, जिसे जेपी ने जगाया था और जिसे संविधान ने समान नागरिकता के रूप में स्थापित किया था। जिस दिन किसी घटना पर हमारा पहला प्रश्न यह होगा कि 'सच क्या है, कानून क्या कहता है और न्याय किसमें है?' यह लोकतंत्र की सफलता होगी। यदि यह पूछा जाता है कि 'वह किस जाति का था?' तो भारतीय समाज का दुर्भाग्य बना रहेगा।

भारत को मिला वैश्विक वित्तीय सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व

महेन्द्र तिवारी

भारत ने वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पहली बार किसी भारतीय अधिकारी को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में वह भारत सरकार के संस्कृति सचिव हैं। पेरिस में आयोजित संस्था की पूर्ण बैठक में सदस्य देशों ने उन्हें इस पद के लिए चुना। यह केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय शासन व्यवस्था में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रमाण भी है।

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत 2010 से इस संस्था का सदस्य है, लेकिन पिछले 16 वर्षों में किसी भारतीय को इसके शीर्ष नेतृत्व में स्थान नहीं मिला था। अब पहली बार भारत संस्था के सर्वोच्च नेतृत्व ढांचे का हिस्सा बनेगा और उसकी नीतियों तथा प्राथमिकताओं को आकार देने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाएगा। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, वित्तीय संस्थागत क्षमता और वैश्विक विश्वसनीयता का संकेत माना जा रहा है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल विश्व स्तर पर धनशोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से जुड़े वित्तीय नेटवर्कों के खिलाफ मानक निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग अपराधी, आतंकवादी संगठन और अवैध नेटवर्क न कर सकें। यह संस्था सदस्य देशों की नीतियों और कानूनों का मूल्यांकन करती है तथा आवश्यक सुधारों की सिफारिश करती है। इसके निर्णयों का प्रभाव वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था, विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और

आर्थिक विश्वसनीयता पर पड़ता है।

विवेक अग्रवाल की नियुक्ति उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और वित्तीय अपराधों से निपटने में उनकी विशेषज्ञता का परिणाम मानी जा रही है। वह पहले इस संस्था में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक भी रह चुके हैं। वित्तीय खुफिया इकाई का कार्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी करना, धनशोधन से जुड़े मामलों की पहचान करना और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। इस अनुभव ने उन्हें वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के जटिल मुद्दों को समझने और समाधान विकसित करने की क्षमता प्रदान की।

भारत के लिए यह उपलब्धि केवल प्रतिष्ठा का विषय नहीं है बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखती है। पिछले एक दशक में भारत ने धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ अपने कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच एजेंसियों ने अनेक मामलों का खुलासा किया है। वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए तकनीकी प्रणालियों को सशक्त बनाया गया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार के साथ सुरक्षा मानकों को भी लगातार बेहतर किया गया है। इन प्रयासों के कारण भारत को वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और सक्षम साझेदार के रूप में देखा जाने लगा है।

वर्ष 2024 में भारत के मूल्यांकन के दौरान संस्था ने भारत के धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी ढांचे की सराहना की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने प्रभावी परिणाम प्राप्त करने वाला ढांचा विकसित किया है। यही कारण है कि आज भारत को केवल एक सदस्य देश के रूप में नहीं बल्कि नीति निर्माण में योगदान देने वाले नेतृत्वकारी देश के रूप में देखा जा रहा है।

उपाध्यक्ष का पद संस्था की कार्यप्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के साथ मिलकर संस्था के एजेंडा, बैठकों, प्राथमिकताओं और वैश्विक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। सदस्य देशों के बीच सहमति निर्माण, नई चुनौतियों पर नीति निर्धारण और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवेक अग्रवाल इस जिम्मेदारी के साथ उन विषयों पर भी काम करेंगे जो तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई वित्तीय तकनीकों से जुड़े हैं।

आज दुनिया के सामने केवल पारंपरिक धनशोधन की चुनौती नहीं है। आभासी परिसंपत्तियां, सीमा पार डिजिटल लेनदेन, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और आतंकवादी नेटवर्कों की बदलती रणनीतियां नई चिंताएं पैदा कर रही हैं। भारत ने एक ओर डिजिटल भुगतान को व्यापक बनाया है तो दूसरी ओर सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। यही अनुभव अब वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण में उपयोगी साबित हो सकता है।

भारत की एक और विशेषता यह है कि उसने वित्तीय समावेशन और वित्तीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। जनधन खातों, आधार आधारित पहचान प्रणाली और डिजिटल भुगतान तंत्र ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा है। साथ ही वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। यह मॉडल अनेक विकासशील देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। भारत की बढ़ती भूमिका इस अनुभव को वैश्विक मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करेगी।

यह नियुक्ति भारत की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज आर्थिक कूटनीति और वित्तीय सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। किसी देश की विश्वसनीयता केवल उसकी सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि उसकी वित्तीय प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता से भी आंकी जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कठोर वैश्विक कार्रवाई की वकालत करता रहा है। ऐसे में इस संस्था के शीर्ष नेतृत्व में भारत की उपस्थिति उसकी आवाज को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी।

अक्सर यह चर्चा होती है कि इस संस्था की निगरानी सूची में शामिल होने का किसी देश पर कितना प्रभाव पड़ता है। जिन देशों को बढ़ी हुई निगरानी के दायरे में रखा जाता है, उन्हें विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय ऋण और वैश्विक वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया के अधिकांश देश संस्था के मानकों को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि इसके नेतृत्व में स्थान प्राप्त करना किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

विवेक अग्रवाल की नियुक्ति को भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत की सफलता करार दिया और कहा कि यह वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्कों के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह नियुक्ति इस बात का भी संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की संस्थागत क्षमता और उसके अनुभव पर भरोसा करता है।

स्वयं विवेक अग्रवाल ने भी इस नियुक्ति को भारत के सामूहिक प्रयासों की मान्यता बताया है। उनके अनुसार यह भारत के धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी ढांचे की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित, समावेशी और लचीला बनाने के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

व्यंग्य

गर्व से कहो हम पति हैं

सूर्यबाला

महिलाओं को मालूम है कि जिस तरह हर सफल पुरुष के पीछे कोई महिला होती है उसी तरह हर असफल महिला के पीछे भी कोई-न-कोई पुरुष होता है। आप भी माने या न मानें, स्त्री – स्वातंत्र्य या महिला-मुक्ति का आंदोलन भी, जो माकूल स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, उसके पीछे भी यही कारण है। इसे यों समझिए कि अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से, बेहिसाब तादात में महिलाएँ, सामाजिक-राजनीतिक विकास की गाड़ी पकड़ने को चुस्त-दुरुस्त तैयार है। इंजन ने सीटी भी मार दी। महिलाएँ हचककर फुटबोर्ड पर लटक भी लीं, लेकिन, चक्का जाम! भई, यह तो वही बात हुई कि इंडियन एअरलाइंस के आसमान से टूटे तो भारतीय रेलवे के खजूर में अटके। गाड़ी थी कि न टस, न मस।

पड़ताल हुई तो पता चला कि पिछले पहियों के नट-बोल्ट इतने खस्ताहाल हैं कि ये अगलों को खिसकने ही नहीं दे रहे।

यहाँ हम इन पाठकों का परिचय इन पिछले पहियों से करा दें। ये पिछले पहिए, पुरुष हैं। पाठकों को यह भी ज्ञात होगा कि स्त्री और पुरुष को हमने समाज और परिवार की गाड़ी के दो पहिए माना है। अब एक पहिए धुआँधार चालू हो और दूसरा पूरी तरह पंचर, तो कैसे चलेगा भई!

बस इसलिए हम जागरूक और प्रबुद्ध महिलाओं ने सोचा, चलो, पहले अपनी भारतीय रेलगाड़ी के इन जाम चक्कों की मरम्मती और दुरुस्ती पर ध्यान दिया जाए। इनके बिगड़ैल पूर्वाग्रह के स्पीड-ब्रेकर सपाट किए जाएँ, तभी अपनी गाड़ी सरपट दौड़ेगी। वरना यह क्या कि हम तो प्रगति और विकास की नसेनी पर सोत्साह फेंटा कसकर चढ़ने को तैयार, लेकिन यह मुआ (सॉरी पुरुष) अभी बेड टी के इंतजार में सोया पड़ा है। इसका क्या ठिकाना, नींद के झोंके में एक पाँव फटकारेगा तो हमारी लगाई सीढ़ी, धड़ाम से चारों खाने नीचे चित्त वही, हर असफल महिला के पीछे एक पुरुष।

इसलिए कई महिला संगठनों ने अनेक शिखर-वार्ताओं के बाद यह निर्णय लिया कि नहीं, हमें काउंटर-पार्ट, बेचारे पुरुष को यूँ ही सोता नहीं छोड़ना है। अर्थात उसे जगा कर ही छोड़ना है, क्योंकि – 'उठ जाग मुसाफिर देर भाई... तुझे नहीं, मुझे तो ऑफिस जाना है...।

सो, हे पति! हे पुरुष! इनमें से एक या दोनों, उठ! और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमारी दूरदर्शिता और उदारता का लोहा मान... जो हमने 'अपनी' दशा सुधारने का काम बीचों-बीच छोड़कर, तुझे उठाने और तेरी धूल-धक्कड़ झाड़ने का टास्क हाथ में ले लिया है।

यह काम उतना आसान नहीं। इसके लिए हमें पूरी तरह समर्पित और एकजुट होकर काम करना होगा। क्योंकि महिलाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि आज का पुरुष अनेक प्रकार की हीनता-बोधों से ग्रस्त है। अनेक अहं, अनेक वहम, अकर्मण्यता तथा आलस्य इसके मूल कारण हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी वर्तमान, गिरी हुई दशा पर तरस खाएँ तथा उन्हें उनकी संकीर्ण विचारों की चारदीवारी से बाहर लाने की हर चंद कोशिश करें।

इसके लिए सबसे पहले तो रैलियाँ निकाली जाएँ और उनकी तख्तियों पर उत्साहवर्धक वाक्य लिखवाएँ जाएँ। जैसे – 'पति एक सम्मानजनक ओहदा है' ...या फिर 'पतित्व हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है...' अथवा 'गर्व से कहो, हम पति हैं...' आदि इत्यादि। सर्वे से प्राप्त सूचना के अनुसार, 'पत्नी' और 'परिवार' के नाम से नर्वस होनेवाले पतियों की संख्या में भी इधर बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ पति तो इसी भय के कारण ड्यूटी आवर्स के बाद भी ताश-पपलू आदि के बहाने मारकर, ऑफिस में ही पड़े रहते हैं। ऐसे पतियों को समझना चाहिए कि यह पलायनवाद अर्थात भगोड़ापन है। यही कारण है कि उनका पुरुष समाज अर्थात पूरा का पूरा पुरुष समाज, पलायन करते-करते आज इस दीन-हीन दशा को पहुँच गया है। हमारे देश की दुर्गति का प्रमुख कारण भी यही है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब पुरुष वर्ग पलायन करता रहा, तब-तब देश रसातल को जाता रहा, यानी हमेशा ही...।

फिलहाल देश और रसातलवाले मुद्दे को छोड़कर हम अपने मेनिफेस्टों पर आते हैं जिसके अनुसार इन सामूहिक तथा एकजुट अभियानों के अतिरिक्त, पारिवारिक स्तर पर भी, हर पत्नी का फर्ज बनता है कि वह कम से कम एक अदद पुरुष अर्थात पति को स्वावलंबी बनाने में प्राण पर से जुट जाए! मिसाल के तौर पर अदि वह किसी जरूरी काम में फँसी है तो निठल्ले पति द्वारा डपटकर पानी माँगे जाने पर हरगिज न उठे। उसे स्वयं उठकर पानी लेने की आदत डलवाएँ। साथ ही उसे स्वयं पानी शर्ट में बटन टाँगने तथा पाजामे में नाड़ा डालने के लिए प्रेरित करें।

पत्नी को स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे मौकों पर पति पहले झल्लाएगा, डपटेगा तथा पत्नी को पागलखाने में भर्ती करने की धमकी भी देगा। किंतु पत्नी को अपनी फर्ज अदायगी से डिगना नहीं चाहिए। उसे फौरन समझ लेना है कि यह पुरुष नहीं, उसकी हीन भावना बोल रही है।

कविता संसार

बदली हुई तहज़ीब

चन्द्रकांत खुंटे 'क्रांति'

सोचता हूँ...
कितने सीधे और मासूम थे वो लोग
जो अपनी मोहब्बत, अपनी यादें
किताबों के पन्नों के बीच
एक गुलाब की शक्ल में महफ़ूज़ रखते थे।
वो कागज़ की खुशबू और पंखुड़ियों का सूखना
एक पूरा दौर था सादगी का।
और आज का यह आधुनिक दौर देखिए...
जहाँ लोग किताबें तो नहीं खोलते
पर जब भी मुँह खोलते हैं
तो लफ़्ज़ों की जगह ज़हर उगलते हैं।
तरक्की के इस नए ज़माने में
दिलों की जगह नफ़रत ने ले ली है।
अब किसी के पास वक़्त नहीं
कि वो किसी को याद करे
पर हर किसी के पास पूरा वक़्त है
कि वो अपनी तीखी जुबान से
दूसरों के वजूद को छलनी कर दे।
अजीब विडंबना है–
वो गुलाब रखने वाले कल के लोग पिछड़े कहलाए,
और जुबान पर ज़हर रखने वाले
आज के लोग 'बेहद स्मार्ट' और कामयाब बन बैठे।।

यूपी में तन-मन भिगोने जल्द आ रहा है मानसून

-संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में गर्मी से परेशान लोगों के लिये जल्द अच्छी खबर आने वाली है। यूपी में मानसून 27 से 30 जून तक पूर्वी-पश्चिमी क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है, जो 5 जुलाई तक पूरे राज्य में पूरी तरह छा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, जून के तीसरे सप्ताह से मानसूनी गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी और महीने के अंत तक अधिकांश जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले वर्षों के ट्रेंड और आईएमडी की भविष्यवाणी के आधार पर, इस बार भी मानसून 27 से 30 जून के बीच राज्य में पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ विचलन के कारण पूर्वी यूपी में पहले और पश्चिमी यूपी में थोड़े बाद में आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश आमतौर पर दो चरणों में होता है। पूर्वी हिस्सों में मानसून 15 से 20 जून के बीच दस्तक देता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में 25 से 27 जून के बीच फैल जाता है। मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून 27-30 जून तक आने की संभावना है। इस तरह पूर्वी यूपी में मानसून पहले प्रवेश करेगा और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में छाएगा। 5 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह छा जाएगा। वर्तमान में (22 जून 2026) देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री-मानसून एक्टिविटी है और 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो जून से सितंबर तक केन्द्रित होती है। राज्य की कुल वर्षा में पहाड़ी क्षेत्रों में वार्षिक औसत 170 सेमी तक हो सकता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में 84 सेमी तक रहता है। इस बार भी उम्मीद है कि मानसून जमकर बरसेगा, लेकिन मौसम के तेवरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बारिश सावधानी भी मांगती है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है, लेकिन तेज बारिश से थोड़ा-बहुत भी हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता 25 फीसदी से कम, जबकि शेष उत्तर प्रदेश में 25 से 50 फीसदी के बीच रहती है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में वर्षा कहीं कम तो कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। राज्य के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण पैटर्न है, क्योंकि बुंदेलखंड पिछले वर्षों से वर्षा की कमी से परेशान है और इस क्षेत्र में कृषि पर सीधा प्रभाव होता है। पूर्वी यूपी में वर्षा अधिक होने के कारण खेती बेहतर होगी, लेकिन पश्चिमी यूपी में भी पर्याप्त वर्षा की उम्मीद है। मध्य यूपी में वर्षा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच के स्तर पर रहने की संभावना है।

सुरक्षा की जीत, गरिमा की हार? नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का दोहरा चेहरा

-प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

21 जून 2026 को नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा समाप्त हुई। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते लाखों विद्यार्थियों के चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा बोझ भी झलक रहा था। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में आयोजित किया गया। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों, 95 हजार परीक्षा कक्षों, 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरों, 51 हजार जैमरों, हजारों बायोमेट्रिक कर्मचारियों और कड़ी फ्रिस्किंग के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पेपर लीक की आशंकाएं लगभग समाप्त रहीं और परिणामों पर विश्वास बहाल होने की उम्मीद जगी। इसके लिए एनटीए और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस सफलता के बीच एक सवाल खड़ा है–क्या निष्पक्षता की यह कीमत हमारी युवा पीढ़ी की गरिमा और मानसिक शांति से वसूली जानी चाहिए?

पिछले वर्षों में बार-बार हुए पेपर लीक कांडों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई थी। मई 2026 की घटना के बाद सरकार और एनटीए ने पूरे तंत्र को लगभग रीसेट कर दिया। प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर उनके परिवहन तक अभूतपूर्व गोपनीयता बरती गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्थानों पर भारतीय वायुसेना की सहायता से प्रश्न-पत्र पहुंचाए गए, जीपीएस ट्रैकिंग, पुलिस एस्कॉर्ट और एआई आधारित निगरानी तंत्र सक्रिय किए गए। राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग हुई। हजारों पर्यवेक्षक, साइबर निगरानी दल और खुफिया एजेंसियों का त्रिस्तरीय सुरक्षा नेटवर्क परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर रखे रहा। यह व्यवस्था किसी शैक्षणिक आयोजन से अधिक एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान जैसी प्रतीत होती थी।

इन उपायों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। लाखों विद्यार्थियों को भरोसा मिला कि इस बार उनकी मेहनत संगठित नकल या पेपर लीक के कारण व्यर्थ नहीं जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े माता-पिता को भी संतोष था कि उनके बच्चों का भविष्य किसी अपराधी गिरोह या भ्रष्ट नेटवर्क के हाथों बंधक नहीं बनेगा। लंबे समय से अपेक्षित विश्वास बहाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। निष्पक्षता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है और उसे बचाने के लिए कठोर कदमों का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है। किंतु हर सफलता कुछ ऐसे प्रश्न भी छोड़ जाती है जिन्हें केवल आंकड़ों और प्रशंसाओं से ढंका नहीं जा सकता।

सबसे बड़ा प्रश्न उस अनुभव का है जिससे विद्यार्थी गुजरे। आधार आधारित फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट सत्यापन, जेबों, कानों, जूतों और यहां तक कि कपड़ों की चेन, जिप तथा धागों तक की जांच–यह सब उस युवा पीढ़ी के साथ हुआ जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी। 38,795 फ्रिस्किंग कर्मी और 48,448 बायोमेट्रिक कर्मचारी व्यवस्था की आवश्यकता रहे होंगे, लेकिन विद्यार्थियों के मन में यह अनुभव भी दर्ज हुआ कि उन पर पहले संदेह किया गया, बाद में विश्वास। कई अभ्यर्थियों ने स्वयं को अपराधियों की तरह टटोला जाता महसूस किया। यह भावना किसी परीक्षा की सफलता का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।

इस पूरी प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर छात्राओं के लिए फ्रिस्किंग कई बार असहजता और तनाव का कारण बनी। यद्यपि महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, फिर भी मानसिक दबाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। माता-पिता दूर खड़े अपने बच्चों को डिजिटल और भौतिक निगरानी के घेरे में प्रवेश करते देखते रहे। शिक्षा का मंदिर कई स्थानों पर सुरक्षा चौकी जैसा दिखाई देने लगा। यह दृश्य केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस सामाजिक अविश्वास का भी प्रतीक है जो धीरे-धीरे संस्थाओं और नागरिकों के बीच बढ़ता जा रहा है। जब एक छात्र परीक्षा देने से पहले स्वयं को संदिग्ध साबित होने से बचाने की प्रक्रिया से गुजरता है, तब कहीं न कहीं शिक्षा का मूल उद्देश्य भी आहत होता है। दरअसल समस्या का मूल कारण विद्यार्थी नहीं हैं। समस्या उस व्यवस्था में है जिसने वर्षों तक पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों को पनपने दिया। यदि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत होती, तो शायद इतनी कठोर सुरक्षा की आवश्यकता न पड़ती। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली की ओर संक्रमण, उन्नत डिजिटल सुरक्षा उपाय तथा एनटीए में संरचनात्मक सुधार लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस बार की सफलता सिद्ध करती है कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन यदि सुधार केवल सुरक्षा तक सीमित रहेगा और मूल समस्याएं जस की तस रहेंगी, तो हर वर्ष विद्यार्थियों को इसी प्रकार की कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देश को अब तय करना होगा कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली कैसी हो। क्या हम हर वर्ष युद्ध जैसी तैयारियां करेंगे, या ऐसे तकनीकी और संस्थागत सुधार विकसित करेंगे जिनसे सुरक्षा और सम्मान दोनों साथ चल सकें? फ्रिस्किंग को अधिक संवेदनशील और कम अपमानजनक बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया को चरणबद्ध, डिजिटल और लीक-प्रूफ बनाया जा सकता है। सुरक्षा का उद्देश्य भय नहीं, विश्वास पैदा करना होना चाहिए। यदि कोई व्यवस्था निष्पक्ष तो हो जाए, पर उसमें मानवीय गरिमा खो जाए, तो वह अधूरी सफलता ही कहलाएगी।

नीट-2026 की पुनर्परीक्षा भारत की परीक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस बार परीक्षा सफल रही, विवादों से अपेक्षाकृत मुक्त रही और लाखों छात्रों के परिश्रम को न्याय मिलने की संभावना मजबूत हुई। यह उपलब्धि छोटी नहीं है। फिर भी यह घटना चेतावनी देती है कि केवल सुरक्षा बढ़ाना समाधान नहीं है। मां-बाप के सपनों से जुड़ी यह व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या हम अपने युवाओं को पंख देकर उड़ाना चाहते हैं या उन्हें बायोमेट्रिक सलाखों के बीच भविष्य तलाशने के लिए छोड़ देना चाहते हैं?

दगड़ी की सरपट दौड़, पहुंचा 4700 पर...!

● पोहा मुरमुरा में भी जोरदार तेजी

भाटापारा। नीचे में 3900 रुपए। ऊपर में 4500 रुपए क्विंटल। पोहा में बोली जा रही यह कीमत और भी आगे जाने की धारणा इसलिए बन रही है क्योंकि पोहा क्वालिटी के धान की कीमत और अंतरप्रांतीय मांग पोहा में लगातार बढ़त की राह पर है। प्रतिस्पर्धी खरीदी पोहा क्वालिटी के महामाया धान में और तैयार पोहा में अंतरप्रांतीय उपभोक्ता मांग ने धान और पोहा की कीमतें बढ़ाई हुई हैं। तेजी की धारणा को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि बारिश के दिनों के लिए पोहा उत्पादक इकाइयां भंडारण पर भी गंभीर हैं।

महामाया और पोहा

खरीफ की तैयारी के बीच पोहा क्वालिटी के धान की आवक कृषि उपज मंडियों में बनी हुई है लेकिन बारिश के दिनों के लिए इकाइयों की खरीदी धान में जिस गति से निकली हुई है, उसके बाद महामाया धान में प्रति क्विंटल भाव 2200 से 2400 रुपए बोले जा रहे हैं। असर उस पोहा में देखा जा रहा है, जो न्यूनतम 3900 रुपए और उच्चतम 4500 रुपए क्विंटल पर पहुंचा हुआ है। बढ़ सकती है यह कीमत क्योंकि उपभोक्ता राज्यों की खरीदी पोहा में निकल चुकी है।

दगड़ी में तूफानी तेजी

पशु आहार उत्पादक इकाइयों और विक्रेता संस्थानों में डेयरियों तथा पशुपालकों की जोरदार डिमांड ने दस्तक दे दी है। फलस्वरुप दगड़ी ने 4200 से 4700 रुपए क्विंटल जैसी उच्च कीमत अपने नाम कर ली है। तेजी की धारणा दगड़ी में भी बनी हुई है क्योंकि अब इसमें भी अंतरप्रांतीय मांग अब पोहा उत्पादक इकाइयों तक पहुंचने लगी है। घरेलू पशुपालकों की खरीदी अपने स्तर पर अलग से बनी हुई है।

सफरी और मुरमुरा

सिमट रहा है रकबा सफरी धान की खेती का। बढ़ रही है कीमत क्योंकि मुरमुरा बनाने वाली ईकाइयों की मांग बदस्तूर जारी है। ऐसे में सीमित मात्रा में आ रहा सफरी धान 2200 से 2300 रुपए क्विंटल पर पहुंचा हुआ है। फलस्वरूप मुरमुरा सफेद 5800 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। कीमत बढ़ने का अंदेशा इसलिए है क्योंकि मांग की तुलना में सफरी धान की आपूर्ति बेहद कमजोर है।

बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड में बड़ा खुलासा

50 लाख के जेवर और 3 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट से संगठित तरीके से स्क्रैप चोरी कर करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार करने वाले गिरोह के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड के बाद सोमवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों की अवैध कमाई से अर्जित करोड़ों रुपये की संपत्ति और महंगे आभूषणों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी संजय सिंह के लॉकर से करीब 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण तथा लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों से भी संपत्ति संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। पुलिस अब आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।

फ्लू डस्ट की आड़ में चल रहा था चोरी का खेल

मामले का खुलासा 26 मई 2026 को हुआ था, जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हथखोज स्थित ए.के. ट्रेडर्स में छापा मारा। जांच के दौरान हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ बीएसपी से चोरी किए गए लोहे की प्लेट, बीम और अन्य स्क्रैप सामग्री लोड पाई गई। मौके पर भारी मात्रा में स्क्रैप का भंडारण भी मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि फ्लू डस्ट परिवहन की आड़ में बीएसपी से चोरी किया गया लोहा बाहर निकालकर अवैध रूप से बेचा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 250 टन लोहे की प्लेट, बीम और अन्य स्क्रैप सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 90 लाख रुपये बताई गई। वहीं परिवहन और लोडिंग में उपयोग किए जा रहे वाहन एवं मशीनरी सहित कुल 3 करोड़ 22 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

उत्तर प्रदेश से दबोचा गया मुख्य आरोपी

प्रकरण में पहले ही नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। मुख्य फरार आरोपी संजय सिंह की तलाश में दुर्ग पुलिस की विशेष टीम उत्तर प्रदेश भेजी गई, जहां देवरिया क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया गया। 16 जून को गिरफ्तारी के बाद उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ के दौरान संजय सिंह ने गिरोह से जुड़े अमित शर्मा उर्फ कैलाश शर्मा और आकाश कुमार सिंह की भूमिका उजागर की, जिसके बाद दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि चोरी किए गए लोहे की बिक्री से प्राप्त रकम को संपत्तियों और आभूषणों में निवेश किया गया था।

फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल

पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल ले जाकर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के स्क्रैप के परिवहन में उपयोग किए गए वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई जाती थीं। पुलिस ने ऐसी कई नंबर प्लेट भी जब्त की हैं।

अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस के अनुसार इस बहुचर्चित स्क्रैप चोरी प्रकरण में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की विवेचना जारी है और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों के संबंध में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर गिरोह की आर्थिक गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़े अन्य अहम तथ्य भी सामने आ सकते हैं।

समय सीमा की बैठक संपन्न

कलेक्टर ने की पल्स पोलियो अभियान के तैयारियों की समीक्षा

● 24 जून को आयोजित ग्राम सभाओं में सभी विभागों के महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल करने के दिए निर्देश

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान 2026 तथा 24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि जिले में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान 28 जून 2026 को आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 28 जून को बूथ स्तर पर तथा 29 एवं 30 जून को घर-घर पहुंचकर शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत जिले के लगभग एक लाख चार हजार छः सौ सत्ताईस (1,04,627) बच्चों को खुराक देने हेतु 744 पोलियो बूथों पर 900 टीमें एवं 2430 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। निर्धारित बूथों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, हाट बाजार एवं बस स्टैंड जैसे स्थानों पर भी ''दो बूंद जिंदगी'' की खुराक पिलाई जाएगी। कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित प्रत्येक बच्चे तक खुराक पहुंचाना सुनिश्चित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने 24 जून 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में आयोजित होने वाली ग्राम सभा को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागों को अपने-अपने महत्वपूर्ण एजेंडा ग्राम सभा में शामिल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा जनभागीदारी का सशक्त माध्यम है, अतः इसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों को केंद्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं से शत-प्रतिशत संतृप्त किया जाए।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) का अवलोकन एवं वाचन कर मार्गदर्शिका व एसओपी के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार करते हुए दावा-आपत्ति प्राप्त की जाए। साथ ही 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में लागू हो रहे विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन, पूर्व बैठक के पारित संकल्पों के पालन प्रतिवेदन, त्रैमासिक आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन तथा विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति का वाचन कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर ने समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से कर अधिरोपण एवं संग्रहण की ऑनलाइन व्यवस्था, पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 परिणामों के प्रदर्शन, अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा, मुक्तिधाम में साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं, जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीयन तथा ग्राम संपदा ऐप में स्थायी संपत्तियों के पंजीयन की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सड़कों पर आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने तथा पशुओं को खुले में न छोड़ने का संकल्प पारित कराने पर भी बल दिया।

बाड़ी में घुसे तेंदुए की स्थिति गंभीर, करंट लगने की आशंका, हुआ सफल रेस्क्यू

● वन क्षेत्र में शिकारियों की होते रहती है आमद करेंट लगाकर किया जाता है शिकार

बलौदा बाजार। सोनाखान के ग्राम महकम में आज एक तेंदुआ बाड़ी में घुस आया था। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। जिसे देखते हुए वन विभाग ने बिलासपुर से रेस्क्यू टीम बुलाकर तेंदुए का टेक्युलाईजर कर सफल रेस्क्यू किया। फिलहाल तेंदुए की स्थिति चिंताजनक है और उसे ईलाज के लिए जंगल सफारी भेजा जा रहा है। पशु चिकित्सक डाक्टर चंदन ने बताया कि तेंदुए की हालत चिंताजनक है यहां भीड़ है इसलिए ईलाज नहीं कर पायेंगे। उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर परीक्षण उपरांत बताया जा सकेगा उसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई है।

बहरहाल कयास यह लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में शिकारियों की आमद लगातार होते रहती है और अक्सर करेंट लगाकर इनका शिकार किया जाता है। इसके पूर्व भी जंगल में मृत तेंदुआ पाया गया है जिसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि इस तेंदुए को भी करंट का झटका लगा होगा और वह घायल होकर गांव में आ गया। जिस तरह उसकी चाल में सुस्ती दिख रही थी कहा जा सकता है झटका जोर से लगा था। फिलहाल वास्तविक कारण परीक्षण और ईलाज उपरांत पता चलेगा। इस पूरे आपरेशन में एसडीओ वनविभाग अनिल वर्मा, सहित वनविभाग, रेस्क्यू टीम तथा ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा।

एसडीओ वनविभाग अनिल वर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि सुनील साहू की बाड़ी में तेंदुआ घुस आया है जिसके बाद हमारी टीम लगातार नजर रखे थी। बिलासपुर से रेस्क्यू टीम बुलाया गया था जो आकर तेंदुआ का सफल रेस्क्यू किया है और अभी परीक्षण किया जा रहा है वह काफी सुस्त नजर आ रहा है। तेंदुआ का परीक्षण डाक्टर करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या है।

सेल ने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एमडीआई गुड़गांव के साथ एमओयू किया

भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ यह समझौता, सेल में भविष्य की कमान संभालने वाले लीडर्स को तैयार करने के उद्देश्य से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स पर मिलकर काम करने के लिए किया गया है।

यह साझेदारी अकादमिक ज्ञान को व्यावहारिक इस्तेमाल के साथ जोड़ेगी। इसके तहत कस्टमाइज्ड लीडरशिप प्रोग्राम्स, रणनीति और इनोवेशन पर आधारित लर्निंग इंटरवेंशन, मापने योग्य व्यावसायिक प्रभाव के लिए एक्शन लर्निंग, ओवरसीज लर्निंग प्रोग्राम, संयुक्त रिसर्च व कंसल्टिंग और कंपनी के अधिकारियों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए केस स्टडीज़ शामिल होंगे। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज के साथ तालमेल बिठाते हुए संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करना है।

इस समझौता ज्ञापन पर सेल के एमटीआई के कार्यपालक निदेशक संजय धर और एमडीआई, गुड़गांव की प्रोफेसर सुमिता राय ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सेल के निदेशक (कार्मिक) के. के. सिंह और सेल तथा एमडीआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

वर्षों बाद भाटापारा के रावणभाठा मैदान में लौटा बास्केटबॉल का रोमांच

शिवरतन शर्मा ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

भाटापारा। नगर के रावणभाठा मैदान में वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर बास्केटबॉल की धमक सुनाई दी। रविवार देर शाम नगर स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ शिवरतन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह रही कि इसमें केवल भाटापारा नगर के युवाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। वर्षों बाद हुए इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह था। युवाओं ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में दोनो टीमों के खिलाड़ियों

ने कोर्ट पर जबरदस्त जज्बे, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया। मैदान में खिलाड़ियों की फुर्ती, पासिंग और डंक ने साबित कर दिया कि भाटापारा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो ऐसे मंचों की।

शिवरतन शर्मा ने कहा - यह वापसी ऐतिहासिक है : शिवरतन शर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित कर कहा की वर्षों बाद रावणभाठा मैदान पर बास्केटबॉल का यह आयोजन लौटना अपने आप में ऐतिहासिक है। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट का समापन नहीं, बल्कि भाटापारा में खेल संस्कृति की वापसी है। शिवरतन शर्मा ने आगे कहा, बास्केटबॉल केवल खेल नहीं है, यह जीवन का पाठ पढ़ाता है। एक सेकंड में सही निर्णय लेना, गिरकर फिर से उठना और मैं को भूलकर हम बनकर टीम के लिए खेलना-यही सीख हमें आगे ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान का सपना ऐसे ही आयोजनों से पूरा होता है, जहां गली-मोहल्ले के युवा मैदान में पसीना बहाकर देश का नाम रोशन करने का हौसला रखते हैं।

विजेता - उपविजेता सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र : समारोह में शिवरतन शर्मा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस लगन से नगर के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, वह वाकई काबिले तारीफ है। हर खिलाड़ी चैंपियन है, जिसने मैदान पर उतरकर अपनी हिम्मत दिखाई।

Chola
Enter a better life

चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी-54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का, औद्योगिक संपदा, गुइंडी, चेन्नई- 600 032.
शाखा कार्यालयः शॉप नं. 7वीं, करेंसी टावर, वीआईपी चौक, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर, छ.ग. 492001,
सम्पर्क नं. प्रकाश वर्मा- 9981343191, प्रखर शर्मा- 9826432751, अरशद हुसैनी- 7389006995

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) **नियम, 2002 के नियम 9(1)** के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और पतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियां की बिक्री के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना । एतद्वारा आम जनता और विशेष रुप से ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी रखी गई है, जिसका **सांकेतिक कब्जा चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाईनेंस कंपनी लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी के द्वारा लिया गया है, जिसे इसके बाद चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाईनेंस कंपनी लिमिटेड के रुप में संदर्भित किया गया । प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर की जाएगी । इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://bankauctions.in.** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं ।

यह सूचित करना भी प्रासंगिक है कि कंपनी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, आज की तारीख तक जबलपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण (DRT) या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में उक्त नीलामी संपत्ति के संबंध में कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है। साथ ही, आज की तारीख तक इस नीलामी के संबंध में कोई भी ''अंतरिम/स्थायी रोक'' (Stay) लागू नहीं है

यह बताना भी जरूरी है कि संजय अवस्थी मामले में, सह-उधारकर्ताओं ने माननीय डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जबलपुर के सामने केस नंबर 1155/2024 एवं 941/2024 के तहत केस दायर किया है, जो अभी लंबित है। साथ ही, सह-उधारकर्ताओं ने माननीय जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के सामने एक उपभोक्ता शिकायत भी दायर की है । हालाँकि, इस नोटिस की तारीख तक इन मामलों में नीलामी की कार्यवाही पर कोई ''अंतरिम/स्थायी रोक'' नहीं है ।

खाता नंबर, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता का नाम	1. तिथि 2. मांग सूचना राशि 3. कुल बकाया ऋण 4. कब्जे की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि, बोली वृद्धि, राशि (रुपये में)	ई-नीलामी तिथि, समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि एवं निरीक्षण तिथि
ऋण खाता- HE01HCH00000073393 1. **नागेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा पिता विनोद कुमार विश्वकर्मा (आवेदक),** 2. **विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट, इसके मालिक नागेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा (सह-आवेदक) के माध्यम से,** 3. **कुसुम विश्वकर्मा पति विनोद कुमार विश्वकर्मा (सह-आवेदक),** 4. **विनोद कुमार विश्वकर्मा (सह-आवेदक), सभी का पताः** वार्ड नं. 05, शौकी नगर, किरोड़ीमलनगर, गणेश चौक, रायगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ 496001, 5. **विनोद कुमार विश्वकर्मा (सह-आवेदक),** पोस्ट बॉक्स नं. 16, खरसिया रोड, रायगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़ 496001.	**08/01/2026** ₹ **33,10,136.00** as on **08/01/2026** ₹ **34,07,551.00** as on **15/06/2026** को भुगतान की तारीख तक आगे के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत और शुल्क के साथ । **28/03/2026 सांकेतिक कब्जा**	खसरा नं.- **3/1/1Ja** (खसरा **3/1/1ka** का भाग), प.ह.नं. 06, मौजा- ग्रामः कोकड़ीतराई, आरएनएम- किरोड़ीमल नगर, तहसील एवं जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496005, क्षेत्रफल- **0.0160** हेक्टेयर में स्थित अचल संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश । **चौहद्दीः उत्तर-** गली, **दक्षिण-** खुशरूल्ला, **पूर्व-** शेष भूमि, **पश्चिम-** शेष भूमि ।	₹ **41,00,000/-** ₹ **4,10,000/-** ₹ **50,000/-**	**15/07/2026** सुबह **11:00** बजे से दोपहर **1:00** बजे तक (प्रत्येक **3** मिनट के असीमित विस्तार के साथ), **14/07/2026** (शाम **5.30** बजे तक) **07/07/2026** और **08/07/2026** (सुबह **10.00** बजे से दोपहर **1.00** बजे तक)
ऋण खाता - HE01MOG00000117445 1. **अकील अहमद पुत्र अब्दुल रशीद खान (आवेदक),** मकान नं. 58, वार्ड नं. 15 दैहानी भाठा, बागबाहरा, बागबाहरा खुर्द (विरान), महासमुंद, छत्तीसगढ़- 493449 2. **साबिया खातून पति अकील अहमद (सह-आवेदक),** मकान नं. 58, वार्ड नं. 15 दैहानी भाठा, बागबाहरा, बागबाहरा खुर्द (विरान), महासमुंद, छत्तीसगढ़- 493449, 3. **ईवी कन्वर्शन (मालिक- अकील अहमद पुत्र अब्दुल रशीद खान) (सह-आवेदक),** कविता नगर मोती नगर शिव मंदिर जाली फैक्ट्री के पास रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	**10/12/2025** ₹ **23,15,023.00** **10/12/2025** तक ₹ **25,23,893.00** **15/06/2026** को भुगतान की तारीख तक आगे के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत और शुल्क के साथ । **06/03/2026 सांकेतिक कब्जा.**	खसरा नं. **31** का भाग (जिसे **31/2** के रूप में फिर से नं. दिया गया), मौजा- तेंदुलोथा खुर्द, प.ह.नं 23, आरआईसी- तेंदुकोना, तहसील- बागबाहरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)- 493449, जिसका एरिया- **78.96** वर्ग मीटर. या **839.59** वर्ग फीट में स्थित आवासी संपत्ति के समस्त भाग व अंश । **चौहद्दीः उत्तर-** सड़क, **दक्षिण-** शासकीय भूमि, **पूर्व-** लक्ष्मीचंद का मकान, **पश्चिम-** नेतराम का मकान ।	₹ **24,30,000/-** ₹ **2,43,000/-** ₹ **50,000/-**	**15/07/2026** सुबह **11:00** बजे से दोपहर **1:00** बजे तक (प्रत्येक **3** मिनट के असीमित विस्तार के साथ), **14/07/2026** (शाम **5.30** बजे तक) **07/07/2026** और **08/07/2026** (सुबह **10.00** बजे से दोपहर **1.00** बजे तक)
ऋण खाता - HE01HCH00000052969 1. **केशव कुमार साहू पुत्र सार्तिक राम साहू (आवेदक),** 2. **कमला साहू (सह-आवेदक),** 3. **उमाशंकर साहू पुत्र सार्तिक राम साहू (सह-आवेदक),** 4. **रूपलता साहू पति केशव कुमार साहू (सह-आवेदक),** 5. **मोनिका साहू पुत्री उमाशंकर साहू (सह-आवेदक),** 6. **बलराम साहू पुत्र सार्तिक राम साहू (सह-आवेदक), सभी का पताः** मकान नं. 102, वार्ड नं. 15, श्याम स्टील गली कोटरा रोड, दरोगापारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़-496001.7. **सुमेधा कूलर्स एंड मोटर निर्माण वर्क्स (सह-आवेदक),** कुरमापाली, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़-496001, 8. **रैमत साहू पुत्र सार्तिक राम साहू (सह-आवेदक),** मकान नं. 102, वार्ड नं. 15, श्याम स्टील गली कोटरा रोड, दरोगापारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़-496001.	**10/12/2025** ₹ **50,97,689.00** as on **10/12/2025** ₹ **51,34,342.00** as on **15/06/2026** को भुगतान की तारीख तक आगे के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत और शुल्क के साथ । **28/02/2026 सांकेतिक कब्जा**	खसरा नं. **210/12** के साथ **213/12**, प.ह.नं.- **22**, शीट नं. **07**, प्लॉट नं. **15** भाग, मौजा- ग्राम दरोगापारा, वार्ड नं. 15, श्याम स्टील गली, कोटरा रोड, , आरआईसी- बैकुंठपुर, तहसील व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)- 496001, क्षेत्रफल- **0.0087** हेक्टेयर या **940** वर्गफीट में स्थित संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश । **विलेख के अनुसार चौहद्दीः उत्तर-** मकरध्वज का मकान, **दक्षिण-** चतुरसिंह की भूमि, **पूर्व-** चिंतामणि का मकान एवं सड़क, **पश्चिम-** भीखम सिंह की भूमि ।	₹ **47,10,000/-** ₹ **4,71,000/-** ₹ **50,000/-**	**15/07/2026** सुबह **11:00** बजे से दोपहर **1:00** बजे तक (प्रत्येक **3** मिनट के असीमित विस्तार के साथ), **14/07/2026** (शाम **5.30** बजे तक) **07/07/2026** और **08/07/2026** (सुबह **10.00** बजे से दोपहर **1.00** बजे तक)
ऋण खाता - X0HERRH00000781974 & X0HERRH00001178863 1. **संजय अवस्थी (आवेदक),** जेड-20, मेन रोड गीता नगर, रायपुर, (छ.ग.)- 492001. **इसके अलावाः** मकान नं. 20, ख. नं. 251 चिरहुलडीह, गीता नगर, रायपुर, (छ.ग.)-492001. 2. **प्रेमलता तिवारी (सह-आवेदक),** 3. **मीना अवस्थी (सह-आवेदक),** 4. **मनीष कुमार अवस्थी (सह-आवेदक),** सभी निवासी। पता - जेड-20, मेन रोड गीता नगर, रायपुर, (छ.ग.)-492001	**15/06/2017** ₹ **1,14,14,296.64/- &** ₹ **76,57,788.59/-** कुल ₹ **1,90,72,085.23/-** as on **09/06/2017** ₹ **2,62,24,693/-** as on **19/06/2026** को भुगतान की तारीख तक आगे के ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत और शुल्क के साथ । **04/09/2017 (सांकेतिक कब्जा)**	खसरा नं. 251, प.ह.नं. 106-बी, शीट नं. **25**, जिसका प्लॉट नं. **46/55, 46/57 एवं 46/1** (भाग), में शामिल स्वामी आत्मानंद वार्ड नं 15, चिरहुलडीह, गीता नगर कॉलोनी, रायपुर खास, तहसील व जिला- रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रफल **6500** वर्ग फुट में स्थित संपत्ति ।	₹ **3,15,00,000** ₹ **31,50,000/-** ₹ **1,00,000/-**	**15/07/2026** सुबह **11:00** बजे से दोपहर **1:00** बजे तक (प्रत्येक **3** मिनट के असीमित विस्तार के साथ), **14/07/2026** (शाम **5.30** बजे तक) **07/07/2026** और **08/07/2026** (सुबह **10.00** बजे से दोपहर **1.00** बजे तक)

1. सभी इच्छुक भागीदारों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वेबसाइट **https://bankauctions.in&www.cholamandalam.com/news/auction-notices** देखें। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रशिक्षण, सहायता, प्रक्रिया के लिए संभावित बोलीदाता **श्री मुहम्मद रहिस- 8124000030 / 6374845616, मेसर्स 4 क्लोसर, रेखा, फोन नंबर- 8142000062, प्रखर शर्मा- 9826432751** से सम्पर्क कर सकते हैं । ईमेल आईडी- **CholaAuctionLAP@chola.murugappa.com.** का संदर्भ लेवें ।
2. नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://bankauctions.in** देखें एवं ई-नीलामी में भाग लेने के लिए **www.cholamandalam.com/news/auction-notices** पर जाएं ।

इसे प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिवस की बिक्री सूचना भी समझी जावे ।

दिनांकः 22.06.2026, स्थानः रायपुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी/ चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कं.लिमि.

न्याय के आंगन में गूंजा योग का संकल्प

- **स्वस्थ आयु के लिए न्यायाधीशों अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने मिलाए कदम**

सूरजपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आज सूरजपुर जिला न्यायालय परिसर में अद्भुत ऊर्जा, सकारात्मकता और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती विनीता वार्नर के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में न्यायपालिका के सभी स्तंभों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर एक साथ योग का अभ्यास किया।

विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ योगाभ्यास

कार्यक्रम को गति देते हुए प्रमुख योग शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पाठक और सह-योग शिक्षक कुमारी नेहा सोनी ने मंच संभाला। उन्होंने न केवल योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम का जीवंत प्रदर्शन कराया, बल्कि बेहद सरल और ज्ञानवर्धक तरीके से यह भी समझाया कि किस आसन को करने से शरीर को क्या विशिष्ट लाभ मिलते हैं। साथ ही, विभिन्न आयु वर्ग और शारीरिक क्षमता वाले लोगों को कौन-से आसन करने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

सिर्फ एक दिन नहीं, जीवनशैली बने योग

न्यायालय के वरिष्ठ जजों ने अपने विचारों से उपस्थित जनसमूह में एक नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने कहा कि हमें सिर्फ आज के दिन योग करके शांत नहीं बैठ जाना है, बल्कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग एक अचूक औषधि है।

स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर विशेष जोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री पायल टोपनो ने सभी को योग दिवस की बधाई देते हुए इस वर्ष की विशेष थीम पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य योग के माध्यम से हर व्यक्ति को एक लंबा, स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन प्रदान करना है।

न्यायपालिका के सभी अंगों ने पेश की एकजुटता की अनूठी मिसाल

इस गरिमामयी आयोजन में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ न्यायाधीशगण, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व न्यायालय के समस्त न्यायिक कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर योग किया। अत्यधिक मानसिक श्रम और तनाव वाले कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह आयोजन न सिर्फ शारीरिक स्फूर्ति लेकर आया, बल्कि मानसिक शांति और कार्यक्षेत्र में आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला एक बेहतरीन व सराहनीय प्रयास साबित हुआ।

गांवों में भी उत्साह से मनाया गया विश्व योग दिवस

ग्रामीणों की रही बड़ी संख्या में सहभागिता

कोरिया। कोरिया जिले में विश्व योग दिवस विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न पंचायत कार्यालय परिसरों, खेल मैदानों तथा ग्राम पंचायतों में निर्मित अमृत सरोवर तटों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योग सत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, ग्राम सचिवों, रोजगार सहायकों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इसके साथ ही मनरेगा के श्रमिकों और स्व-सहायता समूहों की दीदियों की सक्रिय सहभागिता भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने का संदेश दिया। विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग के माध्यम से लोगों को योग के महत्व और उसके दैनिक जीवन में उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। जिला प्रशासन की ओर से योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी ग्राम पंचायतों एवं संबंधित विभागों के समन्वय की सराहना की गई।

श्रेया ने जिले को किया गौरवान्वित

- **बीपीएससी परीक्षा में पाई सफलता, बनीं कल्याण पदाधिकारी**

सूरजपुर/भैयाथान। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और दृढ़ संकल्प से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है जिले की होनहार बिटिया श्रेया गोयल ने कहते हैं न कि उड़ान के लिए पर नही प्रण होनी चाहिए हौसलों से उड़ान होती है इसे श्रेया ने चरितार्थ कर दिखाया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार श्रेया गोयल की

प्रारंभिक शिक्षा है 1 - 8 नेहरू बाल मंदिर भैयाथान में हुई वहीं माध्यमिक शिक्षा 9-10 सरस्वती शिशु मंदिर भैयाथान में होने के पश्चात उच्च माध्यमिक शिक्षा 11-12 हॉली क्रास हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर से कॉमर्स में उच्च शिक्षा कॉलेज हॉली क्रास वूमेन्स कॉलेज अंबिकापुर से बीकॉम में 2017 में 10 वीं में भैयाथान में प्रथम स्थान। 12 वीं में अंबिकापुर शहर में द्वितीय स्थान प्राप्त सीजीबीएसई में यूपीएससी की तैयारी करते हुए बीपीएससी क्लियर हुआ है।

6 साल की मेहनत का परिणाम है। श्रेया ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 20 जून को जारी हुए परीक्षा परिणामों में श्रेया का चयन प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के गरिमामयी पद पर रहते हुआ है। उन्होंने इस परीक्षा में 21वीं रैंक हासिल कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है।

जिले सहित पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिजनों में खुशी की लहर

स्वर्गीय ओम प्रकाश अग्रवाल की पौत्री और संजय अग्रवाल की सुपुत्री श्रेया गोयल की इस अभूतपूर्व सफलता से पूरे परिवार और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। प्रदीप किराना स्टोर्स भैयाथान परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रेया की इस उपलब्धि पर उनके भाई शुभम अग्रवाल सहित पूरे परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी इस शानदार कामयाबी पर बेहद खुश श्रेया गोयल ने इसका पूरा श्रेय ईश्वर की असीम अनुकंपा, अपने माता-पिता के आशीर्वाद, भैया-भाभी के निरंतर सहयोग, परिवारजनों, शिक्षक वर्ग और अपने मित्रगणों के कुशल मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने कहा कि अपनों के सहयोग और सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत के कारण ही वे इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रही हैं। श्रेया गोयल की इस कामयाबी से युवाओं, विशेषकर क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ने और प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने की एक नई प्रेरणा मिलेगी।

आवास प्लस 2.0 की सूची के सत्यापन हेतु 24 जून को होगा ग्राम सभाओं का आयोजन

- **जिले में 1.40 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे पूर्ण, ग्राम सभा में होगा पात्र हितग्राहियों का सामाजिक सत्यापन**

सूरजपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत संचालित आवास प्लस 2.0 अभियान के तहत जिले में पात्र आवासहीन एवं कच्चे आवासों में निवासरत परिवारों की पहचान की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 24 जून 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची (परमानेंट वेट लिस्ट - पीडब्ल्यूडी) का सार्वजनिक अवलोकन एवं सत्यापन कराया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा सूची में शामिल प्रत्येक नाम का ग्राम स्तर पर सामाजिक सत्यापन हो सके। प्रशासन ने इसे ''मोर आवास - मोर अधिकार'' अभियान का महत्वपूर्ण चरण बताते हुए ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी है।

जिला प्रशासन के अनुसार आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण का कार्य जिले के सभी विकासखंडों में पूर्ण कर लिया गया है और इसके माध्यम से कुल 1 लाख 40 हजार 79 संभावित हितग्राहियों की पहचान की गई है। विकासखंडवार स्थिति देखें तो सर्वाधिक 32 हजार 377 हितग्राही प्रतापपुर में चिन्हांकित किए गए हैं, जबकि सूरजपुर में 31 हजार 23, रामानुजनगर में 26 हजार 583, भैयाथान में 24 हजार 282, ओड़गी में 14 हजार 549 तथा प्रेमनगर में 11 हजार 265 संभावित हितग्राही चिन्हित किए गए हैं। इन सभी परिवारों की जानकारी अब ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर उनकी पात्रता की पुष्टि की जा सके।

24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। उपस्थित ग्रामीण सूची का अवलोकन कर सकेंगे और यदि किसी व्यक्ति के संबंध में दर्ज जानकारी गलत पाई जाती है अथवा कोई पात्र परिवार सूची से छूट गया है, तो वे उसके संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रशासन के अनुसार ग्राम सभा में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक संशोधन के पश्चात अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी दोनों सुनिश्चित होंगी।

ग्राम सभा में सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची को प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद पात्र परिवारों को योजना अंतर्गत आवास स्वीकृति प्रदान करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल अपलोडिंग के माध्यम से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध बनेगी तथा हितग्राहियों को योजना का लाभ शीघ्र प्राप्त होगा।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ श्रेणियों के परिवारों को अपवर्जन की सूची में रखा गया है। इनमें पक्के मकान अथवा दो से अधिक कमरों वाले पक्के मकान में निवासरत परिवार, मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन के स्वामी, यंत्रीकृत कृषि उपकरण रखने वाले परिवार, 50 हजार रुपये या उससे अधिक क्रेडिट लिमिट वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी कर्मचारी वाले परिवार, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम संचालित करने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक आय अर्जित करता हो, आयकरदाता एवं व्यावसायिक करदाता परिवार तथा 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित अथवा 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार सम्मिलित हैं। वहीं प्राथमिकता निर्धारण में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वरीयता दी जाएगी।

एकाकी जीवन में उर्मिला को मिला सुरक्षित आशियाने का संबल

कोरिया। समय पर मिली छोटी-सी मदद किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसा ही बदलाव कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलपुर निवासी श्रीमती उर्मिला के जीवन में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मिले पक्के मकान ने उनके एकाकी जीवन को नई सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान किया है।

कठिन परिस्थितियों में किया संघर्ष

जिला पंचायत कोरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही श्रीमती उर्मिला का वैवाहिक जीवन टूट गया। इसके बाद उनके सामने आजीविका और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती खड़ी हो गई। विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत पूजा महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें गांव के विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य मिला। इसी आय के माध्यम से वह अपने जीवन-यापन की जिम्मेदारी निभा रही हैं।

जरूरत के समय मिली आवास योजना की सहायता

कच्चे मकान में रहकर अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही उर्मिला को गत वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ। योजना से प्राप्त सहायता राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की नई शुरुआत की। उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने पक्के मकान का निर्माण पूरा किया। वर्षों से सुरक्षित और सम्मानजनक घर का सपना देखने वाली उर्मिला की यह इच्छा आखिरकार पूरी हो गई।

पक्के घर से बढ़ा आत्मविश्वास

श्रीमती उर्मिला बताती हैं कि पहले उन्हें अपने रहने की सुरक्षा और भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। बरसात और अन्य मौसमों में कच्चे मकान की स्थिति उन्हें परेशान करती थी। लेकिन अब पक्का घर मिलने के बाद उनकी चिंताएं काफी हद तक दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और समाज में सम्मान भी मिला है। अब वह अपने आजीविका संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं तथा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उर्मिला को केवल एक पक्का घर ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर जीवन का नया आधार भी प्रदान किया है।

मछली पालन बना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आधार

- **सरकारी योजनाओं से मिल रहा संबल, मत्स्य पालन से खुल रहे आय और स्वरोजगार के नए द्वार**

कोरिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि के साथ-साथ सहायक व्यवसायों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है मछली पालन, जो आज केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन चुका है। कम लागत, कम समय में बेहतर उत्पादन और बाजार में लगातार बढ़ती मांग के कारण मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी किसानों से खेती को केवल धान उत्पादन तक सीमित न रखते हुए दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाने का आह्वान किया है। इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रहा मछली पालन

ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे सीमित भूमि और अपेक्षाकृत कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तालाब, जलाशय, नहर और अन्य जल स्रोतों का उपयोग कर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। बढ़ती आबादी और पौष्टिक भोजन की मांग के कारण मछली की खपत लगातार बढ़ रही है।

नैनो उर्वरक-कम लागत, अधिक उत्पादन, खुशहाल किसान

- **नई तकनीकों से जुड़े किसान कृपाल, नैनो उर्वरकों को बताया खेती के लिए लाभकारी**

निवासी कृपाल सिंह (50 वर्ष) खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपनी तीन एकड़ कृषि भूमि के लिए वे आदिम जाति सहकारी समिति धौराटिकरा पहुंचे, जहां से उन्होंने खेती की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डीएपी, राखड़, धान बीज, मूंग बीज तथा नैनो यूरिया प्राप्त की।

कोरिया। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे उन्नत उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर खेती को अधिक उत्पादक, किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज एवं उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होने से किसानों को खेती की तैयारियों में सुविधा मिल रही है और वे नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

कोरिया जिले के ग्राम आनी कृपाल सिंह ने बताया कि कृषि विभाग एवं सहकारी समिति के माध्यम से उन्हें नैनो उर्वरकों की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने इस वर्ष अपनी फसल में नैनो यूरिया के उपयोग का निर्णय लिया है। उन्हें विश्वास है कि इससे फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और नैनो उर्वरक किसानों के लिए एक प्रभावी एवं नवाचारपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। कम लागत में बेहतर पोषण उपलब्ध कराने वाले ये उर्वरक खेती की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

कृपाल सिंह के अनुसार नैनो यूरिया फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने का एक प्रभावी माध्यम है।

कुंभकर्णीय नींद में सोये रहते हैं जिम्मेदार, आम जनता परेशान

बेवज़ह बिजली कटौती से पूरे केसीजी जिले के उपभोक्ता परेशान

- **बिजली विभाग की लचर व्यवस्था पर उठ रहे बड़े सवाल**

खैरागढ़। केसीजी जिले में इन दिनों बेवज़ह बिजली कटौती की बड़ी समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और बिजली विभाग की इस लचर व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं लेकिन आम जनता को राहत देने के बजाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोये रहते हैं। पाठकों को बता दें कि केसीजी जिले के ग्रामीण अंचलों में कई जगह हालात इस कदर बदतर है कि बिजली कब आयेगी और कब चली जायेगी इसका कोई निश्चित समय नहीं रहता और दिन हो या रात उपभोक्ताओं को बिना सूचना दिये भी घंटों बिजली गुल रहने की बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है वही इससे

आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ-साथ खेती-किसानी, छोटे कारोबार और छात्रों की पढ़ाई भी बहुत प्रभावित हो रही है। बिजली संकट की इस गंभीर समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले कई महीनों तक विद्युत विभाग द्वारा प्री-मानसून मेंटनेंस, लाइन सुधार और अन्य तकनीकी कार्यों के नाम पर नियमित रूप से बिजली बंद रखी गई और तब उपभोक्ताओं ने यह सोचकर असुविधा भी सहन की थी कि बरसात के मौसम में उन्हें निर्बाध और बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी लेकिन मानसून की दस्तक से पहले ही विद्युत विभाग के दावों की पोल खुल गई है और हकीकत सामने आने लगी है क्योंकि हल्की हवा चलने या ज़रा सी बारिश होते ही कई गांवों और कस्बों की बिजली कई घंटों के लिए पूरी तरह ठप्प हो जाती है और लाखों रुपये खर्च कर किये गये कथित सुधार और मेंटनेंस कार्यों के बावजूद स्थिति में कोई विशेष बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है जो विभाग की लापरवाही की पोल खोलती है। गौरतलब है कि केसीजी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि यदि मामूली मौसम परिवर्तन से ही बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है तो काफी लंबे समय तक चलाये गये मेंटनेंस अभियानों का वास्तविक लाभ क्या हुआ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या और भी गंभीर है यहां तक कि कई गांवों में बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय नहीं होने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है और किसानों को सिंचाई कार्यों में परेशानी हो रही है तो वहीं गर्मी और उमस के बीच बार-बार बिजली गुल होने से लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया है।

गौरतलब है कि उपभोक्ताओं की नाराजगी का एक बड़ा कारण विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का उदासीन और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी बताया जा रहा है। जिले के स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली बंद होने पर जानकारी लेने के लिए फोन करने पर अधिकांश मामलों में कॉल रिसीव नहीं किये जाते और यदि संपर्क हो भी जाये तो अक्सर एक ही जवाब मिलता है कि ऊपर से लाइन बंद है या फॉल्ट सुधार का कार्य चल रहा है वही इस तरह के रटे-रटाए झूठे जवाबों से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है जिससे लोगों में विद्युत विभाग के प्रति नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है और ये लगातार बिगड़ती विद्युत व्यवस्था के कारण विपक्ष द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले आरोपों को भी बल मिल रहा है। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि जिले के कई ग्रामीण इलाकों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित और चरमराई हुई नजर आ रही है और हालात कई स्थानों पर इस कदर खराब है कि लोग अब यह कहने लगे हैं कि बिजली व्यवस्था का कोई जवाबदेह तंत्र दिखाई नहीं देता और पूरा सिस्टम सिर्फ़ भगवान भरोसे संचालित हो रहा है।

प्रशासन की सजगता से रूकवाया गया बाल विवाह

बलरामपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर नियंत्रण के लिए जिले में जिला प्रशासन सक्रीय है। इसी कड़ी में विकासखंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरंधा में प्रशासन की तत्परता और समन्वित प्रयास से नाबालिक बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत कोरंधा में एक नाबालिग बालिका का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन बलरामपुर तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थल पर पहुंचकर जांच की जिसमें बालक एवं बालिका की आयु, विवाह के लिए निर्धारित आयु से कम पायी गई। टीम ने मौके पर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाइश दी गई। कम उम्र में विवाह होने से बालक एवं बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अल्प आयु में मातृत्व से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। समझाइश पर परिजनों ने अपने बच्चों की सही आयु में विवाह करने की बात कही। इस दौरान ग्राम वासियों से भी अपील की गई कि वे अपने आसपास इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानून की जानकारी दी जा रही है, साथ ही समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फेसबुक हैक कर व्याख्याता को बदनाम करने की साजिश, भ्रामक और अमर्यादित पोस्ट

सूरजपुर। रामानुजनगर शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल गणेशपुर रामानुजनगर, सूरजपुर में पदस्थ व्याख्याता सुदीप कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से वायरल हो रहे एक विवादित पोस्ट का कड़ा खंडन किया है। उन्होंने इस कृत्य को अपनी छवि धूमिल करने की नीयत से अज्ञात तत्वों द्वारा रची गई एक गंभीर साजिश करार दिया है।

6-7 महीने पहले ही हैक हो चुकी है आईडी

व्याख्याता सुदीप कुमार शर्मा ने जारी बयान में बताया कि लगभग 6-7 माह पूर्व ही उनकी मूल फेसबुक आईडी हैक हो गई थी। इसकी लिखित व मौखिक शिकायत उन्होंने तत्काल रामानुजनगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा उक्त फेक आईडी को ब्लॉक करा दिया गया था। तब से उन्हें अपनी फेसबुक आईडी पर कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही थी। बीते दिनों किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हैक की जा चुकी आईडी या उनके नाम का इस्तेमाल कर एक भ्रामक पोस्ट वायरल कर दिया। इस पोस्ट में मृतक लल्ला सिंह की मृत्यु के संबंध में और कलेक्टर कोरिया द्वारा कानून व्यवस्था हेतु लागू धारा 163 बीएनएस के आदेश की प्रति डालकर लिखा गया था कि रिश्वतखोर लल्ला सिंह अभी तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है।

युद्ध नशे के विरुद्ध

नशे से दूरी बनाने की पहल अभियान नवजीवन

- स्कूली बच्चों ने नशे से दूरी के लिए रंगोली, निबंध व पोस्टर के माध्यम से दिया मजबूत संदेश

सूरजपुर। युवाओं को नशे से दूर रखने, नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में अभियान नवजीवन चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार, 22 जून 2026 को थाना भटगांव पुलिस ने स्थानीय एडी जुबली स्कूल में विशेष जागरुकता अभियान का आयोजन किया जहां पुलिस ने छात्रों से सीधे संवाद कर उन्हें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी साथ ही इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में उनका सहयोग भी मांगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने यह संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में योगदान देंगे।

थाना प्रभारी भटगांव बृजेश सिन्हा ने बेहद सरल भाषा में छात्रों को बताया जाता है नशा व्यक्ति के दिमाग और शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसकी लत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। नशे की गिरफ्त में आने से पढ़ाई, करियर, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए नशे से दूरी बनाकर रखे।

थाना प्रभारी ने कहा कि नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री, तस्करी या उससे जुड़ी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, उसे मानस पोर्टल टोल-फ्री नंबर 1933, पुलिस कन्ट्रोल रूम व संबंधित थाना प्रभारी को सीधे कॉल करके किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दे सकते हैं या मदद मांग सकते है। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, जिससे लोग बिना किसी डर के सूचना साझा कर सकते हैं।

इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा नशे से दूरी और जागरूकता के लिए आकर्षक व ज्ञानवर्धक जानकारियों को समाहित करते हुए रंगोली, पोस्टर का प्रदर्शन किया एवं निबंध के माध्यम से नशे से बचाव की जानकारी दी। पोस्टर मेकिंग में प्रथम दुर्गा राजवाड़े, द्वितीय अंश, तृतीय माही सिंह, रंगोली में प्रथम ऋतु राजवाड़े, द्वितीय नंदिनी तिवारी, तृतीय श्रेया मिश्रा, निबंध में प्रथम अंश को थाना प्रभारी के द्वारा मेमोंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष परमेश्वरी राजवाड़े, पार्षद लक्ष्मी महतो, पीएसआई कृष्ण भास्कर, अनिमेश दास, एएसआई विवेकानंद सिंह, राजकिशोर खलखो, स्कूल के प्राचार्य लियोस सदोम, शिक्षकगण, पुलिस कर्मचारी व स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

सीमित पूंजी से संघर्ष कर रहे भागवत को पीएम स्वनिधि योजना से मिला सहारा

25 हजार ऋण से व्यवसाय को बढ़ाने में मिली मदद

बलरामपुर। विकासखंड बलरामपुर के ग्राम झलपी निवासी भागवत गुप्ता के जीवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने नई उम्मीद जगाई है। सब्जी विक्रेता के रूप में अपना परिवार चलाने वाले भागवत गुप्ता की आर्थिक स्थिति अब पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई है। इस योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उनके छोटे व्यवसाय को नई गति दी है

भागवत गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार का मुख्य आधार सब्जी बिक्री का व्यवसाय है। वे गांव और आसपास के क्षेत्रों में सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पहले सीमित पूंजी के कारण वे पर्याप्त मात्रा में सब्जियां नहीं खरीद पाते थे, जिससे उनकी आमदनी भी सीमित रहती थी। कई बार परिवार के दैनिक खर्चों का प्रबंधन करना भी कठिन हो जाता था।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आवेदन किया और योजना के तहत उन्हें 25 हजार ऋण स्वीकृत हुआ। इस राशि से उन्होंने अपने व्यवसाय में पूंजी बढ़ाई, अधिक मात्रा में सब्जियों की खरीद शुरू की तथा अपने कारोबार का विस्तार किया ।

अंधेरे में सिसकती जिंदगी

80 वर्षीय सूरदास रामकुमारी साहू योजनाओं से वंचित

- न आवास, न पेंशन, न अंत्योदय राशन कार्ड

सूरजपुर। रामानुजनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में रहने वाली 80 वर्षीय दृष्टिबाधित वृद्धा रामकुमारी साहू की जिंदगी आज भी अभाव, संघर्ष और उपेक्षा के बीच गुजर रही है। उम्र के इस पड़ाव में जहां उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सहारा मिलना चाहिए था, वहीं वे कई महत्वपूर्ण सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित बताई जा रही हैं। उनकी स्थिति न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है, बल्कि योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

जानकारी के अनुसार करीब 20 वर्ष पूर्व खेत में धान लुवाई के दौरान उनकी आंखों में गंभीर चोट लग गई थी। समय पर उचित उपचार नहीं मिलने और घरेलू उपचार के कारण धीरे-धीरे उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पति स्वर्गीय रामसहाय साहू का निधन भी लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका है। इसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह संघर्षों से घिर गया। वर्तमान में वे अपने पुत्र जोखन लाल साहू के साथ रहती हैं, जो मजदूरी करने के साथ-साथ थोड़ी कृषि भूमि में खेती करता है तथा गर्मी के दिनों में गांव-गांव साइकिल से बर्फ बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता है।

परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। बारिश के मौसम में मकान की छत टपकती है और दीवारें भी कमजोर हो चुकी हैं। आर्थिक तंगी के बीच परिवार के लिए पक्का आवास बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि रामकुमारी साहू को महतारी वंदन योजना, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, अंत्योदय राशन कार्ड तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है।

महाविद्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

- रानी रश्मि देवी सिंह शास.महाविद्यालय में हुआ आयोजन

खैरागढ़। रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मिली जानकारी अनुसार रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ के प्राचार्य डॉ ओपी गुप्ता के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं मेरा युवा भारत खैरागढ़ छुईखदान गंडई के संयुक्त तत्वावधान में 21 जून रविवार को महाविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिये योग विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में योग शिक्षक विजय वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराकर उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापक सुरेश आडवाणी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी यशपाल जंघेल, सतीश कुमार, सृष्टि वर्मा, भबीता मंडावी, मनीषा व मोनिका जत्ती के साथ बड़ी संख्या में कार्यालय कर्मचारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक भी उपस्थित रहें।

सचिव के अड़ियल रवैये से परेशान ग्रामीण, पंचायत कार्यालय आने से बना रहे दूरी

- ग्राम पंचायत चाचीडाड 2 में लोगों के काम प्रभावित होने का आरोप

प्रतापपुर। ग्राम पंचायत चाचीडाड 2 में पंचायत सचिव रामसती सुरता के कार्यशैली और व्यवहार को लेकर ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव के अड़ियल रवैये के कारण पंचायत के सामान्य कार्य भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार पंचायत से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए ग्रामीणों को कई बार पंचायत कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में प्रमाण पत्र, योजनाओं से संबंधित जानकारी, मजदूरी भुगतान, आवेदन सत्यापन एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए पहुंचने पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिव द्वारा लोगों से ठीक ढंग से बात नहीं की जाती, जिससे पंचायत में लोगों के बीच नाराजगी का माहौल बना हुआ है।

ग्रामीणों के मुताबिक पहले पंचायत कार्यालय में लोगों की आवाजाही बनी रहती थी, लेकिन अब सचिव के व्यवहार से परेशान होकर कई लोग पंचायत जाने से भी बचने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में लोगों को राहत मिलने के बजाय और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मामला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चाचीडाड 2 का है। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पंचायत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि आम ग्रामीणों के कार्य समय पर हो सकें और उन्हें बार-बार भटकना न पड़े। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर शिकायत करने को मजबूर होंगे। वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।

इस संबंध में जब जनपद पंचायत प्रतापपुर के सीईओ अनिल कुमार तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी मिली है। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि पंचायत सचिव दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

सीईओ के इस बयान के बाद अब ग्रामीणों को प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की उम्मीद है।

28 से 30 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान

बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अंतर्गत पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। जिसका उद्देश्य जिले के सभी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर भारत की पोलियो-मुक्त बनाए रखना तथा बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। जिले में अभियान के प्रथम दिवस 28 जून 2026, रविवार को निर्धारित 693 पोलियो बूथों पर 1386 स्वास्थ्यकर्मियों एवं सहयोगी दलों द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके पश्चात 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करेंगी। अभियान के दौरान जिले के 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 1 लाख 07 हजार 731 बच्चों को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासन के आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन पर उठे सवाल

शालेय शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी स्पष्ट आदेश के बावजूद जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। इस मामले में शालेय शिक्षक संघ सूरजपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इस समस्या का समाधान कराने की मांग की है। विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि सेवाकाल के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों की उक्त योग्यता को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए। शासन द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने विभागीय अनुमति के बिना भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनकी योग्यता का भी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बावजूद विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा 16 जून 2026 को एक आदेश जारी कर संबंधित शिक्षक से परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति आदेश प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। पत्र में उल्लेख है कि विभागीय अनुमति आदेश उपलब्ध कराने के पश्चात ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता को सेवा पुस्तिका में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

शालेय शिक्षक संघ सूरजपुर ने इस पत्र पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि जब शासन स्वयं बिना विभागीय अनुमति शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की योग्यता को सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का निर्णय ले चुका है, तब पुनः विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा विभागीय अनुमति आदेश की मांग किया जाना शासन के स्पष्ट निर्देशों के क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों की मंशा शिक्षकों को अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं से मुक्त करते हुए उनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी योग्यता को मान्यता प्रदान करना है। ऐसे में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग से न केवल शिक्षकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि शासन के आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी संशय उत्पन्न हो रहा है। शालेय शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि शासन के आदेश एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा जारी पत्र के बीच उत्पन्न विसंगति का परीक्षण किया जाए तथा स्पष्ट निर्देश जारी कर सभी पात्र शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी योग्यता सेवा पुस्तिका में तत्काल दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

महिपाल के कच्चे घर की चिंता हुई दूर

प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के आवास का सपना हुआ पूरा

बलरामपुर। शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। जिले में भी इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों परिवारों को पक्की छत मिल चुकी है और उनका जीवन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और बेहतर हुआ है।

विकासखण्ड कुसमी के ग्राम पंचायत सेमरा के निवासी महिपाल पैकरा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। वे बताते हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में मौसम अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में हमेशा डर बना रहता था कि कहीं मकान को क्षति न पहुंचे। सीमित आय होने के कारण पक्का घर बनवाना महिपाल के लिए असंभव था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए राहत बनी। योजना के अंतर्गत उन्हें शासन से पक्का आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हुई।

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
ग्राम-उच्चभिट्ठी
दिनांक 17/06/2026
ईश्तहार
आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका बिहारी लाल पिता/पति स्व. पतिराम जाति .... साकिन उच्चभिट्ठी तहसील चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ने इस न्यायालय में अपने पुत्र/पुत्री/पिता/पति .... के जन्म/मृत्यु दिनांक 13/10/1997 स्थान पर उच्चभिट्ठी कारण से होने पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पटवारी मय पंचनामा, शपथ पत्र सहित पेश किया है। अतः जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 03/07/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित हो कर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा
आज दिनांक 17/06/2026 को न्यायालय के सील मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।
जारी दिनांक 17/06/2026
पेशी दिनांक 03/07/2026
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
सील **चांपा**

न्यायालय तहसीलदार लालपुर थाना जिला-मुंगेली (छ.ग.)
//ईश्तहार//
रा.प्र.क्र. ब-121/2026
क्रमांक/18/वाचक/तह./2026
लालपुर थाना दिनांक 18.06.2026
सर्वधारणा/आम जनता ग्राम तेलियापुरान को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयकुमार पति/पिता श्री महेत्तर राम जाति तेली साकिन तेलियापुरान तहसील लालपुर थाना जिला-मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया है कि आवेदक के पत्नि कालिका बाई आ. श्री जयकुमार के मृत्यु दिनांक 02/07/2007 ग्राम तेलियापुरान को हो जाने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु इस न्यायालय से आदेश हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति हो तो न्यायालय में दिनांक 02/07/2026 समय 11:00 बजे दिन को स्वयं/अपने प्राधिकृत के माध्यम से दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 18/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
लालपुर थाना
सील **जिला-मुंगेली (छ.ग.)**

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मुंगेली (श.)
तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.)
//सूचना//
श्री धनंजय पिता जगराम मरार निवासी मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)
संदर्भित पत्र में विषयांतर्गत न्यायालय तहसीलदार के आदेशानुसार आपका आवेदन पर ग्राम मुंगेली म.नं. 2 प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. मुंगेली (ग्रा), तहसील-मुंगेली, जिला-मुंगेली स्थित भूमि खसरा नं. 1137/15 रकबा 0016 हेक्टेयर का स्थल सीमांकन मौके पर दिनांक 29/06/2026 को 10:00 बजे किया जायेगा।
अतः आप आवश्यक दस्तावेज व सीमांकन हेतु आवश्यक संसाधन के साथ स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल के आसपास के व्यक्तियों को सूचित करायें।
श्री आशीष मौर्य प.ह.नं. 19 को सूचनार्थ आप संबंधित ग्राम के आवश्यक अभिलेख सहित स्थल पर उपस्थित रहें एवं हितबद्ध पक्षकारों को कोटवार के माध्यम से सीमांकन पूर्व सूचित करें।
राजस्व निरीक्षक
सील **मुंगेली (श.)**

समक्षः- श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय छुईखदान जिला-के.सी.जी. (छ.ग.)
//शपथ-पत्र//
मैं कमलेश कुमार पिता रामदास जाति-मरार निवासी सिलपट्टी तहसील-छुईखदान जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.) शपथ पूर्वक निम्न कथन व्यक्त करता हूं-
1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है।
2. यह कि भारत शासन द्वारा मेरे पुत्री का आधार कार्ड जिसका नंबर 5167 8259 4297 है जिसमें मेरे पुत्री का नाम मंजूशा पटेल लिखा गया है एवं आधार कार्ड में जन्म दिनांक 01/01/2012 वह गलत है।
3. यह कि मेरे पुत्री के आधार कार्ड में नाम मंजूशा पटेल के स्थान पर सही नाम तनिषा एवं सही जन्म दिनांक 23/01/2011 किया जाए।
4. यह कि उपरोक्त शपथपत्र में लेख की गई समस्त जानकारी सही व सत्य है यदि इस शपथ पत्र में लिखी गई बातों के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके लिए मैं शपथकर्ता स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
शपथकर्ता
- सत्यापन -
मैं शपथकर्ता सत्य निष्ठा से सत्यापन करता हूं कि शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 4 में जो जानकारी दी गयी है वह सत्य एवं सही है।
स्थान-छुईखदान
दिनांक 22/06/2026
सत्यापनकर्ता
सील **कमलेश पटेल**

समक्षः- श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय छुईखदान जिला-के.सी.जी. (छ.ग.)
//शपथ-पत्र//
मैं रहमान खान पिता इमदाद खान जाति मुस्लमान उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम-उदयपुर तहसील-छुईखदान जिला के.सी.जी. (छ.ग.) शपथ पूर्वक निम्न कथन व्यक्त करता हूं-
1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है।
2. यह कि भारत शासन द्वारा जारी मेरे पुत्र के आधार कार्ड जिसका नंबर 3619 0896 0119 है जिसमें मेरे पुत्र का नाम सुरेक खान लिखा गया है। एवं जन्म तिथि 01/01/2010 है।
3. यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम सुरेक खान के स्थान पर नाम शोएब खान किया जाए। एवं जन्म तिथि 01/01/2010 के स्थान पर जन्म तिथि 04/11/2010 किया जाए।
4. यह कि उपरोक्त शपथपत्र में लेख की गई समस्त जानकारी सही व सत्य है यदि इस शपथपत्र में लिखी गई बातों के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके लिए मैं शपथकर्ता स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
शपथकर्ता
- सत्यापन -
मैं शपथकर्ता सत्य निष्ठा से सत्यापन करता हूं कि शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 4 में जो जानकारी दी गयी है वह सत्य एवं सही है।
स्थान-छुईखदान
दिनांक 22/05/2026
सत्यापनकर्ता
सील **रहमान खान**

प्ररूप-(तीन)
शपथ-पत्र
मैं फूलमति (FULMATI) (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी मोहन दुग्गा उम्र 27 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम चिपरेल पोस्ट देवगांव तहसील व जिला नारायणपुर (छ.ग.) एतद् द्वारा पूर्णतः पुष्टि करती हूं तथा निम्नानुसार घोषित करती हूं :-
1. मैं ग्राम चिपरेल पोस्ट देवगांव तहसील व जिला नारायणपुर (छ.ग.) की स्थायी निवासी हूं।
2. मेरा पुराना नाम फूलमती (FULMATI) है और मैं अपना उपनाम सुधार कर मेरा नाम सही उपनाम सहित फुलमती दुग्गा (FULMATI DUGGA) (नया नाम) करवाना चाहती हूं। जो मेरे विवाह प्रमाण पत्र में अंकित है।
3. मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालयमें कोई प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है।
4. मैं नाम बदलकर, यदि कोई, गैर कानूनी काम करती हूं तो उसके लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगी।
5. मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रही हूं तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।
शपथकर्ता
- सत्यापन -
मैं शपथकर्ता श्रीमती फुलमती दुग्गा पति श्री मोहन दुग्गा सत्यापित करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की कंडिका 01 से 05 तक की समस्त जानकारी मेरे स्वयं के ज्ञान से सत्य एवं सहीं है। आज दिनांक 22/06/2026 को स्थान नारायणपुर में अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान कर सत्यापित की।
स्थान :- नारायणपुर
दिनांकः- 22/06/2026
सत्यापनकर्ता
सील **फुलमती**

'न चेकिंग, न ड्रेस कोड, प्राइवेट कर्मचारियों से गिनवाए जा रहे थे नोट', चंदा चोरी में एसआईटी का बड़ा खुलासा

लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले की एसआईटी जांच कर रही है. इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. एसआईटी को हर स्तर पर घोर लापरवाही मिली है. राम मंदिर ट्रस्ट की रकम में बैंकिंग का काम देख रही एसबीआई का ही नोट अलग कराने/गड्डी बनवाने और गिनवाने का काम था. एसबीआई निजी सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों को ठेके पर लेकर नोट गिनवाती थी.

आने जाने के दौरान नहीं होती थी चेकिंग

जानकारी के अनुसार एसबीआई ने वाराणसी की निजी सिक्योरिटी एजेंसी को ठेका दिया था. निजी सिक्योरिटी एजेंसी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर अयोध्या के ही लड़कों को नोट गिनवाने के काम में रख दिया था. परिचित की सिफारिश पर ही नौकरी मिलने की प्रथा पर अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी पर लगवा दिया था।

ड्यूटी पर आने-जाने के दौरान चेकिंग में भी लापरवाही सामने आई है. कौन क्या लेकर आ रहा क्या लेकर जा रहा, कोई जांच नहीं होती थी. घरेलू कपड़ों में ही कर्मचारी राम मंदिर ट्रस्ट के कमरे में बैठकर नोट गिनने लगते थे. सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने में भी लापरवाही सामने आई है. चोरी करने के लिए कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे और चोरी कर लेते थे।

ड्रेस कोड का भी नहीं होता था पालन

सभी के लिए ड्रेस कोड बनाया गया था और एक ड्रेस भी दी गई थी. लेकिन पहनता कोई नहीं था. एसआईटी की पड़ताल में मंदिर परिसर से दान पेटी ट्रस्ट के कमरे में ले जाने से लेकर बैंक में नोट जमा होने तक हर स्तर पर लापरवाही सामने आई है.

इधर अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई संभावित है. मामला कोर्ट नंबर-2 में सूचीबद्ध किया गया है.

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मोहित अशोक शर्मा ने बताया कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) कर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा. उनके अनुसार यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और व्यापक जनहित से जुड़ा है, इसलिए इस पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की अपेक्षा की जा रही है. याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले को पूरक सूची (सप्लीमेंट्री लिस्ट) में शामिल कराने का अनुरोध भी किया जा सकता है.

जांच की जद में आए कर्मचारियों को अयोध्या छोड़ने की मनाही

प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद SIT विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जांच के दायरे में आए सभी लोगों को बिना सूचना अयोध्या छोड़ने से मना कर दिया है.

जांच में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर छोड़ने से पहले एसआईटी को जानकारी दें. यह फैसला जांच को प्रभावित होने से रोकने और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से तुरंत पूछताछ सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. फिलहाल एसआईटी मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है।

अब श्रीलंका पर अमेरिका का फोकस दो सीनियर अफसर दौरे पर

नई दिल्ली। कोलंबो में अमेरिका के दो वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग दौरों पर श्रीलंका पहुंचे हैं. इनमें पैसिफिक एयर फोर्सेज के कमांडर जनरल केविन श्नाइडर भी शामिल हैं. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ये दौरे रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित हैं. रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर क्षेत्र में वॉशिंगटन की बढ़ती सक्रियता के बीच इन दौरों को अहम माना जा रहा है.

अमेरिकी दूतावास के मुताबिक, श्नाइडर रविवार को तीन दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे और उनका दौरा 24 जून को खत्म होगा. दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री एस पॉल कपूर भी रविवार को ही तीन दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे. ये हाई प्रोफाइल दौरे ऐसे समय में हो रहे हैं जब हिंद महासागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और हाल के वर्षों में चीन ने बुनियादी ढांचे में निवेश और समुद्री मौजूदगी का दायरा बढ़ाया है।

शांति समझौते की ओर बढ़े अमेरिका और ईरान!

अमेरिका अपनी व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत श्रीलंका समेत क्षेत्र के देशों के साथ रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक जुड़ाव को और गहरा करने की कोशिश में है. अमेरिकी मिशन के

अनुसार, श्नाइडर अपने दौरे के दौरान श्रीलंका सरकार और रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे. इनमें रक्षा मंत्रालय और श्रीलंका वायुसेना के नेता भी शामिल हैं. दूतावास ने कहा कि बातचीत का फोकस हवाई और समुद्री क्षेत्र की निगरानी, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा.

श्नाइडर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के सभी कर्मियों और संसाधनों की निगरानी करते हैं. दूतावास ने इस यात्रा को अमेरिका-श्रीलंका रक्षा साझेदारी की बढ़ती मजबूती का संकेत बताया. उसने इसे साझा अभ्यासों, सैन्य आदान-प्रदान और वरिष्ठ स्तर पर लगातार संवाद पर बने फैलते द्विपक्षीय रिश्ते में नया अहम पड़ाव भी कहा. दूतावास ने कहा, अमेरिका शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने की सामूहिक कोशिश में श्रीलंका को एक जरूरी साझेदार मानता है।

सौगत रॉय ने बजट सत्र से पहले सरकार पर उठाए सवाल

बागी टीएमसी सांसदों की सदस्यता रद्द करें स्पीकर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस दौरान सौगत रॉय के साथ चार अन्य सांसद भी इस बैठक में शामिल थे। करीब एक घंटे तक चली इस बातचीत में टीएमसी नेताओं ने बागी सांसदों के कदम को नियम के खिलाफ बताया।

सौगत रॉय ने स्पीकर से कहा कि जो सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं, उन्हें कानून के हिसाब से लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि इन बागी सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय (मर्जर) के नियमों का पालन नहीं किया है।

इसलिए उनके नए गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सौगत रॉय को उम्मीद है कि स्पीकर संविधान के अनुसार फैसला लेंगे।

पश्चिम बंगाल बजट सत्र से पहले सौगत रॉय ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह देखना चाहते हैं कि भाजपा सरकार घाटे के कर्ज और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से कैसे निपटती है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी। इन सांसदों ने नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने और संसद में एनडीए (NDA) का समर्थन करने का फैसला किया है। बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलकर सदन में अलग बैठने की जगह भी मांगी थी। उनका दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है।

टीएमसी नेतृत्व इस कदम से बेहद नाराज है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने इसे मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा बताया। उन्होंने कहा कि ये सांसद ममता बनर्जी के चेहरे और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए थे। अब एनडीए का साथ देना उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। वहीं, मदन मित्रा ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का जाना बताता है कि 'दाल में कुछ काला है।'

मेरे अकाउंट के पैसों से अंतिम संस्कार करना...

शख्स ने ली परिवार की जान, फिर की खुदकुशी

अमरावती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार की जान ले लीच इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. खुदकुशी करने से पहले शख्स ने अपने टीवी स्क्रीन पर सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने अपने जुर्म की दिल चीर देने वाली वजह का खुलासा किया था.

30 साल के दामू ने अपनी पत्नी की लाइलाज बीमारी से परेशान होकर अपने परिवार की जान ले ली और फिर आत्महत्या कर ली. दामू, एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र था, जो अपनी पत्नी निर्मला (25), अपने बेटे दिलीप और बेटी श्रीविद्या के साथ रहता था। दामू की जिंदगी में बुरा मोड़ तब आया, जब उसकी पत्नी निर्मला को दिमाग से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हो गई. कई स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद भी, परिवार को बताया गया कि उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है।

पत्नी और बच्चों के खाने में मिलाया जहर!

अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देख पाने और उसके बिना अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए दामू ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया. पुलिस को शक है कि उसने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था. इस घटना का पता अगली सुबह तब चला जब घर में ताला लगा होने पर परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को बताया।

अमोनिया गैस रिसाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हुई, विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। राज्य के श्रम कल्याण मंत्री जे मोहम्मद फरवास ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर उनके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 21 जून को दो महिला श्रमिकों की मौत हुई थी, जबकि सोमवार सुबह तीन अन्य प्रवासी महिला श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की संख्या पांच हो गई है।

मुख्यमंत्री ने गठित की संयुक्त जांच समिति

विधानसभा में बयान देते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने हादसे की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की है। इस टीम को 24

घंटे के भीतर प्रारंभिक और तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है तथा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मंत्री ने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति सुरक्षा या परिचालन संबंधी लापरवाही का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जवाबदेही तय करने में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।

74 श्रमिक हुए थे प्रभावित

मंत्री ने बताया कि पाइपलाइन में अचानक हुए अमोनिया गैस रिसाव के कारण 70 महिलाओं सहित कुल 74 श्रमिक प्रभावित हुए और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यवश इस हादसे में पांच महिला श्रमिकों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए राहत राशि की घोषणा की है और सरकार उनके पार्थिव शरीरों को गृह राज्य भेजने का पूरा खर्च वहन करेगी।'

सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ था हादसा

यह हादसा 21 जून को एक निजी सीफूड प्रोसेसिंग एवं निर्यात इकाई में हुआ था। नियमित औद्योगिक कार्य के दौरान अमोनिया गैस का रिसाव होने से वहां मौजूद श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रभावित श्रमिकों में अमोनिया गैस के संपर्क में आने के कारण सांस लेने में तकलीफ, आंखों और श्वसन तंत्र में जलन, खांसी, सीने में दर्द तथा गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे लक्षण देखे गए।

पुणे पोर्शे केस: आरोपी के पिता की जमानत रद्द कराने की मांग

- अदालत पहुंची पुलिस; वायरल वीडियो बना मुसीबत

पुणे। पुणे पुलिस ने पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता, विशाल अग्रवाल की जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस का आरोप है कि विशाल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह अर्जी शिवाजीनगर सत्र न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे के माध्यम से दी गई है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

वायरल वीडियो बना मुसीबत

यह कदम तब उठाया गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में विशाल अग्रवाल अपने परिवार के साथ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वह एक स्थानीय रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बेटे के साथ नाच रहे हैं और पीछे संगीत बज रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे।

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य विधि विभाग से अदालत जाने की अनुमति ली गई। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि जमानत मिलने के बाद इस तरह का जश्न मनाना गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इससे गवाहों पर दबाव पड़ने की आशंका है। पुलिस अदालत को बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी थीं, उन्हें पूरी तरह तोड़ा गया है।

अग्रवाल परिवार ने क्या कहा?

दूसरी ओर, अग्रवाल परिवार ने इस वीडियो को पूरी तरह गलत और पुराना बताया है। विशाल अग्रवाल की कानूनी टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि यह वीडियो साल 2023 का है। उनके मुताबिक, यह वीडियो गोवा के एक होटल में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह के जश्न के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने साफ किया कि यह कार्यक्रम 19 मई 2024 को पुणे के यरवदा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए पोर्शे हादसे से बहुत पहले का है।

पुलिस ने इस वीडियो के सिलसिले में विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस इन बयानों और डिजिटल सबूतों को अदालत के सामने पेश करेगी। अदालत ने विशाल अग्रवाल को इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला 19 मई 2024 का है, जब कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्शे कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। आरोप है कि कार विशाल अग्रवाल का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। विशाल अग्रवाल उन 10 आरोपियों में शामिल हैं, जिन्हें खून के नमूने बदलने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

बागियों को आदित्य ठाकरे ने बताया बिकाऊ

- वफादारी पर भी सवाल, कहा- लालच में विचारधारा छोड़ी

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के बागी सांसदों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने बागी सांसदों पर विचारधारा के बजाय निजी लालच को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे ने इन सांसदों को बिकाऊ करार दिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उन मतदाताओं के साथ धोखा किया है जिन्होंने उन्हें महाविकास अघाड़ी (MVA) और 'इंडिया' गठबंधन के समर्थन से जिताया था।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सांसद कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की मदद से चुनाव जीते थे। मतदाताओं ने एनडीए (NDA) के उम्मीदवारों और उनकी विचारधारा के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन अब इन सांसदों ने अपनी वफादारी और प्रतिष्ठा को शर्मनाक तरीके से बेच दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। आदित्य के अनुसार, इन सांसदों ने रातों-रात अपनी

विचारधारा सिर्फ इसलिए बदल ली क्योंकि वे लालची हो गए थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि चुनाव के समय इन नेताओं ने ही गठबंधन के बड़े नेताओं से अपने क्षेत्र में रैलियां करने की मांग की थी।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) ने पार्टी की बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) अनिल देसाई ने यह नोटिस भेजा है। इसमें सांसदों को सख्त चेतावनी दी गई है कि उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। सांसदों को 24 घंटे के भीतर लिखित में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। पार्टी ने साफ किया है कि अगर वे जवाब नहीं देते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने खुद ही पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इसके बाद संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा।

यह विवाद तब और गहरा गया जब दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नो में से केवल तीन लोकसभा सांसद ही पहुंचे। बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे शामिल हुए। जबकि संजय दीना पाटिल समेत छह सांसद गायब रहे। गायब रहने वाले अन्य सांसदों में नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, ओमप्रकाश राजेनिंबाल्कर और भाऊसाहेब वाकचौरे के नाम शामिल हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पहले ही कह दिया है कि इन अनुपस्थित सांसदों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये छह सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया है कि इन सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन सांसदों का यह व्यवहार शर्मनाक है और उन्होंने जनता के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल

- केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में जयराम रमेश ने परियोजना के तहत बनने वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास को लेकर कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। पत्र में जयराम रमेश ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास के लिए निजी कंपनी की भागीदारी के लिए निविदाएं जारी करने की समय-सीमा और निजी कंपनी के चयन की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

उन्होंने यह भी पूछा कि परियोजना में निजी क्षेत्र की न्यूनतम हिस्सेदारी 55 प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो क्या 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी, या फिर सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी न्यूनतम हिस्सेदारी तय की गई है? जयराम रमेश ने प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता भी जताई।

निजी स्वामित्व और फंडिंग पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि समिति के रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना के

विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में कम से कम 55 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली इकाई के पास होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह दावा कि परियोजना का उद्देश्य रक्षा और ट्रांसशिपमेंट अवसंरचना का विकास है, जबकि यह भ्रामक है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस परियोजना का असल उद्देश्य एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाना है ताकि वह देश की सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकीय भूमि पर होटल और कैसीनो विकसित कर सके। ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ एक नागरिक-सह-नौसैनिक हवाईअड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र विकसित करने की भी योजना है।

प्रथम पेज का शेष

लखनऊ की कोचिंग में आग,...

ने कहा कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने सरकार से घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसों का शिकार किसी भी परिवार के बच्चे हो सकते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को मिलकर गंभीर प्रयास करने चाहिए। जलती इमारत से कूदने वाला घायल जयंत सर्जरी वार्ड में शिफ्टः अग्निकांड में घायल जयंत गुप्ता को ट्रॉमा सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वह जलती इमारत से कूद गया था।

6 शव पोस्टमार्टम हाउस लाए गए, सभी की उम्र 25 से 30 साल के बीचः लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अब तक 6 मृतकों के शव पोस्टमार्टम हाउस लाए गए हैं। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार मृतकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। पोस्टमार्टम हाउस भेजे गए मृतकों में सागर (27), नीलेश (27), अनामिका (28), श्याम (30), अनुचा (25) और सोमलया (30) शामिल हैं। मृतकों की पहचान और अन्य औपचारिक प्रक्रिया जारी है।

बीजेपी मेयर रोते हुए बोलीं-...

से ठीक से खाना-पीना भी नहीं कर पा रही हैं। वे पांचवीं बार चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उनके साथ पहली बार ऐसा षडयंत्र किया गया है। उनका कहना है कि वे आदिवासी महिला हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। महापौर ने कहा कि मेरे पति और पिता बीमार हैं। उन्हें कुछ होता है तो संबंधित व्यक्ति जवाबदेह होगा।

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से कलाकेंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और महापौर मंजूषा भगत पर अवैध वसूली करने का आरोप है। ऑडियो कुछ दिन पुराना बताया है। वायरल ऑडियो अनुराग मिश्रा द्वारा जारी किया गया है, जो मीना बाजार का संचालन करते हैं।

वायरल ऑडियो में कथित रूप से अनुराग मिश्रा 3 लोगों से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इनमें एक आवाज भाजपा जिलाध्यक्ष और दूसरी आवाज महापौर मंजूषा भगत के होने का दावा किया गया है। दावा किया गया है कि मीना बाजार लगाने की अनुमति देने के लिए बड़ी रकम की मांग की गई। ऑडियो में अनुराग मिश्रा ने कथित रूप से महापौर मंजूषा भगत से बात करते हुए दिए गए पैसे वापस मांगे। अनुराग मिश्रा ने महापौर से कहा कि मेरे पास इतना नहीं है कि 3 लाख जिलाध्यक्ष को दूं और अलग से इधर दूं। मुझे कलाकेंद्र मैदान में अफीम की खेती नहीं करनी है। ऑडियो में महापौर कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि घर में किसी को बोल देती हूं, जाकर ले लेना।

ममता बनर्जी को चेयरमैन पद...

में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित नहीं किया गया था। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। ताजा घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस अब तीन गुटों में बंटी नजर आ रही है।

राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले...

अभी यह साफ नहीं है कि उन्होंने एसआईटी को अयोध्या छोड़ने की जानकारी दी है या नहीं। इधर, सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव अयोध्या छोड़कर कर्नाटक चले गए हैं। अभी यह साफ नहीं है कि उन्होंने एसआईटी को अयोध्या छोड़ने की जानकारी दी है या नहीं। भास्कर रिपोर्टर ने उनके नंबर पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। मैसेज भेजकर भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

एसआईटी ने जांच का डेटा 7 पेन ड्राइव में सेव किया है। 6 दिन की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी मामले में आज या कल में एफआईआर भी करा सकती है, जिसमें चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और अनुकल्प मिश्रा समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नामजद किया जा सकता है।

ट्रम्प के इशारों पर काम नहीं...

ईरान के बीच चल रही बातचीत दूसरे दिन शुरू हो गया है। पहला दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तीखे बयानों की वजह से तनावपूर्ण रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता सफल रही।

उद्धव के 6 सांसद शिंदे की...

मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक में उद्धव गुट के 4 विधायक निजी कारणों से नहीं पहुंचे। पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 288 में 20 सीटें जीती थीं।

राउत ने कहा- शिंदे ने 6 गद्दार पैदा किएः उद्धव ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया से कहा कि उन्हें (बागी सांसदों को) अपना पक्ष रखने दीजिए। सही समय आने पर हम अपना पक्ष रखेंगे। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने 6 गद्दार पैदा किए हैं। हालात संभालने के लिए अब सर्जरी करनी पड़ेगी। इससे पहले संजय राउत ने एक्स पर बताया था कि उद्धव 27 जून से महाराष्ट्र में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान वे बागी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे।

बंगाल में मदरसों को मिलने...

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ विरासत में मिला है। वित्तीय अनुशासन को बहाल करना और शासन में जनता का विश्वास जीतना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना हमारी सोच का मुख्य आधार है और हमें शासन व्यवस्था में लोगों का भरोसा वापस कायम करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है।

तिरछी नज़र से

महँगाईः टमाटर ने क्लास बदली – अब वह Middle Class नहीं रहा

प्रभातदत्त झा

सुधी पाठकों, इस देश में 'महँगाई' शब्द का उच्चारण करते ही नेता जी की भौंहें तन जाती हैं – 'कौन कह रहा है महँगाई है? देखिए, Inflation तो Control में है।' सरकारी आँकड़ों में Inflation 4-5% है। पर बाज़ार में जाइए – टमाटर सौ रुपये किलो, प्याज साठ, दाल डेढ़ सौ। हम पूछते हैं – 'यह Inflation किस बाज़ार में Control में है? हमें भी बताइए, हम भी वहीं से सब्ज़ी लेंगे।'

हमारी रसोई में एक मूक क्रांति हो रही है। पहले थाली में दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी होती थी। अब थाली में 'Budget Management' होता है। गृहिणियाँ अब गृहमंत्री नहीं – Finance Minister हैं। हर सुबह वे Market Survey करती हैं, तुलना करती हैं, और ऐसे विकल्प खोजती हैं जिनकी कल्पना कोई अर्थशास्त्री नहीं कर सकता।

जैसे — 'आज दाल नहीं, पर दाल जैसी दिखने वाली चीज़ बनाएँगे।' यह Culinary Innovation है, जो महँगाई की कोख से जन्मी है।

टमाटर की बात करें तो यह सब्ज़ी अब सब्ज़ी नहीं रही — यह Investment है। जब टमाटर दो सौ रुपये किलो था, तब लोग उसे तिजोरी में रखते थे। **एक सज्जन ने बताया** — 'भाई साहब, मैंने पाँच किलो टमाटर खरीदे थे। घर में रखे, दाम और बढ़े – तो बेच दिए। पाँच सौ का मुनाफा।' मैंने कहा, 'यह तो Trading है।' बोले, 'जी – Tomato Futures।' शेयर बाज़ार वाले नोट कर लें।

'थाली' पर राजनीति बड़ी रोचक है। हर सरकार कहती है — 'हमने सस्ती थाली दी।' विपक्ष कहता है – 'थाली खाली है।' सच यह है कि थाली है – पर उसमें जो होना चाहिए, वह या तो महँगा है, या 'Imported' है, या 'Out of Stock'। CSDS के एक सर्वे के अनुसार शहरी मध्यम वर्ग अब भोजन पर अपनी आय का 35-40% खर्च करता है – जो दस साल पहले 25% था। मतलब – जितना कमाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा पेट में जाता है। पेट देशभक्त नहीं होता – वह सिर्फ भूखा होता है।

सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो किसान टमाटर उगाता है, उसे पाँच रुपये किलो मिलता है। जो बीच में है, उसे पचास। और जो शहरी खरीदता है, वह डेढ़ सौ देता है। इस सफर में टमाटर का दाम तीस गुना बढ़ता है – पर किसान की आय नहीं। यह 'Supply Chain' है – जिसमें Supply किसान करता है और Chain बाकी सब पहनते हैं।

और जब महँगाई बढ़ती है तो नेता जी का प्रिय वाक्य आता है – 'जनता को कम खाना चाहिए, Obesity बढ़ रही है।' यानी समस्या का समाधान – समस्या को ही लक्ष्य बना दो। महँगाई ने Diet Control कर दिया – तो यह तो Health Policy है। सरकार और स्वस्थ्य को मिलकर इसका पेटेंट करा लेना चाहिए।

***निष्कर्ष — महँगाई कोई आँकड़ा नहीं है** — वह हर घर की रसोई में रोज़ जलती आग है, जो गृहिणी की आँखों में दिखती है जब वह बाज़ार से लौटती है और थैला हल्का होता है पर बिल भारी। असली सवाल यह है – जब थाली सिकुड़ती जा रही है, तो 'विकसित भारत' में आम आदमी की भूख का हिसाब कौन रखेगा?*

हर तीसरे दिन एक मौतः श्रमिक सुरक्षा अब भी अधूरा वायदा

कारखानों में श्रमिक और अन्य कामगारों की सुरक्षाः वर्तमान स्थिति और सुधार के सुझाव

अवनीश झा

रायपुर से बिलासपुर तक फैली रेलवे लाइन के किनारे जब कोई इस्पात कारखाने की चिमनी देखता है, तो उसे शायद यह न पता हो कि उस चिमनी के नीचे एक ऐसी दुनिया चलती है जहाँ हर सुबह काम पर जाने वाला मज़दूर यह भरोसा लेकर नहीं जाता कि वह शाम को सही-सलामत लौटेगा। बलौदाबाजार के धौराभाठा में कुछ महीने पहले हुई औद्योगिक दुर्घटना ने इस डर को फिर सच कर दिया - जांच में सामने आया कि किल्न का शटडाउन किए बिना मज़दूरों से जोखिमपूर्ण काम कराया गया, हाईड्रोलिक स्लाइड गेट बंद नहीं था, वर्क परमिट जारी नहीं हुआ था, और मज़दूरों को हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते व हेलमेट जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक नहीं दिए गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कारखाने के एक हिस्से का संचालन तत्काल रोकना पड़ा।

यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह उस तंत्र की झलक है जिसमें उत्पादन की रफ्तार अक्सर सुरक्षा की सीढ़ियाँ फलांगकर आगे निकल जाती है।

आंकड़े जो डराते हैं

श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में लगभग 6,500 मज़दूर फैक्ट्री, खदानों और निर्माण कार्यों में हुए हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत हादसे कारखानों में हुए। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक यह है कि 2017 और 2020 के बीच, भारत के पंजीकृत कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मज़दूरों की मौत हुई और 11 घायल हुए, और इस दौरान कम से कम 3,331 मौतें दर्ज की गईं।

- रोज़ाना औसत 3 मौतें, 11 घायल (2017-2020, पंजीकृत कारखाने)
- 5 वर्षों में 96,500 मौतें (फैक्ट्री, खदान, निर्माण क्षेत्र)
- 14,710 दोषी ठहराए गए(2010-2020, धारा 92 व 96ए)
- सिर्फ़ 14 को सज़ा मिली(2018-2020 के बीच)

सबसे विचलित करने वाला आंकड़ा सज़ा को लेकर है - कानून किताबों में सख्त है, पर अमल में लगभग बेदम। और यह आंकड़े केवल पंजीकृत कारखानों के हैं – देश में लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके हादसों का कोई पुख्ता आंकड़ा ही दर्ज नहीं होता।

हाल की रिपोर्टिंग भी यही दिखाती है - 2025 में महाराष्ट्र और हरियाणा के कारखानों में 2,500 से ज़्यादा मज़दूर घायल हुए, जबकि निरीक्षण न तो पर्याप्त हैं और न ही उनमें श्रमिकों की कोई भागीदारी होती है।

शोध क्या कहता है

IIT कानपुर के एक अध्ययन ने इस संकट की जड़ें साफ़ पहचानी हैं। शोध के मुताबिक, बॉयलर जैसे संवेदनशील उपकरणों का संचालन अक्सर अप्रशिक्षित संविदा श्रमिकों के हवाले होता है, जिनके पास सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की कोई ठीक ट्रेनिंग नहीं होती। साथ ही, कई उद्योग लागत घटाने के नाम पर वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा जैसे बुनियादी ढांचे की अनदेखी करते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक पुराना पर अब भी प्रासंगिक अध्ययन बताता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति श्रमिकों की अनभिज्ञता ही ज़्यादातर औद्योगिक दुर्घटनाओं से न बच पाने की मूल वजह है, और इसके लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण ज़रूरी है।

छत्तीसगढ़ की ज़मीनी तस्वीर

छत्तीसगढ़ में स्थिति को सुधारने की कोशिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन चुनौतियाँ बड़ी हैं। रायगढ़ जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने हाल ही में पाँच कारखानों पर सख्ती दिखाई – जांच में सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी पाए जाने पर श्रम न्यायालय ने दोषी प्रतिष्ठानों पर कुल पाँच लाख पच्चीस हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया। उप संचालक राहुल पटेल का कहना था कि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राज्य में निरीक्षण व्यवस्था को भी डिजिटल किया गया है। ALIS यानी ऑटोमेटेड लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम अब कंप्यूटर के ज़रिए रैंडम तरीके से कारखानों का चयन करता है और निरीक्षक को 48 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। इसके अलावा राज्य ने एक नई सुरक्षा फोर्स की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर उद्योगों को सुरक्षा, ऑडिट और आपदा प्रबंधन सेवाएं देगी।

बावजूद इसके, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों की एक हालिया बैठक में अधिकारियों ने कारखाना प्रबंधकों को फिर वही बुनियादी हिदायतें दोहराईं- सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और आपात मॉकड्रिल। यह दोहराव खुद बताता है कि निर्देश और अमल के बीच की खाई अब भी बनी हुई है।

सुधार की दिशा में क्या ज़रूरी है

संविदा श्रमिकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण : खासकर बॉयलर, किल्न और रासायनिक प्रक्रियाओं वाले कार्यों में स्थायी और ठेका श्रमिकों के बीच भेद खत्म कर समान सुरक्षा प्रशिक्षण देना।

निरीक्षण को मज़बूत और पारदर्शी बनाना : ALIS जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का दायरा बढ़ाकर असंगठित क्षेत्र के छोटे कारखानों तक ले जाना।

सज़ा को वास्तविक बनाना : केवल जुर्माना नहीं, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन जैसी ठोस कार्रवाई।

सुरक्षा समिति को वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य बनाना : हर पंजीकृत कारखाने में श्रमिक प्रतिनिधित्व वाली सक्रिय सुरक्षा समिति।

असंगठित क्षेत्र का डेटा संग्रह : जब तक 90 प्रतिशत श्रमिकों के हादसों का रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा, तब तक नीति निर्माण अधूरा रहेगा।

अंत में सुरक्षा हेलमेट और दस्तानों से कहीं ज़्यादा, यह भरोसे का सवाल है – उस भरोसे का, जो एक मज़दूर अपने घर से निकलते वक्त अपने परिवार को देता है कि वह लौटेगा। जब तक यह भरोसा कानून की किताबों से निकलकर फैक्ट्री के फर्श तक नहीं पहुंचता, तब तक हर चिमनी का धुआं किसी न किसी अनकही कीमत की याद दिलाता रहेगा।

एक कारखाना तभी सच में उत्पादक है, जब उसकी मशीनें चलें : मगर उससे पहले भी, और उससे ज़्यादा यह तय हो कि उसके मज़दूर हर शाम सही-सलामत घर लौटें।

-अवनीश झा,जालना महाराष्ट्र
(इंडस्ट्री-मामलों,मजदूर-आंदोलन और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और विशेषज्ञ)

शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य : बढ़ते बोझ के बीच उपेक्षित मुद्दा

रविकांत ठाकुर

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों, रिक्त पदों की कमी और डिजिटल दबाव के कारण खुद मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स और अध्ययनों में सामने आया है कि शिक्षकों में तनाव, बर्नआउट, चिंता और अवसाद की समस्या बढ़ती जा रही है, जो सीधे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रही है।

बढ़ते बोझ के प्रमुख कारण

कार्यभार की अधिकता - 30 हजार से अधिक रिक्त शिक्षक पदों के कारण एक शिक्षक कई कक्षाओं, विद्यार्थियों और प्रशासनिक कार्य संभाल रहा है। मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, चुनाव ड्यूटी जैसी जिम्मेदारियां पढ़ाई के साथ जुड़ गई हैं।

डिजिटल बोझ - 27 से अधिक एप्स और पोर्टलों पर बार-बार डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग। तकनीकी दिक्कतें, समय-सीमा और दोहराव शिक्षकों को मानसिक रूप से थका रहे हैं।

अन्य चुनौतियां - कम वेतन, पदोन्नति में देरी, संसाधनों की कमी, अभिभावकों-समाज का दबाव, COVID के बाद बढ़ी ऑनलाइन शिक्षण की आदतें और व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियां। ग्रामीण क्षेत्रों में अकेलेपन और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

प्रभाव क्या है?

शिक्षकों में लगातार थकान, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और उदासीनता बढ़ रही है।

कई शिक्षक बर्नआउट की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिससे कक्षा में उत्साह कम हो रहा है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

लंबे समय में यह डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

अध्ययनों के अनुसार, शिक्षकों का खराब मानसिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों के सीखने, व्यवहार और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक असर डालता है।

समाधान की दिशा में कदम

कार्यभार संतुलन — रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू कर डुप्लिकेट काम कम करें।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता - स्कूलों में काउंसलिंग सेंटर, नियमित वर्कशॉप, योग-ध्यान कार्यक्रम और हेल्पलाइन की व्यवस्था।

ट्रेनिंग और सपोर्ट - शिक्षकों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, समय प्रबंधन और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दें।

नीतिगत बदलाव - शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सर्वेक्षण कर समाधान निकालें। कई राज्यों में सफल मॉडल (जैसे टीचर वेलफेयर प्रोग्राम) अपनाए जा सकते हैं।

समाज की भूमिका - अभिभावक और समाज शिक्षकों का सम्मान बढ़ाएं, अनावश्यक दबाव कम करें।

निष्कर्षतः शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। यदि उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा, तो शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर रहेगी। छत्तीसगढ़ हो या मध्यप्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षकों के कल्याण और बेहतर शिक्षा वातावरण के लिए निरंतर आवाज उठाती रहेगी।

रविकान्त ठाकुर, (बच्चों को समुचित और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु शासकीय और अशासकीय स्तर पर कार्य करते हुए कई पुरस्कार प्राप्त, शिक्षकों के प्रशिक्षण में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण में महती भूमिका। म. प्र. और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को शैक्षिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान)

शून्य में गूँजती थापः एक विदा हो चुके पिता के नाम फादर्स डे

कैलेंडर की तारीखें जब 'फादर्स डे' की दस्तक देती हैं, तो दुनिया उत्सव के रंग में रंग जाती है। हर तरफ बधाइयों के शब्द और उपहारों के सिलसिले तैरने लगते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसके लिए यह दिन किसी उत्सव का नहीं, बल्कि एक निशब्द एकांत और आँखों के कोरों में सिमटी नमी का होता है। मेरे पापा अब इस नश्वर संसार में नहीं हैं। उनके जाने से जीवन में जो खालीपन आया है, वह कोई ऐसा गड्ढा नहीं जिसे वक्त भर दे; वह तो एक अनंत शून्य है, जिसमें बस उनकी यादों की प्रतिध्वनि गूँजती रहती है।

पिता का होना दरअसल किसी उत्सव जैसा नहीं, बल्कि घर की अदृश्य नींव जैसा होता है। वे छत की तरह दिखते भले न हों, लेकिन पूरे वजूद को थामे रहते हैं। जब तक वे थे, दुनिया की हर धूप छाँव सी लगती थी और हर मुश्किल एक अदने से तिनके जैसी। उनके रहने से जो बेफिक्री का एक सुरक्षा-कवच मिला हुआ था, उनके जाते ही वह अचानक टूट गया। तब समझ आया कि कंधों पर ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना क्या होता है।

आज जब वे भौतिक रूप से मेरे पास नहीं हैं, तो मुझे अहसास होता है कि पिता केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार हैं, एक संस्कार हैं। वे मेरे भीतर के उस विवेक में जीवित हैं जो मुझे सही और गलत का अंतर बताता है। जब भी मैं जीवन के किसी दोराहे पर थका हुआ हारने लगता हूँ, तो मेरे भीतर से एक मद्धम सी आवाज़ आती है–वही ढाँढस, वही अनुशासन, जो कभी पापा की आवाज़ हुआ करती थी। वे विलीन भले ही पंचतत्व में हो गए हों, लेकिन मेरे अस्तित्व के कण-कण में उनका अक्स आज भी महकता है।

इस फादर्स डे पर मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है, न ही मैं उनके गले लगकर अपनी भावनाएं जता सकता हूँ। मेरे पास केवल स्मृतियों के कुछ अछूते पन्ने हैं और कृतज्ञता से भीगी हुई आँखें हैं। पापा, आप जहाँ भी ब्रह्मांड के किसी कोने में एक तारा बनकर चमक रहे हों, आपकी दी हुई सीख मेरी हर सांस का संबल बनी रहेगी।

मर्मस्पर्शी काव्यांजलि

विदा हुआ वो साया सिर से, रह गई बस तन्हाई,
महफ़िल के इस शोर में पापा, याद आपकी आई।
ढूँढती हैं ये आँखें तुमको क्षितिज के उस पार कहीं,
छूकर गुज़रे जो ठंडी हवा, लगता है आप यहीं।

आपने जो बोए थे मुझमें, वो संस्कार ज़िंदा हैं,
आपकी आँखों के देखे, वो सारे सपनें ज़िंदा हैं।
जिस्म जुदा हुआ तो क्या, रूह में आप समाए हो,
मेरी हर एक धड़कन में, तुम बनकर अक्स आए हो।

तर्पण में क्या अर्पण करूँ, शब्द मेरे कमज़ोर हैं,
इस सूने अम्बर में बस, आपकी यादों के छोर हैं।
जब तक ज़िंदा हूँ इस जग में, आपका नाम बढ़ाऊँगा,
पापा, आपके ही अंश को मैं, हर पल सार्थक बनाऊँगा।

डॉ. निधि गुप्ता
बिलासपुर
(पी. एच.डी., एम.लिब., एल.एल.बी., बी.एस.सी.)

नशा नहीं, ज़िंदगी चुनिएः एक पीढ़ी के बचने की कहानी.....

रात के करीब नौ बजे थे। बिलासपुर के एक मोहल्ले में रामलाल जी अपने दरवाजे पर बैठे थे, निगाहें गली के मोड़ पर टिकी हुई थीं। बेटा हर शाम इसी वक्त लौटता था- कभी हंसता हुआ, कभी थका हुआ, पर लौटता जरूर था। आज तीसरी रात है कि वह नहीं लौटा। रामलाल जी को अब तक नहीं पता था कि 'दोस्तों के साथ टाइम पास' शब्द कब 'नशे की लत' में बदल गया था। यह कहानी सिर्फ रामलाल जी की नहीं है- यह हर उस घर की कहानी है जहां माता-पिता रात-रात जागते हैं, बिना यह जाने कि उनका बच्चा किस दलदल की ओर बढ़ रहा है।

26 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हर साल लाखों परिवारों की पीड़ा और करोड़ों युवाओं के भविष्य पर मंथन का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व नशा रिपोर्ट 2025 के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में लगभग 31.6 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन किया, जो 15 से 64 वर्ष की आबादी का करीब 6 प्रतिशत है। इनमें भांग का सेवन करने वालों की संख्या 24.4 करोड़, ओपिओइड 6.1 करोड़, एम्फेटामाइन 3.07 करोड़, कोकीन 2.5 करोड़ और एक्स्टसी 2.1 करोड़ रही। रिपोर्ट यह भी आगाह करती है कि संगठित नशा तस्करी गिरोह वैश्विक संकटों का फायदा उठाकर समाज के सबसे कमजोर और सबसे युवा वर्ग को निशाना बना रहे हैं।

भारत की तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, जिनमें 16

करोड़ शराब और करीब 12 करोड़ अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले हैं। इनमें से लगभग 6 करोड़ लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, मगर समुचित पुनर्वास सुविधाओं के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता। हर साल तंबाकू जनित बीमारियों से लगभग 20 लाख और शराब से जुड़े कारणों से करीब 5 लाख भारतीयों की जान चली जाती है- ये आंकड़े किसी युद्ध के हताहतों से कम नहीं।

छत्तीसगढ़ और बिलासपुर भी इस लड़ाई से अनछुए नहीं हैं। राज्य सरकार ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में विशेष एनडीपीएस अदालतें गठित कर 11 मई 2026 से प्रभावी किया है, जो दर्शाता है कि नशे के मामले अब सिर्फ पुलिस थानों तक सीमित नहीं, बल्कि न्यायपालिका की प्राथमिकता बन चुके हैं। शहर के कोनी थाना क्षेत्र में हाल में गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तारी जैसी घटनाएं बताती हैं कि सुदूर गांवों से लेकर शहर की गलियों तक नशे का जाल किस तरह फैल चुका है। राहत की बात यह है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देशभर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें 5.26 करोड़ युवा और 3.31 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, और 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान इस मुहिम से जुड़ चुके हैं।

सवाल यह है कि आखिर युवा पीढ़ी नशे की ओर क्यों खिंचती चली जा रही है। परीक्षा का दबाव, बेरोजगारी की चिंता, टूटते सामाजिक रिश्ते, सोशल मीडिया पर दिखावे की होड़ और दोस्तों का दबाव- ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बना देते हैं जिसमें नशा 'राहत' का झूठा भरोसा देता प्रतीत होता है। जबकि सच्चाई यह है कि यह राहत क्षणिक होती है और इसके पीछे टूटते परिवार, बिगड़ता स्वास्थ्य और खोता आत्मविश्वास जैसी स्थायी क्षतियां छिपी रहती हैं।

समाधान किसी एक संस्था या सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार को संवाद का माध्यम बनना होगा, स्कूल-कॉलेजों को जीवन-कौशल शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, और समुदाय को नशा मुक्ति केंद्रों तथा परामर्श सेवाओं को सुलभ बनाना होगा। मीडिया, धर्मगुरु, खेल जगत के नायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि- सभी को इस मुहिम में साझीदार बनना होगा, ताकि नशा छोड़ने की इच्छा रखने वाला कोई भी युवा संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए।

शहर चाहे बिलासपुर हो या अमृतसर, भुवनेश्वर हो या जयपुर...जो शिक्षा और साहित्य, संस्कृति के केंद्र रहे हैं, हरेक शहर के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाकर रखे।

नशा किसी को रातोंरात नहीं पकड़ता, यह कदम-कदम पर दस्तक देता है- कभी जिज्ञासा के बहाने, कभी दोस्ती के दबाव में। और ठीक इसी तरह, इससे बचाव भी कदम-कदम पर होता है- एक संवाद, एक भरोसा, एक वक्त पर बढ़ाया गया हाथ। 26 जून सिर्फ एक दिवस नहीं, हर माता-पिता, हर शिक्षक और हर युवा के लिए यह सवाल है: क्या हम अपने आसपास किसी रामलाल जी को दरवाजे पर अकेला बैठा रहने देंगे, या समय पर हाथ बढ़ाएंगे?

- प्रभात दत्त झा
देवेन्द्रनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495001

स्वामी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि. के लिए प्रकाशक सुभाष मिश्रा के द्वारा मुद्रक मिशन मीडिया प्रा.लि., रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं बंद टॉकीज के सामने, सदर वार्ड नं. 10, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक- सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक-भालचंद्र जोशी, स्थानीय संपादक-विजय सिंह* आरएनआई रजि. नं.- CTHIN/26/A4159 पीआरबी एक्ट 2023 के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।